चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 25 जुलाई- 31 जुलाई 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मोदी जी! लोगों के विश्वास के साथ शासन करिए...

नीयत सही नीति बदलें

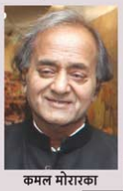

कमल मोरारका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में कहा है कि मीडिया का एक खास तबका उन्हें सत्ता में नहीं आने देना चाहता था या कह सकते हैं कि मीडिया को ये उम्मीद नहीं थी कि वे सत्ता में आ सकते हैं. उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे मीडिया के उस तबके का अभी तक दिल नहीं जीते सके हैं. प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया यह एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है. मैं उन्हें एक सुझाव देना चाहता हूं. हालांकि, मैं उनके समूह से नहीं जुड़ा हूं इसलिए उम्मीद है कि मेरे सुझाव को सही मायने में नहीं लिया जाएगा.

सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि मीडिया को लेकर उनका विश्लेषण गलत है. वे मीडिया के जिस तबके की बात कर रहे हैं, उन लोगों के मन में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है. सवाल ये नहीं है कि मीडिया उन्हें सत्ता में नहीं देखना चाहता था. इस तरह की सोच या बहस निरर्थक है. इसमें कोई सही हो सकता है, तो कोई गलत हो सकता है. लेकिन एक बात तय है कि उन्हें सत्ता में आते हुए नहीं देखने की इच्छा रखने वाला बयान गलत है. लोकतंत्र में अगर फ्री एंड फेयर (भयमुक्त और निष्पक्ष) चुनाव होते हैं, तो जो भी सत्ता में आता है, उसे आपको स्वीकार करना होता है. भले ही आपने उसे वोट दिया हो या नहीं दिया हो. यह सवाल ही नहीं उठता है कि मीडिया उनके प्रधानमंत्री बनने से नाखुश है. महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रधानमंत्री मीडिया के जिस तबके की बात कर रहे हैं, वे लोग आखिर सोचते क्या हैं, उनके एहसास क्या हैं? आइए इसका विश्लेषण करते हैं...

मीडिया के इस खास हिस्से की बुनियाद संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार के रक्षा की गारंटी पर टिकी है. वहीं संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि देश की नीति किस दिशा में जाएगी या जानी चाहिए. इनके मन में जो सवाल या चिंताएं हैं, वो ये हैं कि भाजपा और खास तौर पर उसके मातृ संगठन आरएसएस के कई विचार संविधान की मूल भावनाओं से मेल नहीं खाते हैं. ऐसे में चिंता इस बात की थी कि अगर ऐसे संगठन से संबंध रखने वाला व्यक्ति सत्ता में आता है, तो वो चीजों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है. प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि देश का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है, जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए. उन्होंने ऐसा कह सुषमा स्वराज के इस सुझाव को खारिज कर दिया कि भगवद्गीता को देश का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए. सुषमा स्वराज उनके कैबिनेट की सदस्य हैं, लेकिन आरएसएस बहुत खुश होगी अगर भगवद्गीता को राष्ट्रीय ग्रन्थ घोषित कर दिया जाए. कुछ ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं, जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना है. प्रधानमंत्री यदि सचमुच उनका दिल जीतना चाहते हैं, जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया और जिनके मन में उनकी नीतियों को लेकर शंकाएं हैं, तो उन्हें ऐसे लोगों पर लगाम लगाना होगा जो बीफ बैन कराना चाहते हैं, गीता को राष्ट्रीय ग्रन्थ घोषित कराना चाहते हैं और ऐसे सुझाव देते हैं जिसका देश की नीति से कोई संबंध नहीं है.

साफ-साफ शब्दों में कहें तो दो साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो राज्यनीति और संविधान के दायरे से बाहर हो. परेशानी तब पैदा होती है जब साध्वियां, योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे लोग ऐसे अव्यावहारिक बयान देते हैं, जिन्हें लागू करना संभव नहीं है. वे न सिर्फ गैर-हिंदुओं, बल्कि उन हिंदुओं में भी भय का वातावरण पैदा करते हैं, जो उनके साथ नहीं हैं. उदाहरण के लिए, बीफ बैन का मामला. मुझे कोई यह नहीं दिखा सकता है कि हिंदू धर्मशास्त्रों में कहीं भी बीफ खाने पर पाबंदी की बात लिखी गई हो. दरअसल सनातन धर्म के शास्त्रों में बीफ खाने पर पाबंदी की बात नहीं की गई है. बहुत बाद में मवेशियों को बचाने और अन्य कारणों से ये फैसला लिया गया कि हमें गायों की हत्या नहीं करनी चाहिए. इसमें कोई हर्ज की बात नहीं थी, लेकिन बीफ बैन करने के लिए धर्म का सहारा लेने से एक तो कोई मकसद पूरा नहीं होगा, दूसरे इससे कई परेशानियां पैदा होंगी. मुंबई में सरकार ने बीफ पर बैन लगा दिया. नतीजा यह हुआ कि मुंबई में जितने अंतरराष्ट्रीय कान्फ्रेंस होते थे, वे अब गोवा में होने लगे. इससे कौन सा मसला हल हो गया, कौन सा मकसद पूरा हुआ, यह समझ से परे है.

> *साफ-साफ शब्दों में कहें तो दो साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो राजनीति और संविधान के दायरे से बाहर हो. परेशानी तब पैदा होती है जब साध्वियां, योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे लोग ऐसे अव्यावहारिक बयान देते हैं, जिन्हें लागू करना संभव नहीं है. वे न सिर्फ गैर-हिंदुओं, बल्कि उन हिंदुओं में भी भय का वातावरण पैदा करते हैं, जो उनके साथ नहीं हैं.*

> *प्रधानमंत्री का एजेंडा क्या है? वे चाहते हैं कि देश का विकास हो. वे चाहते हैं कि किसानों की आय छह साल में दोगुनी हो जाए. वे और भी कई अच्छे काम करना चाहते हैं, जो अच्छी बात है. अगर आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो उसमें हर अच्छी बात को जगह दी गई है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. लेकिन सिर्फ कागज पर लिख देने से उसे लागू नहीं किया जा सकता है. इसके लिए हर दिन काम करना होगा.*

भाजपा और उसके समर्थक बार-बार नेहरू की विश्वसनीयता खत्म करने की कोशिश करते हैं. राजनीतिक तौर पर ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को यह एहसास होना चाहिए कि सच क्या है? मैं आश्वस्त हूं कि वे इसे महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी पहुंच सारे सरकारी कागजात तक है. प्रधानमंत्री आसानी से सारी सूचनाएं ले सकते हैं. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मालूम था कि अगर भारत को तरक्की की राह पर ले जाना है तो अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, जिसमें लोग आकंठ डूबे हैं, दूर करना होगा. दस साल तक जेल में रहने, पूरी दुनिया देखने और एक आजाद ख्याल व्यक्ति होने के नाते वे इस देश को पूरी तरह से समझते थे. उन्होंने एक बेहतरीन विचार दिया कि अगर आप भारत को एक आधुनिक देश बनाना चाहते हैं, तो आपको नई उम्मीद व जोश के साथ आगे बढ़ना होगा. उन्होंने भाखड़ा-नांगल, स्टील प्लांट, आण्विक ऊर्जा जैसे आधुनिक चीजों की बुनियादें रखीं. उन्होंने सोचा कि अगर वे लोगों को रोजगार देने में सफल हुए, तभी समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता व अंधविश्वास दूर कर पाएंगे. लेकिन रोजगार सृजन के मुकाबले में बदकिस्मती से जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ी. 1964 तक (जब तक नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे) इसमें सीमित सफलता ही मिली और बाद की कांग्रेस सरकारों ने भी उन्हीं की राह पर चलने की कोशिश की.

बेशक नेहरू ने दो बड़ी गलतियां कीं, जिसका पता बाद में चला. आज लोग कहते हैं कि उस वक्त क्या होना चाहिए था? आज क्या होना चाहिए, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है. लोग कहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर नेहरू को संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं जाना चाहिए था. नेहरू एक सज्जन व्यक्ति थे. उन्होंने सोचा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने से एक उचित समाधान निकलेगा. बेशक सरदार पटेल उन्हें बोल सकते थे कि ऐसा करना सही नहीं होगा. संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोशिश की, लेकिन उसके प्रस्ताव का कोई असर नहीं हुआ और कश्मीर आज भी एक समस्या बना है. उसी तरह से चीन का मामला है. इंदिरा गांधी ने भी नेहरू से कहा था कि अगर चीन ईमानदारी नहीं दिखा रहा है और जैसा कि

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नीयत सही, नीति बदलें

पृष्ठ 1 का शेष

उसके कथनी-करनी में भेद है, तो उसकी बात हमें नहीं माननी चाहिए. जैसे ही चीन ने हमला किया, नेहरू इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाए. वे टूट गए और उनकी जल्द ही मृत्यु हो गई. गलतियां किसी से भी हो सकती हैं. जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ गलतियां कीं, लेकिन देश को जिस राह पर वे ले गए, उसका श्रेय उनसे नहीं छीना जा सकता है. अगर आज भारत दुनिया के आजाद ख्याल देशों में से एक है, जहां बोलने की आजादी है, प्रेस की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और सबके लिए समान अवसर उपलब्ध है तो इसका श्रेय नेहरू को जाता है. जिस बिंदु को मैं रेखांकित करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मीडिया का एक तबका उनका समर्थन करे तो उन्हें रूढ़िवादी विचारों को त्यागना होगा. मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने दो साल में प्रशासनिक स्तर पर कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें कोई गलती निकाली जा सके. अगर सरकार बहुमत में होती है तो उसकी अपनी नीतियां होती हैं. नीतियां आती हैं, जाती हैं, लेकिन देश के बुनियादी धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बचाए रखना हर हाल में जरूरी होता है. अगर इसे चंद लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है और धीरे-धीरे यह व्यवस्था का हिस्सा बनने लगता है तो दस-पंद्रह वर्षों के बाद हम एक अलग देश होंगे, जो शायद बेहतर न हो. प्रधानमंत्री को इन मुद्दों को सुलझाने के लिए मीडिया के उक्त हिस्से को बुलाना चाहिए और यह पूछना चाहिए कि आपका भय क्या है और फिर उस भय को दूर करना चाहिए.

आजादी का मतलब होता है सही चीजें करने की आजादी और गलत चीजें करने की भी आजादी. समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो गलत काम करते हैं. कोई चर्च जलाता है, कोई सांप्रदायिक दंगे करवाता है. जब तक पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करती है, तब इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है. अमेरिका और इंग्लैंड जहां परिपक्व लोकतंत्र हैं, वहां भी हर साल विवाद और दंगे होते रहते हैं. वहां ऐसे मामलों में राज्य तटस्थ है, पुलिस भी काफी सख्त है. लेकिन भारत में ये धारणा है कि पुलिस और सेना प्रो-हिंदू (हिंदुओं के समर्थन में) हो जाती है. ये धारणा अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करती है. भारत में आमतौर पर अल्पसंख्यक का मतलब है मुसलमान. ऐसा क्यों, जबकि ईसाई और सिख भी अल्पसंख्यक हैं?

प्रधानमंत्री का एजेंडा क्या है? वे चाहते हैं कि देश का विकास हो. वे चाहते हैं कि किसानों की आय छह साल में दोगुनी हो जाए. वे और भी कई अच्छे काम करना चाहते हैं, जो अच्छी बात है. अगर आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो उसमें हर अच्छी बात को जगह दी गई है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ कागज पर लिख देने से उसे लागू नहीं किया जा

सकता है. इसके लिए हर दिन काम करना होगा. देश में नौकरशाही के पास लंबे समय से काम करने के कारण व्यापक अनुभव है. उन्हें मालूम है कि हर पांच साल में सरकार बदलती है. लेकिन उनके पास एक बुनियादी नीति होती है जो बदलती नहीं है, चाहे जो भी सरकार आए. कुछ लोग हैं, जो वाकई डरे हुए थे कि अगर वे सत्ता में आए तो क्या होगा? लेकिन मेरे विचार में उनका डर निर्मूल साबित हुआ. प्रधानमंत्री ने बेसिक सिस्टम में परिवर्तन करने वाला कोई काम नहीं किया है. दरअसल, संघ और उसके अन्य सहयोगी संगठन (हालांकि, वे भी बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं) वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. वे विकास, रोजगार, जीवन स्तर में सुधार इत्यादि के एजेंडे से सरकार को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. ये ऐसे एजेंडे हैं, जिन्हें लोग पूरा होते देखना चाहते हैं, उसमें रोजगार का स्थान सबसे पहले आता है. आज छात्र व नौजवान रोजगार चाहता है. प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं अच्छी हैं, जैसे मेक इन इंडिया, लेकिन ये सब एक दिन में पूरी नहीं हो सकती हैं. अगर प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रो राइट (दक्षिणपंथी) रुख से थोड़ा सा अलग हटने के लिए तैयार हों, तो उन्हें एहसास होगा कि भारत में बहुत अधिक निजी पूंजी नहीं है. पूंजी सरकार के पास है या फिर पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास. इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तब उन्हें इस बात का एहसास था. उन्होंने छोटे लोगों को ये अवसर दिया कि वे लोन ले सकें और स्वरोजगार कर सकें. आज मेक इन इंडिया कामयाब नहीं हो सकता अगर हम सिर्फ 4 या 5 बिजनेस हाउसेज का इंतजार करते रहें या कुछ विदेशी कंपनियों की प्रतीक्षा करते रहें. सरकार को निवेश करना होगा. रक्षा क्षेत्र में हम बहुत बड़े खरीदार हैं. अगर हम रक्षा उपकरण बनाना चाहते हैं, तो सरकार को इसमें बहुत सारा पैसा लगाना होगा. बड़े कारखाने लगाने होंगे, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरे सेक्टर को लाभ होगा. वक्त आ गया है कि सरकार को सक्रिय होकर फैसले लेने होंगे, काम करना होगा. सरकार काम कर भी रही है, जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है. सड़कें बन रही हैं, रेलवे में काम हो रहा है, बंदरगाह बन रहे हैं आदि. लेकिन अगर प्रधानमंत्री त्वरित विकास चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए पब्लिक सेक्टर को आगे आना होगा. लेकिन यहां प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ये कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर भ्रष्ट है. इस संदर्भ में प्रधानमंत्री को सतर्क रहना चाहिए. भ्रष्टाचार समाप्त करना एक ऐसा लक्ष्य है, जिसे हासिल करना मुश्किल है. प्रधानमंत्री और उनके बड़े मंत्रियों को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ये उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए. मैं समझता हूं कि इससे आम लोगों में संदेश जाएगा कि सब चीजें ठीक-ठाक हैं. अगर आप निचले स्तर से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, जैसा लोकपाल की मांग के समय कहा जा रहा था, तो यह काम कभी पूरा नहीं होगा. लोकपाल का लाखों कर्मचारियों पर नियंत्रण होगा और सब पर निगरानी रखना, सबके खिलाफ कार्रवाई करना, ये संभव नहीं है. सभी सरकारी सौदों में पारदर्शिता लाई जा सकती है, लेकिन आप इस मानसिकता को नहीं बदल सकते जिसमें हर व्यक्ति पैसा चाहता है.

हमारी कर व्यवस्था सही नहीं है. इसमें लीकेज है. इस सरकार के आने के बाद भी इसमें न सुधार हुआ है, न कोई बदलाव आया है और न कोई बदलाव आ सकता है. बदलाव उसी वक्त आएगा जब आप पूरे कानून को बदलेंगे. पुराने कानून के साथ पुराना सिस्टम ही चलता रहेगा. लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि यह चिंता की बात है. चिंता का असल विषय मौद्रिक है. अगर हम वित्तीय घाटे को 3.5 फीसदी से नीचे रखना चाहते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था के पास इसके लिए पैसा नहीं है. रिजर्व बैंक के गवर्नर इस पर बहुत सख्त नियंत्रण रखना चाहते हैं. बिना पैसे के विकास नहीं हो सकता है. सरकार एफडीआई का इंतजार कर रही है. एफडीआई की अपनी सीमा है. उदारीकरण के बाद पिछले 20 साल की अवधि में एफडीआई का प्रवाह स्थिर रहा है. यह सरकार दावा कर रही है कि इस साल का एफडीआई सबसे अधिक है. हर साल एफडीआई में दस से बीस फीसदी का इजाफा होता है तो इस साल भी यह इजाफा हुआ. इसमें कोई खास बात नहीं है.

प्रधानमंत्री ने पिछले चुनाव में 31 फीसदी वोट हासिल किया था. अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं यह जरूर कोशिश करता कि मेरा वोट आधार 31 फीसदी से ज्यादा हो जाए. हालांकि कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं होने से 31 फीसदी वोट घट भी सकता है. अगर आप अपना वोट आधार सचमुच बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मध्यमार्ग अपनाना होगा. सड़क के दाईं तरफ (दक्षिणपंथ) चलने से कोई लाभ नहीं होगा, बीच में चलिए. उदारवादी रहिए, हर क्षेत्र को फलने-फूलने का मौका मिलेगा. छोटे, बड़े, मंझोले सभी सेक्टर्स को फायदा होगा. कानून का राज होगा. अगर कोई गलत काम करता है तो उसे न्यायपालिका देखेगी. अगर आप हर किसी के पीछे प्रवर्तन निदेशालय, सेल्स टैक्स के अधिकारियों को लगा देंगे तो आप उद्यमियों की ऊर्जा को क्षीण करने का ही काम करेंगे.

प्रधानमंत्री को यह जरूर देखना और समझना चाहिए कि कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक कैसे शासन किया? कांग्रेस के राज में भी भ्रष्टाचार था और सारी समस्याएं थीं, लेकिन लोगों ने उसे इसलिए चुना क्योंकि लोग यह समझते थे कि वे सुरक्षित हैं और कुछ भी करने की आजादी उनके पास है. इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की गलती की. लोगों ने तत्काल उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया क्योंकि लोगों को लगा कि उनकी आजादी छीन गई है. जब तक समस्या किसी और के घर में होती है आम तौर पर लोग प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन समस्या अपने घर में आते ही लोग प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं. भय का माहौल मत बनाइए, लोगों के मन को भयमुक्त कीजिए. हर किसी को आजादी से सांस लेने दीजिए. जब वे कहते हैं कि देश के लिए एकमात्र किताब संविधान है, तो उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान का अक्षरशः पालन हो. पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहित किया जाए, अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाए, ये सारी बातें कांग्रेस के समय की लगेंगी. लेकिन ये सारी चीजें आजादी की लड़ाई के दौरान सोची गई थीं. अगर प्रधानमंत्री वाकई चाहते हैं कि बुद्धिजीवी और जागरूक तबके का समर्थन उन्हें मिले तो उन्हें दाईं तरफ से हटकर सड़क के बीच में (मध्य मार्ग) आना होगा. अगर वे बाईं तरफ से मध्य में आते (लेफ्ट टू सेंटर) हैं तो ये बहुत ही शानदार बात होगी, जैसा कांग्रेस ने किया था. दरअसल, कांग्रेस ने जो कुछ गलतियां कीं उसे ये दूर कर सकते हैं. कांग्रेस ने क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया. इसने कुछ लोगों को सरकार पर अपना फैसला थोपने का मौका दिया. मिसाल के तौर पर कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाएगा. प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं कि वे ऐसी चीजों से खुद को बचाए रख सकते हैं. लेकिन बुनियादी बात ये है कि उन्हें किसी नीति को इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो कांग्रेस की है. कोई भी पॉलिसी किसी दल की नहीं बल्कि देश की होती है. कांग्रेस ने अपने शासन में अपनी पॉलिसी बनाई, वो देश के लिए ही तो थी. मनरेगा, जिसे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की असफलता का स्मारक बताया था, अब उन्हें समझ में आया कि गरीबों को मदद पहुंचाने का एकमात्र रास्ता अभी मनरेगा ही है इसीलिए अब वे इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं. लिहाजा, किसी नीति को यह बोल कर कि ये कांग्रेस की नीति है, उसे खारिज नहीं किया जाए. मैं आश्वस्त हूं कि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे जानकार लोग हैं, जो उन्हें सही सलाह दे सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं.

दूसरा विकल्प ये है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दें, हम राम मंदिर बना लें, ताकि मुसलमानों की मानसिकता को और चोट पहुंचाई जा सके. हम उनलोगों को मार देना चाहते हैं, जो बीफ खाते हैं. सरकार चाहे तो आरएसएस और हिंदू कट्टरवाद को ऐसा कर संतुष्ट कर सकती है, लेकिन इसके बाद इस देश पर शासन करना मुश्किल होगा. ऐसा कर आप ताकत के बल पर शासन तो कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से नहीं. मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने इन सब पर अपनी चिंता जताई है. प्रधानमंत्री आसानी से कह सकते थे कि अब मैं सत्ता में आ गया हूं और जो लोग मुझे सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाहते थे, मैं उनकी फिक्र नहीं करता हूं. लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वे ऐसे लोगों का मन जीतना चाहते हैं. ऐसे लोगों का दिल जीतने का एकमात्र रास्ता है कि आप अपनी नीतियों में बदलाव लाएं. आपको मेहनत करनी होगी और अपने लोगों को समझाना होगा कि अब हम सत्ता में आ गए हैं तो हमें अपने रुख में नरमी लानी होगी. राममंदिर सब कुछ नहीं हो सकता है. आर्टिकल 370 की समाप्ति और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं हो सकता है. ये सारी चीजें ठीक हैं. राम मंदिर में कोई समस्या नहीं है. मैं मानता हूं कि राम मंदिर बनना चाहिए लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों की सहमति और सहयोग से. आर्टिकल 370 को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त जब कश्मीरी खुद ऐसा चाहें. सोशलिस्ट पार्टियां यूनिफॉर्म सिविल कोड में विश्वास रखती हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मुस्लिम समाज प्रभावित होगा. ये मुस्लिम समाज के जागरूक लोगों की मांग पर लागू होना चाहिए. इसे धीरे-धीरे भी लागू किया जा सकता है, अचानक नहीं. इसे कानून के जरिए जबरदस्ती लागू नहीं किया जाना चाहिए. इसे एक उदाहरण से समझते हैं. दल-बदल अच्छी चीज नहीं है. राजीव गांधी ने एक दल-बदल विरोधी कानून पास कराया था. इसका नतीजा ये हुआ कि कानून बनने के बाद ज्यादा संख्या में दल-बदल हुए. सरकार कानून के जरिए लोगों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकती है. मैं समझता हूं कि नीति आयोग वित्तीय मामलों पर विचार करता है. इसी तरह की एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो समग्र भारत के बारे में, समग्र भारत के मुद्दों पर विचार करे कि भारत को किस दिशा में जाना चाहिए. लोगों के विश्वास के साथ शासन करिए. उम्मीद कीजिए कि सरकार इन सब पर अमल करेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 21
25 जुलाई- 31 जुलाई 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

केंद्र ने रोकी जजों की नियुक्ति की विवादास्पद लिस्ट

पक्षपात पर बज्रपात

इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को दिया गया जांच का जिम्मा

प्रभात रंजन दीन

जजों की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट को जो लिस्ट भेजी थी, उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है. लिस्ट भेजने के बाद चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में जज बन कर चले गए. चंद्रचूड़ ने तकरीबन 50 नाम भेजे थे, उनमें से अधिकांश नाम पूर्व और मौजूदा जजों के बेटे, भाई, भांजे, साले व अन्य नजदीकी रिश्तेदारों के हैं. जो बचे वे सब भी सरकार के सिफारिशी-पुत्र हैं या बड़े नेताओं के बेटे या रिश्तेदार हैं. राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र 'चौथी दुनिया' और उसके उर्दू संस्करण ने इस खबर को सबसे पहले उजागर किया और न्यायालय परिसर में न्यायाधीशों द्वारा की जा रही अंधेरगर्दी की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया. 'चौथी दुनिया' में प्रकाशित इस खबर ने सोशल मीडिया मंच पर भी बड़े पैमाने पर देशभर के लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जिससे जजों की नियुक्ति की ऐसी धांधलीपूर्ण सिफारिश के खिलाफ व्यापक आक्रोश सामने आया. खास तौर पर वकीलों, कानून की विधा से जुड़े लोगों और उनके संगठनों की तरफ से जोरदार प्रतिक्रियाएं सामने आईं. आखिरकार केंद्र सरकार ने इस विवादास्पद लिस्ट को स्थगित करने का फैसला किया. केंद्र ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को मामले की जांच करने को कहा है.

इंटेलिजेंस ब्यूरो को जांच का आदेश देते हुए केंद्र ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो लिस्ट भेजी गई है, उनमें अधिकतर लोग वर्तमान जजों, पूर्व जजों और नेताओं के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. इसके अलावा अन्य जो लोग लिस्ट में शामिल हैं, वे भी सिफारिशी बताए गए हैं. लिहाजा, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए. आईबी के एक अधिकारी ने कहा कि मौजूदा और पूर्व जजों या नेताओं के रिश्तेदारों का नाम, जिन्हें जज बनाए जाने की सिफारिश की गई है, एक खुला तथ्य है, इसकी पूरी रिपोर्ट शीघ्र ही केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी. इसमें कोई दो मत नहीं कि जजों की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट भेजी गई है, वह धांधलियों का पुलिंदा है. जज अपने बेटों और नाते रिश्तेदारों को जज बना रहे हैं और सरकार को उपकृत करने के लिए सत्ता के चहेते सरकारी वकीलों को भी जज बनाने की संस्तुति कर रहे हैं. न्यायाधीश का पद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के प्रभावशाली जजों का खानदानी आसन बनता जा रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यभार संभालने के पूर्व जो 50 नाम जजों की नियुक्ति के लिए भेजे उनमें अधिकांश लोग जजों के बेटे और रिश्तेदार हैं या सरकार के पैरवी-पुत्र सरकारी वकील हैं. इनमें 35 नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के और करीब 15 नाम हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के हैं. लेकिन इनमें ओबीसी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक भी वकील शामिल नहीं है. विडंबना ही तो है कि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की स्थापना काल से लेकर अब तक के 65 साल में अनुसूचित जाति का एक भी वकील जज नहीं बना. इसी तरह वैश्य, यादव या मौर्य जाति का भी कोई वकील कम से कम लखनऊ पीठ में आज तक जज नियुक्त नहीं हुआ. वरिष्ठ वकीलों को जज बनाने के नाम पर न्यायपीठों में यह गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी कृत्य निर्बाध गति से चल रहा है, इसके खिलाफ सार्वजनिक मंच पर बोलने वाला कोई नहीं. जजों की कुर्सियां न्यायाधीशों के नाते-रिश्तेदारों और सत्ता-संरक्षित सरकारी वकीलों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं. उन अधिवक्ताओं को जज बनने का कोई अवसर नहीं मिलता जो कर्मठता और ईमानदारी से वकालत करते हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं.

जिन लोगों को जज बनाने की सिफारिश की गई है, उनका एक बार फिर से जायजा लेते चलें. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे सगीर अहमद के बेटे मोहम्मद अल्ताफ मंसूर को जज बनाए जाने की सिफारिश की गई है. अल्ताफ मंसूर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता (चीफ स्टैंडिंग काउंसिल) भी हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे अब्दुल मतीन के सगे भाई अब्दुल मोईन को भी जज बनने योग्य पाया गया है. अब्दुल मोईन उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे ओपी श्रीवास्तव के बेटे रजनीश कुमार का नाम भी जज बनने वालों की सूची में शामिल है. रजनीश कुमार उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल भी हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे टीएस मिश्रा और केएन मिश्रा के भतीजे उपेंद्र मिश्रा को भी जज बनाने की सिफारिश की गई है. उपेंद्र मिश्रा इलाहाबाद हाईकोर्ट के सरकारी वकील हैं. उपेंद्र मिश्र की एक योग्यता यह भी है कि वे बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा के भाई हैं. इसी तरह हाईकोर्ट के जज रहे एचएन तिलहरी के बेटे आरएन तिलहरी और जस्टिस एसपी मेहरोत्रा के बेटे मनीष मेहरोत्रा को भी जज बनने लायक पाया गया है. इनके भी नाम लिस्ट में शामिल हैं. लखनऊ बेंच से जिन सिफारिशी लोगों के नाम जज के लिए चुने गए, उनमें चीफ स्टैंडिंग काउंसिल (2) श्रीमती संगीता चंद्रा और राजकीय निर्माण निगम व सेतु निगम के सरकारी वकील शिशिर जैन के नाम भी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे वीएन खरे के बेटे सोमेश खरे का नाम भी जज के लिए भेजा गया है. इसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्वनामधन्य जज रहे जगदीश भल्ला के भांजे अजय भनोट और न्यायाधीश रामप्रकाश मिश्र के बेटे राजीव मिश्र का नाम भी जजों के लिए अग्रसारित सूची में शामिल है. अंधेरगर्दी की स्थिति यह है कि हाईकोर्ट के जज रहे पीएस गुप्ता के बेटे अशोक गुप्ता और भांजे राजीव गुप्ता दोनों में ही जज बनने लायक योग्यता देखी गई और दोनों के नाम सुप्रीम कोर्ट भेज दिए गए. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सिटिंग जज एपी शाही के साले बीके सिंह का नाम भी अनुशंसित सूची में शामिल है. सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल सीडी सिंह का नाम भी जजों के लिए चयनित सूची में शामिल है.

इस लिस्ट को लेकर सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सरकारी वकीलों (स्टेट लॉ अफसर) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत वकील माना जा सकता है? संविधान के ये दोनों अनुच्छेद कहते हैं कि जजों की नियुक्ति के लिए किसी वकील का हाईकोर्ट या कम से कम दो अदालतों में सक्रिय प्रैक्टिस का 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है. भेजी गई लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने कभी भी किसी आम नागरिक का मुकदमा नहीं लड़ा. काला कोट पहना और पहुंच के बूते सरकारी वकील हो गए, सरकार की नुमाइंदगी करते रहे और जज के लिए अपना नाम अनुशंसित करा लिया. वर्ष 2000 में भी 13 जजों की नियुक्ति में धांधली का मामला उठा था, जिसमें आठ नाम विभिन्न जजों के रिश्तेदारों के थे. अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में कानून मंत्री रहे राम जेठमलानी ने जजों की नियुक्ति के लिए देशभर के हाईकोर्ट से भेजी गई लिस्ट की जांच का आदेश दिया था. जांच में पाया गया कि 159 सिफारिशों में से करीब 90 सिफारिशें विभिन्न जजों के बेटों या रिश्तेदारों के लिए की गई थीं. जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद कानून मंत्रालय ने वह सूची खारिज कर दी थी. उस लिस्ट में शुमार कई लोग बाद में जज बन गए और अब वे अपने रिश्तेदारों को जज बनाने में लगे हैं. इनमें जस्टिस अब्दुल मतीन और जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा जैसे नाम उल्लेखनीय हैं. इम्तियाज मुर्तजा के पिता मुर्तजा हुसैन भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे.

सरकारी वकीलों को जज बना कर पूरी न्यायिक व्यवस्था को शासनोन्मुखी करने का एक तरह से षडयंत्र चल रहा है. कुछ ही अर्सा पहले अधिवक्ता कोटे से जो 10 वकील जज बनाए गए थे, उनमें से भी सात लोग राजीव शर्मा, एसएस चौहान, एसएन शुक्ला, शबीहुल हसनैन, अश्वनी कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार अरोड़ा और देवेंद्र कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश सरकार के वकील (स्टेट लॉ अफसर) थे. इनके अलावा रितुराज अवस्थी और अनिल कुमार केंद्र सरकार के लॉ अफसर थे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता देने में भी भीषण अनियमितता हो रही है. नागरिकों के मुकदमे लड़ने वाले वकीलों को लंबा अनुभव हो जाने के बावजूद उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता नहीं दी जाती, जबकि सरकारी वकीलों को बड़ी आसानी से वरिष्ठ वकील की मान्यता मिल जाती है. कुछ ही अर्सा पहले लखनऊ बेंच के चार वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी गई, जिनमें चीफ स्टैंडिंग काउंसिल आईपी सिंह, एडिशनल एडवोकेट जनरल बुलबुल घोल्डियाल, केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल असित कुमार चतुर्वेदी और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के वकील शशि प्रताप सिंह शामिल हैं. लखनऊ में अनुभवी और विद्वान वकीलों की अच्छी खासी तादाद के बावजूद हाईकोर्ट को उनमें कोई वरिष्ठ अधिवक्ता बनने लायक नहीं दिखता. ऐसे रवैये के कारण वकीलों में आम लोगों के मुकदमे छोड़ कर सरकारी वकील बनने की होड़ लगी हुई है. इसके अलावा जजों के रिश्तेदारों की वकालत का धंधा भी धुआंधार चल रहा है और पनप रहा है. जजों के रिश्तेदार ही जज बन रहे हैं और जजों के रिश्तेदार उन्हीं के बूते अपनी वकालत का धंधा भी चमका रहे हैं. न्याय परिसर में दोनों तरफ से जजों के रिश्तेदारों का ही आधिपत्य कायम होता जा रहा है. ■

न्यायाधीश, न्याय और कॉलेजियम

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जिन लोगों के नाम जज बनाने के लिए भेजे गए थे, उन पर कॉलेजियम की सहमति थी. यह मामला उजागर हुआ तो देश के आम लोगों को न्यायाधीशों और उनके कॉलेजियम की न्यायप्रियता का पता चला. मामला खुलता नहीं तो सारे नाते रिश्तेदार विभिन्न न्यायालयों में न्याय तौलते नजर आते. असलियत में न्यायपालिका और सरकार में टकराव की वजह यही है. इसमें केवल उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है. अन्य राज्यों से भी जज बनाए जाने की जो लिस्ट भेजी गई हैं, उन सबमें मौजूदा या पूर्व जजों के रिश्तेदारों और सिफारिशी-पुत्रों के नाम अटे पड़े हैं. जो अभी व्यवस्था है उसके मुताबिक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में बना कॉलेजियम अपने यहां जजों की नियुक्ति को लेकर अपनी सिफारिशें कानून मंत्रालय को भेजता है. इन प्रस्तावित नामों पर मंत्रालय इंटेलीजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट मांगता है. सारी जांच पूरी होने के बाद नामों की सूची भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेज दी जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम जजों के साथ इस पर आखिरी फैसला लेते हैं. जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस तरह निर्बाध चल रही थी. इसमें बाधा पड़ने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को खारिज कर दिया था. उस समय अलग-अलग उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम द्वारा की गई 115 नामों की सिफारिशें केंद्र सरकार के समक्ष लंबित थीं. इसके बाद केंद्र ने 102 नामों को मंजूरी दे दी और बाकी पर विचार चल रहा था. इन 102 में से सर्वोच्च न्यायालय ने 64 नियुक्तियों पर मुहर लगा दी लेकिन 38 को खारिज कर दिया. अभी करीब सौ नाम और हैं, जिन्हें सरकार ने रोका हुआ है. जजों की नियुक्ति के लिए बन रहे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) के आने के बाद इन पर विचार होगा. बीते साल एनजेएसी को खत्म करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय एमओपी के लिए सहमत हुआ था. सुप्रीम कोर्ट उन प्रावधानों के विरोध में है जो इसकी सर्वोच्च सत्ता में कटौती करे और केंद्र को 'वीटो पावर' दे. एमओपी आने पर शीर्ष न्यायपालिका की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती होगी. इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल कर किसी भी वकील या जिला जज को ऊंची अदालतों में जज नियुक्त किया जाता रहा है. एमओपी में प्रावधान है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की किसी भी सिफारिश को पहले तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे और अगर दोबारा वही नाम भेजा जाए तो बिना कारण बताए उसे खारिज कर दे. अभी कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजे गए नाम को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है. एमओपी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे सुझावों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रही है. ■

चौथी दुनिया में 13-19 जून 2016 के अंक में प्रकाशित ख़बर 'पैरवी में है दम, जज बनेंगे हम' के बाद केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है

इम्पैक्ट न्यूज चौथी दुनिया इम्पैक्ट न्यूज

जज बनाने की सिफारिश में शुमार नाते-रिश्तेदार!

इंटेलिजेंस ब्यूरो को जांच का आदेश देते हुए केंद्र ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो लिस्ट भेजी गई है, उनमें अधिकतर लोग वर्तमान जजों, पूर्व जजों और नेताओं के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. इसके अलावा अन्य जो लोग लिस्ट में शामिल हैं, वे भी सिफारिशी बताए गए हैं.

1. नीरज त्रिपाठी - पुत्र - केशरीनाथ त्रिपाठी, राज्यपाल, पश्चिम बंगाल
2. सोमेश खरे - पुत्र - वीएन खरे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट
3. मोहम्मद अल्ताफ मंजूर - पुत्र - सगीर अहमद, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट
4. अब्दुल मोईन - भाई - अब्दुल मतीन - पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट
5. रजनीश कुमार - पुत्र - ओपी श्रीवास्तव - पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट
6. उपेंद्र मिश्र - भाई - टीएस मिश्र व केएन मिश्र- पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट
7. आरएन तिलहरी - पुत्र - एचएन तिलहरी - पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट
8. मनीष मेहरोत्रा - पुत्र - एसपी मेहरोत्रा - पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट
9. अजय भनोट - भांजा - जगदीश भल्ला - पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट
10. राजीव मिश्र - पुत्र - रामप्रकाश मिश्र - पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट
11. अशोक गुप्ता - पुत्र - पीएस गुप्ता- पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट
12. राजीव गुप्ता - भांजा - पीएस गुप्ता- पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट
13. बीके सिंह - साला - एपी शाही - न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट
14. संगीता चंद्रा - पैरवी पुत्र - चीफ स्टैंडिंग काउंसिल (2)
15. शिशिर जैन - पैरवी पुत्र - राजकीय निर्माण निगम व सेतु निगम के सरकारी वकील
16. सीडी सिंह - पैरवी पुत्र - सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल

feedback@chauthiduniya.com

यूनिफॉर्म सिविल कोड

क्या चाहता है मुस्लिम नौजवान

शफीक आलम

भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का मुद्दा काफी सालों से उठता रहा है. भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय भी इस मुद्दे पर बहस हुई थी. संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में धारा 44 का प्रावधान रखा गया है जिसमें सरकार द्वारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के दिशा में प्रयास करने का उल्लेख है. मोदी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक बड़ा क़दम उठाते हुए लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड के सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है. चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमानों का एक बड़ा तबक़ा विरोध करता रहा है. लिहाज़ा चौथी दुनिया ने यह पड़ताल करने की कोशिश की कि मुसलमानों का नौजवान तबक़ा, ख़ास तौर पर छात्र, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या राय रखता है...

मुसलमानों के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल्कुल ख़िलाफ़ है. देश के मुस्लिम नौजवानों में भी इसकी गूंज साफ़ सुनाई देती है. नौजवानों का एक ऐसा तबका है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर किसी भी बहस के खिलाफ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रहे नासिर हुसैन का कहना है कि संविधान की धारा 44 में कही गई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात ठीक है. लेकिन हम मुसलमान हैं और संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है. अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी बाते होंगी जो हमारी धार्मिक मान्यता के खिलाफ होंगी. खासतौर पर शादी और तलाक के मामले में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो उसमें फिर विरोधाभास आ जाएंगे. लिहाज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ठीक नहीं है. महिलाओं के समान अधिकार के सवाल पर नासिर हुसैन कहते हैं कि औरतों के अधिकार की बात सबसे पहले इस्लाम ने की और कुरान में इसे साफ़-साफ बताया गया है. इस्लाम उन्हें बराबरी का अधिकार देता है, जिसमे तलाक का सिस्टम भी शामिल है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ही पब्लिक एडमिनिट्रेशन में एमफिल कर रहे मजहरुद्दीन की राय भी कमोबेश यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए. इसकी वजह वह यह बताते हैं कि इससे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है. उनका कहना है कि कोई भी धर्म किसी को गलत रास्ता नहीं बताता. यह पूछे जाने पर कि पुराने धार्मिक कानून आधुनिक इंसाफ की अवधारण पर खरे नहीं उतरते तो उनका कहना था कि धर्म सही चीज़ बताता है, लेकिन उनके रहनुमा उसे सही तरीके से उसकी व्याख्या नहीं करते. ज़रूरी है कि मुसलमानों के नेता उन्हें सही रास्ता बताएं, क्योंकि समस्या सामाजिक स्तर पर है. मैं समझता हूं कि इस्लाम औरतों को ज्यादा अधिकार देता है, लेकिन लोग उसका पालन नहीं करते हैं. यह लोगों की गलती है न कि पर्सनल लॉ बोर्ड की, इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है. मजहरुद्दीन साथ ही कहते हैं कि भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने सियासी फायदा लेना चाहती है. जब चौथी दुनिया ने एक दूसरे छात्र मेराज से बात की जो अरबी साहित्य और भाषा में पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना गलत है. उनका कहना है कि हमारी पूरी आस्था कुरान में है. हमें कुरान के हिसाब से जीने दिया जाए. उन्होंने पर्सनल लॉ खासतौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को उनका जायज अधिकार नहीं दिए जाने के सवाल पर कहा कि इस्लाम कभी भी महिलाओं के खिलाफ नहीं रहा है. इस्लाम में जो भी कानून बने हैं, वह बहुत सोच समझकर बने हैं. हम तो यह चाहते हैं कि कुरान से अगर हमारे किसी मसले (सिविल मामलों का) हल निकलता है तो उसमें कोई हस्तक्षेप न हो.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस के छात्र उमर फारूक भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने के खिलाफ हैं. मुस्लिम समाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम सहमति के बाद इसे लागू करने के सवाल पर फारूक कहते हैं कि आप चाहे जितना कानून बना लीजिए इंसान उसे तोड़ता ज़रूर है और उसे आप समाज पर पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते. इसलिए वो मुझे स्वीकार्य नहीं होगा. मिसाल के तौर पर अगर तलाक होता है, तो उसके पीछे कोई वजह होती है बिना वजह कोई अपना घर नहीं बिगाड़ता. मेराज इसमें मीडिया को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं. वे कहते हैं कि औरतें अपनी मर्ज़ी से हिजाब पहन रही हैं और मीडिया यह कह रहा कि उनके पति ने उन्हें ज़बरदस्ती पर्दा करा रहे हैं तो ऐसी चीज़ों से हालात बिगड़ेंगे और फायदा कुछ भी नहीं होगा. जामिया में बीएससी के छात्र फहीम चौधरी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं. उनका मानना है कि पर्सनल लॉ के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. उनका कहना है कि इस देश में हमें अपने धर्म को मानने का अधिकार है, तो हमारे धर्म में जो भी चीज़ें आती हैं उसको भी हमें मानने का अधिकार होना चाहिए. इंटरनेशनल स्टडीज में एमफिल कर रहे मोहम्मद इरफ़ान का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए और मुसलमानों के सिविल मामलों में शरियत के कानून को चलते रहने देना चाहिए. एमबीए की पढ़ाई कर रहे ताहिर अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए कहते हैं कि आप एक मछली को और एक खरगोश को एक साथ नहीं दौड़ा सकते. सबकी प्रकृति अगल-अलग है तो अपनी-अपनी प्रकृति के हिसाब से उनके कानून हैं. अगर वे सबको एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो न मछली तैर पाएगी और न खरगोश दौड़ पाएगा. अगर सिविल कानून को यूनिफॉर्म ही करना है तो इसके और भी तरीके तलाश किए जा सकते हैं. इसलिए हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में नहीं हैं, क्योंकि इसमें हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे.

बहस हो सकती है

छात्रों का एक वर्ग ऐसा भी है जो भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के खिलाफ है, लेकिन उन्हें लगता है यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और इस पर बहस होनी चाहिए. जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से बीएससी कर चुके इंतेख़ाब का मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में खामियां हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को उस समय तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जबतक उससे प्रभावित होने वाले सामज की तरफ से इसे लागू करने की मांग न उठे. वे कहते हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने मुसलमानों के मामलों में हस्तक्षेप करने लगेगी. इसलिए बेहतर यह होगा कि मुसलमानों की तरफ से ही सुधार की सिफारिश की जाए. जामिया में बीए के छात्र मेराज का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में आंतरिक सुधार की गुंजाइश है और इसमें सुधार होने भी चाहिए. लेकिन साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण की नीयत से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला छेड़ा है.

एमएससी कर चुके और बीएड के छात्र इमरान कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है. उनका कहना है कि ये चीज़ें देश की तरक्की के लिए जरूरी नहीं हैं. जिन आपत्तियों को आधार बना कर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही जा रही है, यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद भी वे समस्याएं वैसी की वैसी ही रहीं तो आप फिर क्या करेंगे? इमरान कहते हैं, पर्सनल लॉ पर बहस होनी चाहिए और उसमें ज़रूरी संशोधन भी होने भी चाहिए. मिसाल के तौर पर तीन तलाक है. यह शरिया के हिसाब से ठीक है, लेकिन इसमें अतिरिक्त बंदिश लगा सकते हैं कि यदि आप को तलाक़ देना है, तो फिर गुज़ारा भत्ता वगैरह देना पड़ेगा. इमरान के सहपाठी सलीम उनके इस राय से समहत हैं कि अतिरिक्त बंदिश लगाई जा सकती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस भी हो सकती है, लेकिन वे कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाना चाहिए.

यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी बड़ी समस्याएं हैं मुस्लिम छात्रों का एक वर्ग ऐसा भी है जिनका मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी दूसरी समस्याएं हैं जिनकी तरफ सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए. मिसाल के तौर साम्प्रदायिकता का

मसला हो या फिर सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों की कम नुमाइंदगी का मसला हो. जामिया में ही एमबीए की छात्र ऐमन गिलानी का मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को समान रूप से लागू किया जा सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. साथ में वह यह भी कहती हैं कि समाज के कमज़ोर लोगों को केवल धर्म नहीं प्रभावित करता है, बल्कि कट्टर सोच भी उन्हें प्रभवित करती है. वह कहती हैं कि कट्टर सोच किसी भी रूप में बुरी है. गिलानी यह कहती हैं कि अगर इस्लाम को आप ठीक ढंग से मान रहे हैं तो किसी का हक नहीं मारा जाता. जमीन-जायदाद से लेकर परिवार से संबंधित हर कानून तर्क संगत है. गिलानी सरकार की नीयत पर शक करते हुए कहती हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड से बड़ी समस्याएं हैं, सरकार उन्हें हल करने के लिए कानून क्यों नहीं बनाती? जो देश में साम्प्रदायिक ताकतें मज़बूत हो रही हैं उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं करती? उनका कहना है कि हम छात्र हैं और एम्स जैसे संस्थान में एक भी मुसलमान छात्र को दाखिला क्यों नहीं मिलता? आईआईटी में मुसलमान छात्रों का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है?

इंग्लिश ऑनर्स की छात्र अरिबा कहती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से पुरुष और महिला दोनों प्रभावित होंगे. वह कहती हैं कि देश में जो साम्प्रदायिक समस्या है, वह कभी नहीं जाने वाली है. अगर एक ऐसा सिस्टम आ भी जाता है जिसे सभी मानें तो बहैसियत एक मुसलमान मैं समझती हूं कि हम आज बहुत अधिक असुरक्षित हैं, इस समय हम सबके निशाने पर हैं. हो सकता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अधिक कुर्बानी देनी पड़े और हासिल बहुत कम हो. वह कहती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सौ प्रतिशत भाजपा के सियासी एजेंडे का हिस्सा है यह किसी के भलाई के लिए नहीं किया जा रहा है.

समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए. केरल यूनिवर्सिटी से पास आउट और केरल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा रहे अहमद सिद्दीक का कहना है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को दशकों पहले लागू हो जाना चाहिए था. वह कहते हैं कि एक मुसलमान होने की वजह से मैं समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरी इबादत करने की आज़ादी में किसी प्रकार का बाधा नहीं होगा. दरअसल यह बहुत से पथभ्रष्ट लोगों को खुद के फायदे के लिए इस्लामी कानून को तोड़ने-मरोड़ने से रोकेगा. उनका मानना है कि राज्य और धर्म को पूरी तरह से अलग होना चाहिए. किसी भी वर्ग को विशेष छूट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक हों. यूनिफॉर्म सिविल कोड इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा. सिद्दीक यह भी कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में सियासी दल समाज में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं और जिसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ता है.

रशीद खान का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम इस पर बहस होनी चाहिए. उनका यह भी कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते समय शरियत को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उनकी दलील यह है कि मुसलमानों में शरियत को मानता ही कौन है, इसलिए उसमें बदलाव की गुंजाइश है. कुछ लोग इस्लामी कानून की गलत व्याख्या कर अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं निकलने देते हैं और उनका कहना है कि लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है जो मैं समझता हूं कि मुसलमानों के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह है. बहरहाल यह तो वक्त ही बताएगा कि लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट का अंजाम क्या होता है?

कुल मिलाकर देखा जाए तो इन मुस्लिम नौजवानों की राय वही है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आमतौर पर मुस्लिम समुदाय के अंदर से सुनाई देती है. इसमें एक पक्ष ऐसा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना तो दूर इस पर बहस करने के लिए भी तैयार नहीं. इस पक्ष के मुताबिक मुस्लिम सिविल कानून में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है. जबकि दूसरा पक्ष बातचीत और बहस के लिए तैयार है, लेकिन उसको लगता है कि पर्सनल लॉ की अभी आवश्यकता नहीं है. ऐसे कई क़ानून हैं जिन पर बात होनी चाहिए और जिन्हें लागू किया जाना चाहिए. एक पक्ष है जो मुस्लिम समुदाय के अंदरुनी सहमति से बदलाव का पक्षधर है, लेकिन उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से एतराज है. एक पक्ष ऐसा भी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हर हाल में लागू करवाने के पक्ष में है, लेकिन ज्यादातर नौजवानों का मानना है कि सिविल कोड की बहस के पीछे राजनीति है. उनको लगता है कि भाजपा अपने पुराने एजेंडे को साधने की कोशिश कर रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को ध्रुवीकरण के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड का नक्सलवाद पहुंचा सबसे ख़तरनाक मोड़ पर

नक्सली अब ग्रामीणों से मांग रहे हैं बच्चे

एक अनुमान के अनुसार नक्सली अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग एक हजार बच्चों को उठा चुके हैं, इसमें कुछ नक्सली कैम्प से भागने में सफल रहे हैं. उच्च न्यायालय की कड़ी फटकार के बाद पुलिस हरकत में आई और अभी तक 250 बच्चे, जिसमें कुछ लड़कियां भी हैं, को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया. इन बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए सरकार ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में नामांकन करा दिया है. गुमला के पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने बताया कि इस सूचना के तहत नक्सलियों के खिलाफ 'रुद्र-वन' ऑपरेशन चलाया गया था, जो पूरी तरह सफल रहा. अब जल्द ही 'रुद्र-टू' ऑपरेशन चलाया जायेगा. उन्होंने कहा कि नक्सलियों द्वारा मुखिया से बच्चा मांगने की सूचना पुलिस को अभी तक नहीं मिली है. अगर इस तरह की सूचना सही पायी गयी, तो मुखिया एवं अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी.

प्रशांत शरण

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं पुलिस महानिदेशक डीके पाण्डेय जहां नक्सलियों पर पूरी तरह काबू पाने का दंभ भर रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और है. वे लगातार यह दावा कर रहे हैं कि एक साल के भीतर राज्य को नक्सलमुक्त बना दिया जाएगा, लेकिन राज्य में उग्रवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. इसके साथ ही उग्रवादी संगठनों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है. पहले जहां एमसीसी का एकछत्र राज था, वहीं इस संगठन से टूटकर उग्रवादियों ने अब अपना-अपना संगठन खड़ा कर लिया है. दो दर्जन नक्सली संगठनों का अपना-अपना इलाका है और अपना-अपना वर्चस्व. अपने क्षेत्रों से उग्रवादी संगठन प्रतिमाह करोड़ों रुपए लेवी वसूलते हैं. एक अनुमान के मुताबिक उग्रवादी संगठन प्रतिवर्ष तीन सौ करोड़ से अधिक की राशि लेवी के रूप में वसूलते हैं. उग्रवादियों के कारण ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं. पहले तो केवल लेवी की वसूली होती थी, पर अब नक्सली संगठनों ने अपने संगठन के विस्तार का तुगलकी फरमान जारी किया है. वे हर परिवार से एक बच्चे की मांग कर रहे हैं. बच्चा नहीं देने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है. नक्सली संगठन पहले छोटे-मोटे अपराधियों को संगठन में शामिल करते थे, लेकिन अब नाबालिग बच्चों एवं बच्चियों के मांगने से लोग गांव से अन्यत्र पलायन करने को मजबूर हैं. ग्रामीणों से बच्चा मांगने में सबसे आगे भाकपा माओवादी के सदस्य हैं.

नक्सलियों ने गुमला, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा सहित कई जिलों के मुखियाओं को फरमान जारी कर कहा कि पंचायत चुनाव में हमलोगों ने तुम्हारी सहायता की है, अब अपने-अपने क्षेत्र से दस-दस बच्चे दिलाओ. इस फरमान से कई पंचायतों के मुखिया डरे-सहमे हैं. नक्सली संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि हमलोगों को अब बाल दस्ता बनाकर संगठन को मजबूत करना है. इसलिए हर हाल में बच्चा उपलब्ध कराया जाए. बच्चे को ट्रेनिंग के दौरान हर सुविधा मुहैया कराई जायगी, उसके परिवार को प्रतिमाह एक निश्चित राशि देने की बात कही गयी है. इससे पहले माओवादी गांव में बैठक कर ग्रामीणों पर बच्चा देने का दबाव डालते थे. पूर्व में कई लोगों ने डर से संगठन को बच्चा दे दिया, लेकिन अब ग्रामीण बच्चा देने से इंकार कर रहे हैं. इसे देखते हुए नक्सलियों ने वनोत्पाद के प्रयोग पर रोक लगा दी, पर ग्रामीण नहीं झुके. ग्रामीणों को एकजुट होता देख माओवादी सहित अन्य उग्रवादी संगठन अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर बच्चा दिलाने का दबाव बना रहे हैं. नक्सलियों के डर से बच्चे अब जंगल की ओर नहीं जा रहे हैं. ग्रामीणों के इंकार के बाद माओवादी वनोत्पाद लेने जंगल में भी नहीं घुसने दे रहे हैं. अगर ग्रामीण या बच्चे जंगल में लकड़ी चुनने जाते हैं तो नक्सली उन्हें उठाकर ले जाते हैं.

एक अनुमान के अनुसार नक्सली अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग एक हजार बच्चों को उठा चुके हैं, इसमें कुछ नक्सली कैम्प से भागने में सफल रहे हैं. उच्च न्यायालय की कड़ी फटकार के बाद पुलिस हरकत में आई और अभी तक 250 बच्चे, जिसमें कुछ लड़कियां भी हैं, को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया. इन बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए सरकार ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में नामांकन करा दिया है. गुमला के पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने बताया कि इस सूचना के तहत नक्सलियों के खिलाफ 'रुद्र-वन' ऑपरेशन चलाया गया था, जो पूरी तरह सफल रहा. अब जल्द ही 'रुद्र-टू' ऑपरेशन चलाया जायेगा. उन्होंने कहा कि नक्सलियों द्वारा मुखिया से बच्चा मांगने की सूचना पुलिस को अभी तक नहीं मिली है. अगर इस तरह की सूचना सही पायी गयी, तो मुखिया एवं अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी. नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कराये गये बच्चों से जब यह पूछा गया कि उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तो डरे-सहमे बच्चों ने कोई जानकारी नहीं दी. उन्होंने बताया कि अब भी सैकड़ों बच्चे नक्सलियों के कब्जे में हैं. नक्सली इन बच्चों से सामान एवं हथियार ढोने का काम करवाते हैं. लड़कियों को नक्सली परेशान करते हैं और उनलोगों के साथ गलत भी होता है. डरे-सहमे बच्चों ने बताया कि एक साल पहले नकुल यादव उनलोगों को उठाकर ले गया था. वे लोग संगठन के शीर्ष कमांडर नकुल यादव की देख-रेख में थे. दस्ते से वे खाना बनवाते थे और कुछ गलती करने पर उनलोगों की पिटाई भी की जाती थी. बच्चे हमेशा कैम्प से भागना चाहते थे, पर डर से वे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते थे. लेकिन जब पुलिस के आने की सूचना मिली तो वे लोग भाग निकले. भागे हुए बच्चों में से एक लड़की ने कहा कि उसे बाल दस्ते में शामिल किया गया था. दरअसल नक्सली अपने बचाव के लिए बाल दस्ते का गठन करना चाहते हैं, ताकि बच्चों को आगे कर वे अपना काम आसानी से करा सकें.

इधर, एक अन्य नक्सली संगठन पीएलएफआई ने भी लेवी वसूली के लिए 300 नया कैडर तैयार किया है. इसका मकसद है कि रांची सहित अन्य जिलों में जहां माओवादी कमजोर हुए हैं, उन क्षेत्रों में पीएलएफआई संगठन को मजबूत करना और सरकारी योजनाओं से चल रहे निर्माण कार्यों से लेवी वसूलना. एक अनुमान के अनुसार पीएलएफआई नामक उग्रवादी संगठन पचास करोड़ रुपये लेवी प्रतिवर्ष वसूली करता है. पुलिस जो भी दावा करे, पर हाल के दिनों में उग्रवादी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है. 2015 में जहां 83 उग्रवादी घटनाएं हुई थीं, वहां मई तक ही 102 घटनाएं सामने आ चुकी हैं. उग्रवादियों के साथ 2015 में 9 मुठभेड़ हुई थी, वहीं मई 2016 तक 19 मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं. नक्सलियों ने मई 2016 तक 48 लोगों की हत्या की, जबकि 2015 में 33 लोगों की हत्या उग्रवादियों ने की थी. इस तरह अन्य घटनाओं में भी वृद्धि होती जा रही है.■

नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियानः डीजीपी

झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीके पाण्डेय इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि राज्य को जल्द नक्सलमुक्त बना दिया जायेगा. वे ये दावा भी करते हैं कि झुमरा पहाड़ एवं पारसनाथ जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, से नक्सलियों को पूरी तरह से भगा दिया गया है. नक्सलियों के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान का यह असर हुआ है कि नक्सली अपनी मांद में छुपने को मजबूर हो गए हैं. डीजीपी ने दावा किया कि दो साल के भीतर राज्य में नक्सलियों का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि पारसनाथ को पूरी तरह से नक्सलमुक्त कर दिया गया है, पर हाल में पारसनाथ में पुलिस एवं नक्सलियों की मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मियों की मौत हुई. इस पर उन्होंने कहा कि पारसनाथ को पूरी तरह नक्सलमुक्त बना दिया गया है, पर कुछ नक्सली पुलिस का अभियान देखकर घने जंगलों में छुप गये थे. कुछ नक्सली जो बच गये थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है.■

नक्सली मुख्यधारा में लौटें या परिणाम के लिए तैयार रहें: रघुवर

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का कहना है कि नक्सली मुख्यधारा में लौटें, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें. मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में अब कोई नक्सली गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि नक्सलियों को बंदूक छोड़कर अब मुख्यधारा में लौट जाना चाहिए. राज्य सरकार ने नक्सलियों के लिए नई सरेंडर नीति भी बनायी है. इसके तहत नक्सलियों को नगद राशि के साथ उन्हें पुनर्वासित करने की योजना है. मुख्यमंत्री ने माना कि नक्सलियों की आड़ में अपराधी तत्व सक्रिय हैं और विकास में बाधक बने हुए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है. सरकार की सख्ती से नक्सली दुबक गये हैं. अब पहले से नक्सली घटनाओं में काफी कमी आयी है. छिटपुट घटनाएं तो होती ही रहती हैं. पुलिस को यह आदेश दे दिया गया है कि नक्सली घटना रोकने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े, उठायें. पूरे राज्य में सीमावर्ती राज्यों की मदद से नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पूरे राज्य से नक्सलवाद खत्म कर दिया जायेगा.■

नक्सली लैला नक्सली मजनूं

अब कुख्यात नक्सलियों का शौक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है. सुरा और सुन्दरी उनकी आदतों में शुमार हो रही है. इस दीवानगी में कुछ नक्सलियों की जान भी जा चुकी है. नक्सली भी प्रेमिका के कारण एक-दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं. नक्सली बंदूक के बल पर महिलाओं से जबरन संबंध बनाते हैं, कुछ नक्सलियों के तो एक दर्जन से भी ज्यादा महिला मित्र हैं. नक्सली संगठन द्वारा प्यार की इजाजत नहीं दिये जाने एवं इसे सख्ती से लागू करने के बाद भी नक्सली खुलेआम प्यार के पीछे पागल होते देखे जा रहे हैं. संगठन इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन लड़कियों के चक्कर में संगठन के भीतर खूनी संघर्ष होता रहता है. कुछ दिन पूर्व तृतीय प्रस्तुति कमेटी के वरिष्ठ कमांडर दलाल गंझू और उसके दस्ते ने एमसीसी के एरिया कमांडर रामचरण सिंह की हत्या इसलिए कर दी कि उसने गंझू की भतीजी से जबरन शादी रचा ली थी, जबकि उसकी पहले से दो बीवियां थीं. इसी तरह पतरातू में सोना मांझी नामक युवती के चक्कर में भाकपा माओवादी के कमांडर जगेश्वर यादव की नृशंस हत्या कर दी गई. इस तरह कई नक्सली लड़कियों के चक्कर में नक्सली संगठन छोड़कर महिला नक्सलियों के साथ फरार हो गये हैं. कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन के एक दर्जन से अधिक, विशाल जी की चार महिलाओं के साथ, राजबल्लभ गोप, प्रसाद जी एवं निर्मल जी जैसे कुख्यात नक्सलियों के कई महिलाओं के साथ मधुर संबंध हैं, जबकि यही नक्सली नेता दूसरे नक्सलियों को महिलाओं के साथ इसलिए संबंध नहीं बनाने देते हैं, ताकि वे घर न बसा लें और संगठन न छोड़ दें. पर बड़े नक्सली नेता इस नियम को तोड़ कर महिलाओं के साथ संबंध बना रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

कौन होगा रालोसपा का असली वारिस

सरोज सिंह

बात इतनी आगे निकल चुकी है कि अब वापस लौटने की गुंजाइश बेहद कम है. राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी यानि की रालोसपा के दोनों बड़े नेता खुलकर सियासी मैदान में ताल ठोक रहे हैं. वे यह साबित करने में लगे हैं कि लालू और नीतीश के विरोध में बनी इस पार्टी के असली वारिस वही हैं. दोनों के समर्थक नेता भी बयानबाजी पर उतर आए हैं. ऐसे हालात में यह तय करना मुश्किल है कि रालोसपा पर वास्तव में पहला हक किसका है? चौथी दुनिया ने अरुण की शह और उपेंद्र की मात नामक शीर्षक आलेख में पहले ही यह बात उजागर कर दी थी कि इन दोनों नेताओं की दोस्ती अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है. हालांकि उस समय दोनों नेताओं ने यह कहकर सच्चाई से मुंह मोड़ लिया था कि अभी बात इतनी नहीं बिगड़ी है. लेकिन हालिया घटनाओं और बयानों से स्पष्ट है कि अब दोस्ताने में गहरी दरार पड़ चुकी है. दोनों बड़े नेताओं के रास्ते अलग-अलग हो चुके हैं. लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर दोनों के लिए इसके बाद का रास्ता क्या होगा?

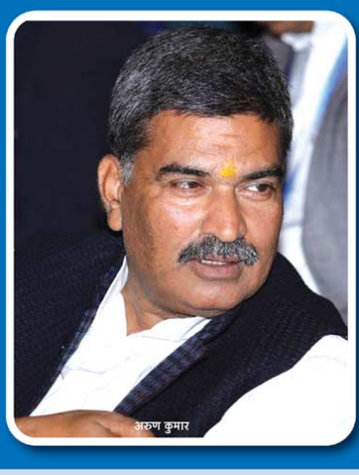
अरुण कुमार

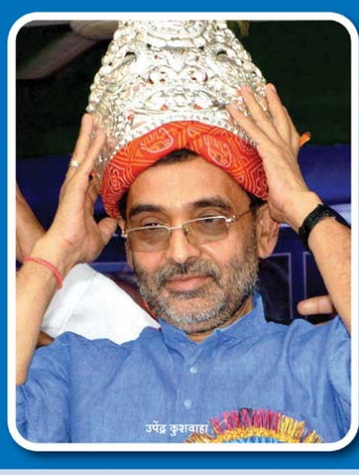
उपेंद्र कुशवाहा

विधानसभा चुनाव के दौरान यह चर्चा गर्म रही कि टिकटों के बंटवारे को लेकर अरुण कुमार का खेमा नाराज है. अरुण कुमार जितनी हिस्सेदारी मांग रहे थे उतना उनको नहीं मिला. वहीं कुछ उम्मीदवारों को भी टिकट बांट दिए गए, जिसे लेकर अरुण कुमार का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया. अरुण खेमा बाजपट्टी से पंकज मिश्रा, रुन्नीसैदपुर से रेखा कुमारी, कुर्था से अशोक वर्मा, नालंदा से हिमांशु पटेल और जगदीशपुर से संजय वर्मा को टिकट दिए जाने के विरोध में था. उपेंद्र कुशवाहा के विरोधियों का कहना है कि जिन नेताओं को टिकट दिया गया है, उनका पार्टी के गठन में कोई योगदान नहीं है. समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर इन क्षेत्रों में ऐसे उम्मीदवारों को जनता पर थोप दिया गया इसलिए चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई.

उपेंद्र कुशवाहा पर दूसरा आरोप है कि उन्होंने तथाकथित दागी उम्मीदवार प्रदीप मिश्रा को तवज्जो दी. इतना ही नहीं चुनाव के समय उनके साथ हेलिकॉप्टर पर भी घूमे. प्रदीप मिश्रा पर अरुण खेमा का आरोप है कि उसके संबंध हवाला कारोबारियों से हैं. वहीं प्रदीप मिश्रा इन आरोपों को बकवास बताकर खारिज करते हैं. उन्होंने इस मामले में अरुण कुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किया है. तीसरा आरोप यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने शशिशंकर कुमार को अपना निजी सचिव बना रखा है. यही शख्स राजेश यादव के नाम से पार्टी का कोषाध्यक्ष भी है.

जहानाबाद सांसद डॉ. अरुण कुमार कहते हैं कि प्रदीप मिश्रा ने राहुल गांधी के पीए के नाम पर झारखंड के राज्यपाल को फोन किया था. इस मामले में वह जेल भी गया. प्रदीप के कहने पर ही चारा घोटाला के आरोपी डॉ. दीपक को पार्टी का झारखंड का अध्यक्ष बना दिया गया था. जब इसके लिए मोटी रकम लिए जाने की बात पार्टी में उठने लगी, तो दीपक के साले राजेश कुमार को अध्यक्ष बना दिया गया. डॉ. अरुण के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ने राजेश यादव को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया और यही व्यक्ति शिवशंकर कुमार के नाम से उनका सहायक निजी सचिव भी है. उपेंद्र ने प्रदीप और राजेश यादव के साथ विदेश यात्रा भी की. इस विदेश यात्रा की जांच होनी चाहिए. यह भी जांच किया जाए कि इस हवाला कारोबारी से मिलकर उपेंद्र कहीं राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? वे कहते हैं कि इस बारे में प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखूंगा. उपेंद्र ने सीमा सक्सेना को राष्ट्रीय सचिव और अपना सलाहकार क्यों बनाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए. मनोज लाल दास मनु का कहना है कि ऐन चुनाव से पहले सीमा सक्सेना की पार्टी में एंट्री होती है और उन्हें एक महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है. आखिर क्यों? जदयू के एक बड़े नेता से सीमा सक्सेना का क्या रिश्ता है, ये सभी जानते हैं. साफ है कि खुफियागिरी के इरादे से सीमा सक्सेना को पार्टी में लाया गया, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा.

उपेंद्र कुशवाहा पर दूसरा आरोप है कि उन्होंने तथाकथित दागी उम्मीदवार प्रदीप मिश्रा को तवज्जो दी. इतना ही नहीं चुनाव के समय उनके साथ हेलिकॉप्टर पर भी घूमे. प्रदीप मिश्रा पर अरुण खेमा का आरोप है कि उसके संबंध हवाला कारोबारियों से हैं. वहीं प्रदीप मिश्रा इन आरोपों को बकवास बताकर खारिज करते हैं. उन्होंने इस मामले में अरुण कुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किया है.

इन आरोपों के जबाव में उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि मुझे झूठ और बेतुकी बातें रचने की कला नहीं आती है. मेरा चरित्र वैसा ही है, जैसा मैं जनता के बीच दिखता हूं. उन्होंने डॉ. अरुण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि समय आने पर जवाब दूंगा. उन्होंने कहा कि क्या गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति अपने पैसे से विदेश नहीं जा सकता है. अगर कोई विदेश ले जा रहा है, तो इसमें क्या अपराध है? मैंने सरकार या पद की ताकत से कभी अपने करीबी को मदद नहीं पहुंचाई है. गरीब घर का आदमी विदेश चला गया, अब यह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उसकी दवा मेरे पास नहीं है. कोई पीएम और प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है, तो मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है. जांच कराना हो, करा लें. मेरा सबकुछ एक खुली किताब की तरह है. उन्होंने आगे कहा-सार्वजनिक जीवन जी रहे व्यक्ति से कई सारे लोग रोज मिलने आते हैं. अब जो उनसे मिलने आता है, तो क्या उससे उसका चरित्र प्रमाणपत्र चेक करके मिला जाता है? राजेश यादव कहते हैं कि दोनों जगह रहने में कोई असंवैधानिक बात नहीं है. बेवजह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है. वे कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की बेदाग छवि और उनके बढ़ते कद से घबराकर कुछ जनाधारविहीन नेता अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं. उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और दिन-ब-दिन मजबूत हो रही है. लेकिन इतना साफ हो गया है कि अब वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा. पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविहारी सिंह कहते हैं कि जिन उसूलों को लेकर पार्टी का गठन हुआ था, उन्हें और मजबूत करने की जरूरत है. आरोप-प्रत्यारोप से तो पार्टी कमजोर ही होगी. बिहार की जनता को पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं. अगर पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरी राजनीतिक कुर्बानी की जरूरत भी पड़ेगी, तो हंसते हुए देने को तैयार हूं.

अब स्पष्ट हो चला है कि इन हालातों में दोनों के बीच सुलह-सफाई की गुंजाइश काफी कम है. वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सभी आरोप-प्रत्यारोप बेवजह लगाए जा रहे हैं. असल कवायद तो पार्टी पर कब्जा करने की है. विधानसभा चुनाव तक तो किसी तरह दोनों नेताओं ने संयम बरता, लेकिन अब कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है. राजनीति की बिसात पर मोहरे बिछ गए हैं और दोनों गुट के लोग चाल चलने में लगे हैं.

इतिहास के पन्नों को पलटें तो राज्य के क्षेत्रीय दलों में कभी नीति को लेकर मतभेद नहीं हुआ. 1990 के बाद जनता दल में कई विभाजन हुए. जॉर्ज फर्नांडीस और नीतीश कुमार इसी सवाल पर अलग हुए क्योंकि उन्हें लालू प्रसाद का नेतृत्व मंजूर नहीं था. रामसुंदर दास से लालू प्रसाद का विवाद भी नेतृत्व के सवाल पर हुआ था. दल के प्रदेश अध्यक्ष के नाते दास की समझ थी कि पार्टी के मातहत सरकार रहे. उधर मुख्यमंत्री के नाते लालू प्रसाद समझ रहे थे कि सत्ता का दूसरा केंद्र बन जाने का असर सरकार के काम-काज पर पड़ेगा. बाद में तो लालू प्रसाद ने शरद यादव का नेतृत्व भी स्वीकार नहीं किया. जनता दल में एक और विभाजन हो गया. राजद के तौर पर नई पार्टी बनी. लोजपा का गठन भी इसी प्रक्रिया के तहत हुआ. रामविलास पासवान भी किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे. रालोसपा, हम या पप्पू यादव की पार्टी के गठन में भी यही पक्ष प्रबल रहा है.

अब स्पष्ट है कि यह रास्ता विभाजन की तरफ ही जा रहा है. दोनों खेमों में तेज मोर्चाबंदी हो रही है. समर्थकों को अपने पाले में मजबूती से करने की कवायद जारी है. शक्ति परीक्षण के अभी कई दौर होने हैं. अरुण खेमा चाह रहा है कि एक बड़े सम्मेलन का आयोजन कर अपनी ताकत का अहसास कराया जाए. उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और उनकी जगह पर अरुण कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए. इसके बाद चुनाव आयोग के पास रालोसपा के स्वामित्व का दावा ठोंका जाए. अरुण खेमे का दावा है कि रालोसपा के ज्यादातर फाउंडर मेंबर उनके साथ हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा का खेमा चाहता है कि अब तस्वीर से परदा उठा दिया जाए. वोट हमारा और राज तुम्हारा की परंपरा से बाज आया जाए और पार्टी विरोधी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए. लड़ाई जारी है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस युद्ध में अंतिम तीर कौन चलाता है और रालोसपा का झंडा अपने नाम करता है.

feedback@chauthiduniya.com

मामला लेवी का, 320 करोड़ की है योजना

मगध के उजाले पर लगा नक्सली ग्रहण

चौथी दुनिया ब्यूरो

झारखंड की सीमा से लगे बिहार में मगध के उग्रवाद प्रभावित इलाके को सौर उर्जा से रौशन करने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना पर ग्रहण लग गया है. सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन कर उग्रवाद प्रभावित मगध के गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल में बिजली आपूर्ति की योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत गया जिले में जीटी रोड स्थित आमस और डोभी में दो सोलर इकाई लगाई जानी है. सौर उर्जा के इन दोनों इकाइयों से बिजली उत्पादन कर जुलाई 2016 में शेरघाटी स्थित पावर सबग्रिड को बिजली की आपूर्ति कर उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्रों को रौशन करने की योजना शुरू होनी थी. स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने व नक्सलियों द्वारा लेवी के लिए काम पर रोक लगाने से अब यह योजना अधर में लटक गई है. नक्सलियों की धमकी के कारण 40 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए शेरघाटी में बन रहे सोलर प्लांट यूनिट का काम ठप हो गया है. गया जिले में नौ प्रखंडों वाला शेरघाटी अनुमंडल उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र माना जाता है. इस अनुमंडल में कोबरा बटालियन, एसएसबी, सीआरपीएफ व बिहार पुलिस के कई थाने और कैंप स्थापित हैं. जंगली और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यह अनुमंडल उग्रवादियों के लिए मुफीद साबित हो रहा है. केंद्र सरकार की योजना के अनुसार गांव में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य तेजी से किया जाने लगा ताकि उग्रवादग्रस्त क्षेत्रों में सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति बहाल की जा सके. इसके तहत गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल में सोलर प्लांट लगाकर पूरे अनुमंडल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया. इस निर्णय के तहत जीटी रोड पर शेरघाटी के नजदीक दो सोलर प्लांट स्थापित किये जाने का काम शुरू हुआ. लेकिन विकास कार्यों की राह में रोड़ा बने नक्सलियों ने इस योजना पर भी रोक लगा दी. इस योजना के सहारे शेरघाटी अनुमंडल मुख्यालय समेत इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, आमस, गुरुआ, मोहनपुर और बाराचट्टी के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की जानी है. शेरघाटी स्थित सोलर प्लांट निर्माण स्थल पर 27 जून 2016 को रात में नक्सलियों ने कार्य स्थल पर पहुंचकर निर्माण कर रहे कंपनी के कर्मचारियों को धमकी दी. उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक संगठन को लेवी नहीं दिया जाएगा, तब तक यहां कोई काम नहीं होगा. अगर बिना अनुमति के काम शुरू किया गया, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इस धमकी के बाद से कार्य स्थल पर सन्नाटा पसरा है. 320 करोड़ रुपये की लागत वाली इस बिजली परियोजना का काम वेलस्पन नाम की एक कंपनी कर रही है. इस योजना के तहत आमस के

सांव व डोभी प्रखंड के बहरा गांव के पास सौर प्लांट की दो अलग-अलग इकाइयां लगाई गई हैं. यहां से उत्पादित बिजली विद्युत लाइन के जरिए शेरघाटी पहुंचेगी और शेरघाटी ग्रिड को बिजली की आपूर्ति की जाएगी. शेरघाटी में बिजली को ग्रिड में ट्रांसफर करने के लिए बस-वे बनाया जा रहा है. नक्सलियों की धमकी के कारण निर्माण कार्य में लगे मजदूर काम छोड़कर भाग गए हैं. इसके बाद ठेका कंपनी के उपाध्यक्ष राजीव कुमार दिल्ली से शेरघाटी पहुंचे और घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली. उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो जुलाई में बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी. लेकिन लगता है अब इस योजना पर लंबे समय तक ग्रहण लग गया है. ठेका कंपनी ने जिला प्रशासन से कार्य स्थल पर सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है. उग्रवादग्रस्त गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल में यदि यह योजना बेहतर तरीके से चालू हो गई तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यों की गति में भी तेजी आएगी. इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने से शेरघाटी के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी. लेकिन लगता है कि मगध के उजाले की योजना को नक्सली अपने लिए खतरा मान रहे हैं. विकास कार्यों में तेजी व इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने से नक्सलियों के ठिकानों तक आसानी से पुलिस की पहुंच संभव है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नक्सली संगठन इन क्षेत्रों में विकास कार्य होने देना नहीं चाहते हैं. यही कारण है कि अक्सर लेवी की मांग कर व धमकी देकर निर्माण स्थल पर कार्य रोक दिया जाता है. 320 करोड़ की इस योजना में भी नक्सलियों ने दस प्रतिशत लेवी की मांग की है. यदि सुरक्षाबलों और जिला प्रशासन का यथोचित सहयोग नहीं मिला तो बिजली उत्पादन की इस महत्वपूर्ण योजना से उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीण वंचित रह जाएंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

मंत्रियों को कर्नाटक हाईकोर्ट का नोटिस

बार काउंसिल के नियमों से बेफ़िक्र हैं कई मंत्री

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 जून को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के उल्लंधन के मामले में नौ लोगों को नोटिस जारी किया था. इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा, कर्नाटक सरकार में मंत्री टीबी जयचंद्र, आरवी देशपांडे, एचके पाटील, वीएस उग्रप्पा, सुरेश कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली व मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं. ये सभी राजनेता कर्नाटक बार काउंसिल में बतौर अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन्होंने मंत्री नियुक्त होने के बाद भी अपना लाइसेंस जमा नहीं कराया है.

चंदन राय

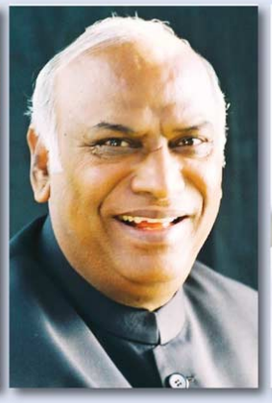

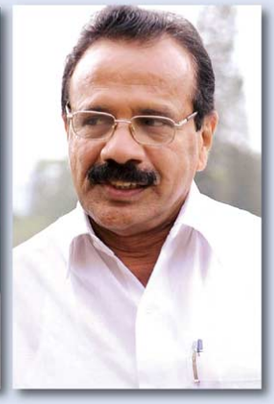

कर्नाटक हाईकोर्ट का एक फैसला वकालत के पेशे से जुड़े केंद्रीय व राज्य सरकार में मंत्रियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 जून को बार काउंसिल के नियमों के उल्लंघन के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा समेत नौ मंत्रियों को नोटिस जारी किया है. अगर इस मामले में वकालत के पेशे से जुड़े मंत्रियों को दोषी करार दिया जाता है, तो इसके दायरे में मोदी सरकार के एक तिहाई मंत्रियों के आने की भी संभावना है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिस तरह इस मामले को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए नोटिस जारी किया है, इससे वकालत से जुड़े केंद्रीय व राज्य सरकार में शामिल मंत्रियों में खलबली मची है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक तिहाई वकील राजनेता शामिल हैं, जो लॉ ग्रेजुएट हैं. इनमें कई राजनेता ऐसे हैं, जो समय-समय पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की पैरवी भी करते हैं. मोदी सरकार के 78 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 25 वकील हैं, जिनमें 11 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं. मोदी सरकार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चेहरों में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, किरण रिजीजू, चौधरी बीरेंद्र सिंह, सदानंद गौड़ा, नीतिन गडकरी, वेंकैया नायडू, रामविलास पासवान, राव इंद्रजीत सिंह, रामकृपाल यादव, राजेन मोहन गोहन, अर्जुन मेघवाल, संतोष कुमार गंगवार, सर्वानंद सोनोवाल, पॉन राधाकृष्णन, कृष्ण पाल, विजय गोयल, फग्गन सिंह कुलस्ते व एसएस अहलूवालिया शामिल हैं. मोदी सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में भी संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील पीपी चौधरी को शामिल किया गया है.

लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट का एक फैसला वकील से राजनेता बने लोगों के गले की फांस बन सकता है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार अगर कोई वकील सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में जाता है तो उसे अपना वकालत का लाइसेंस बार काउंसिल में जमा कराना होता है, जहां उसने रजिस्ट्रेशन कराया है. बेखबरी का आलम ये है कि हाल में कानून मंत्री रहे सदानंद गौड़ा समेत वर्तमान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस नियम की अवहेलना कर रहे हैं. बार काउंसिल के नियम अब तक किताबों के पन्नों तक ही सिमट कर रह गए थे. लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट की सक्रियता के कारण वकालत से राजनीति के पेशे में आए ऐसे तमाम मंत्रियों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 जून को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के उल्लंधन के मामले में नौ लोगों को नोटिस जारी किया था. इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा, कर्नाटक सरकार में मंत्री टीबी जयचंद्र, आरवी देशपांडे, एचके पाटील, वीएस उग्रप्पा, सुरेश कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली व मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं. ये सभी राजनेता कर्नाटक बार काउंसिल में बतौर अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन्होंने मंत्री नियुक्त होने के बाद भी अपना लाइसेंस जमा नहीं कराया है.

एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट नामक एक संस्था ने 2015 के दिसंबर महीने में इस मामले को सबसे पहले उठाया. संस्था ने कर्नाटक लोकायुक्त की अदालत में एक मुकदमा दाखिल किया था. इस मुकदमे में कर्नाटक के कई जाने-माने राजनेताओं को बार काउंसिल के नियमों के उल्लंघन के मामले में आरोपी बनाया गया था. संस्था के अध्यक्ष हुसैन मुइन फारूक का आरोप था कि ये राजनेता वकालत का लाइसेंस बार काउंसिल में जमा कराए बिना ही सरकार से वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं ले रहे हैं. यह व्यावसायिक रूप से गलत तो है ही, साथ ही भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध भी है.

8 जनवरी 2016 को कर्नाटक लोकायुक्त की अदालत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया था. हालांकि लोकायुक्त ने सुनवाई के दौरान यह बात स्वीकार की थी कि ये राजनेता जिन्होंने बार काउंसिल में सनद जमा नहीं कराए हैं, अवैध रूप से वेतन और भत्ते ले रहे हैं. लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन राजनेताओं के वेतन-भत्ते को अवैध मानते हुए भी लोकायुक्त ने मुकदमा खारिज कर दिया. संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि कर्नाटक के बड़े-बड़े राजनेताओं का नाम इस लिस्ट में देखकर दबाव में लोकायुक्त ने यह कदम उठाया होगा. इसके बावजूद फारूक ने हार नहीं मानी. लोकायुक्त के फैसले को चुनौती देते हुए वे कर्नाटक हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए. जस्टिस एल बिल्लप्पा ने उनके आरोपों को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए आरोपी नौ राजनेताओं को नोटिस जारी कर दिया. फारूक का आरोप है कि इनमें से कई नेता तो 30 साल से भी ज्यादा समय से अवैध वेतन और भत्ते ले रहे हैं.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियमावली 49 के अनुसार, एक व्यक्ति वकालत के दौरान किसी भी व्यक्ति, सरकार, संस्था, निगम या इकाई का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हो सकता है. यदि वह वकालत के दौरान किसी ऐसे रोजगार में जाता है, तो उसे बार काउंसिल, जहां कि वह पंजीकृत है, को इसके बारे में जानकारी देनी होती है. जब तक वह ऐसे किसी रोजगार में रहता है, तब तक के लिए उसे अपना लाइसेंस बार काउंसिल में जमा कराना होता है. इसी नियम का हवाला देते हुए फारूक ने हाईकोर्ट में दलील दी कि इन राजनेताओं ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियमावली 49 का जान-बूझकर उल्लंघन किया है.

इतना ही नहीं, फारूक का आरोप है कि पूर्णकालिक रोजगार के दौरान बार काउंसिल में वकालत लाइसेंस का जमा कराना स्वैच्छिक नहीं, बल्कि अनिवार्य होता है. इस संदर्भ में किसी को भी छूट नहीं मिली है. उनका यह भी आरोप है कि इन आरोपियों ने कर्नाटक मिनिस्टर्स सैलरीज एंड एलाउंसेज एक्ट की धारा 14 का भी उल्लंघन किया है. यह एक्ट कर्नाटक में किसी मंत्री के कार्यकाल के दौरान किसी अन्य प्रोफेशन में जाने पर रोक लगाती है. एक्ट के अनुसार, एक मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान कोई व्यापार या पेशा नहीं अपना सकता और न ही अपने पद के अलावा रोजगार के लिए कोई दूसरा पद ग्रहण कर सकता है. फारूक का आरोप है कि इसके अलावा ये राजनेता भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 168, 193, 199, 200, 409, 420, 506 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत दोषी हैं.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियमावली 49 के अनुसार, एक व्यक्ति वकालत के दौरान किसी भी व्यक्ति, सरकार, संस्था, निगम या इकाई का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हो सकता है. यदि वह वकालत के दौरान किसी ऐसे रोजगार में जाता है, तो उसे बार काउंसिल, जहां कि वह पंजीकृत है, को इसके बारे में जानकारी देनी होती है. जब तक वह ऐसे किसी रोजगार में रहता है, तब तक के लिए उसे अपना लाइसेंस बार काउंसिल में जमा कराना होता है.

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार, यदि कोई लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी लाभ प्राप्त करता है, तो वह आपराधिक अवचार का दोषी माना जाएगा. इस मामले में दोषी पाए जाने पर जुर्माने के अलावा कम से कम एक साल व अधिक से अधिक सात साल तक कारावास की सजा का प्रावधान है. अब यदि इस मामले में नौ वकील राजनेताओं को दोषी करार दिया जाता है तो इस फैसले का व्यापक असर होना तय है. इसकी चपेट में वैसे राजनेता व सरकारी पद पर तैनात अधिकारी भी आएंगे, जिन्होंने अपना लाइसेंस बार काउंसिल में जमा नहीं कराया है.

सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने बताया कि एमपी या एमएलए लोक सेवक या जन प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं. ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, जिन्हें कोई नियुक्त करता है. इन्हें वेतन और भत्ता इस मद में दिया जाता है कि वे इन सुविधाओं का उपभोग करते हुए जनता की बेहतर तरीके से सेवा कर सकें. लेकिन जैसे ही ये लोक प्रतिनिधि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मिनिस्टर नियुक्त किए जाते हैं, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आ जाते हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर इन वकालत के पेशे से जुड़े मंत्रियों को बार काउंसिल में इसकी जानकारी देनी होती है, साथ ही वकालतनामा का लाइसेंस भी जमा कराना होता है. उन्हें ये बताना होता है कि इस समयावधि के दौरान वे अदालत में प्रैक्टिस नहीं करेंगे. लेकिन अगर कोई मंत्री नियुक्त होने पर भी वकालत का लाइसेंस जमा नहीं कराता है, तो बार काउंसिल उस पर कार्रवाई कर सकता है. इस संदर्भ में बार काउंसिल उनका वकालत का लाइसेंस रद्द कर सकता है. हालांकि करप्शन ऑफ प्रीवेंशन एक्ट के तहत जुर्माने के अलावा कारावास का भी प्रावधान है.

सभी राजनीतिक दल अपने मंत्रिमंडल में कानून विशेषज्ञों को खास महत्व देने लगे हैं. इसके पीछे उनका तर्क होता है कि वकालत के पेशे से जुड़े राजनेता पार्टी हितों की बेहतर तरीके से रक्षा करते हैं, वहीं मीडिया में बहस के दौरान विरोधियों पर तथ्यों के आधार पर सटीक हमला भी करते हैं. ऐसे विशेषज्ञ बेहतर संवाद शैली व वाक्चातुर्य के कारण सरकारी कार्यक्रमों को जनता में लोकप्रिय बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. हालांकि कानून के जानकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं. वे मानते हैं कि इस मामले में बड़े राजनेताओं पर दंडात्मक कार्रवाई भी मुश्किल है. लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट अगर इन मंत्रियों को दोषी करार देता है, तो वकालत के पेशे से जुड़े मंत्रियों के लिए यह एक खतरे की घंटी है.■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

संविधान और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहनी चाहिए

तीन साल बाद लोक सभा का चुनाव है और कांग्रेस अब भी असुरक्षित, अनिश्चित, दुविधाग्रस्त और अस्पष्ट तरीके से काम करती हुई दिख रही है. यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. मैं इस बात को लेकर चिंतित नहीं हूं कि कौन चुनाव जीतेगा या हारेगा, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में जीवंत और सक्रिय विपक्ष का होना बहुत जरूरी है. हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि वे कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तब वे इसके खतरे को नहीं समझते. आज जनता से वोट करा लें, जनता तो नेतामुक्त भारत चाहती है. जनता की नजर में तो सारे नेता खराब हैं. क्या आप चाहते हैं कि सेना सत्ता संभाल ले? इस तरह की बातें खतरनाक हैं. प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त सरकार, या ये कहें कि हम चुनाव लड़कर फिर पांच साल के लिए सत्ता में आएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को खारिज कर दिया है, जो वहां के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने लगाया था. राजखोवा पूर्व में एक अच्छे नौकरशाह रहे हैं. मेरा मानना है कि आर्टिकल 356 की समस्याओं का पूर्ण विश्लेषण होना चाहिए और इसके इस्तेमाल में संतुलन बनाए रखने का समाधान निकाला जाना चाहिए.

एनटी रामाराव और कई अन्य पार्टियों ने यह मांग की थी कि आर्टिकल 356 और राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए. मेरे अनुसार एक चुनी हुई सरकार बहुमत से सत्ता में आती है और अगर बहुमत खोती है तो सीधे चुनाव में जाना चाहिए. सरकार को बर्खास्त करने का सवाल ही नहीं उठता है. दूसरा मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल तभी करे, जब ऐसा करना अति आवश्यक हो. मेरे अनुसार से आर्टिकल 356 को खत्म करने का विचार सही नहीं है. इसे विद्रोह की स्थिति या देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाए जाने से बचने के लिए बनाकर रखना चाहिए. हालांकि इसका निर्णय कौन करेगा कि कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं? यह उचित नहीं होगा कि एक कानून बना कर यह तय कर दिया जाए कि लोग किस तरीके से व्यवहार करें. यह कोई आज की समस्या नहीं है. नेहरू के समय (1959 में) केंद्र सरकार ने केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, तभी से आर्टिकल 356 के दुरुपयोग के आरोप लगने शुरू हो गए थे. लेकिन वह उस वक्त की एक अकेली घटना थी. दिक्कत तब शुरू हुई, जब दल-बदल में तेजी आई. सरकारिया कमेटी ने भी कहा था कि कोई सरकार बहुमत में है या नहीं, इसका सही निर्धारण सदन के भीतर (फ्लोर ऑफ द हाउस) ही हो सकता है. समस्या तब शुरू हुई जब विधायकों का समूह राज्यपाल से मिलने जाने लगा और राज्यपाल को यह महसूस होने लगा कि अमुक सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है. जबकि राज्यपाल के लिए उचित रास्ता ये होता कि वे मुख्यमंत्री को बुला कर कहें कि आप विधानसभा सत्र बुला कर अपना बहुमत साबित करें.

अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल ने खुद विधानसभा का सत्र बुला लिया और खुद एजेंडा तय कर दिया. निश्चित तौर पर यह काम असंवैधानिक और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का था. केंद्र सरकार आर्टिकल 356 के अन्य प्रावधानों के तहत बिना राज्यपाल की रिपोर्ट मिले भी अरुणाचल सरकार को बर्खास्त कर सकती थी. केंद्र सरकार ने बिना कोई उत्तरदायित्व लिए और सारा भार राज्यपाल पर डालते हुए यह फैसला लिया था. जाहिर है, इससे राज्यपाल की छवि को धक्का लगा. यह सही नहीं है.

राजनेताओं को अपने लिए राजनीति में जिस लक्ष्मण रेखा को खींचना चाहिए, वे वैसी रेखा नहीं खींच पा रहे हैं. जाहिर है ऐसे में न्यायपालिका को अनुशासन की सीख देने की जरूरत पड़ रही है. यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है. न्यायपालिका हमेशा विधायी कार्यों में दखल दे, ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता है. उत्तराखंड और अब अरुणाचल के कटु अनुभव

> **कांग्रेस अभी अपने बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन भाजपा भी अवसर खोती जा रही है. भाजपा को कार्य करने के लिए एक स्पष्ट बहुमत मिला है. उसे राजनीति में नए मानक स्थापित करने चाहिए. गलत चीजों को सुधारना चाहिए. ये सब करने के बजाय भाजपा, कांग्रेस के रास्ते पर ही चलती दिख रही है. उन्हें लगता है कि सत्ता ही सब कुछ है. उन्हें यह समझना चाहिए कि पूर्वोत्तर या किसी छोटे राज्य में सत्ता का कोई मतलब नहीं है.**

के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा को यह बात समझ में आ गई होगी कि राजनीति में सीमा रेखा लांघने से अपना नुकसान ही होता है. इससे उनकी विश्वसनीयता को भी फायदा नहीं पहुंचने वाला है. भाजपा खुद को पार्टी विद डिफरेंस मानती है. उनके नेताओं ने कई बार कहा है कि वे पिछले 60 साल में कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों के ठीक उलट काम करेंगे. लेकिन असल में वे कांग्रेस की ही नकल कर रहे हैं. हर दिन वे वही सब कर रहे हैं, जो पहले कांग्रेस ने किया. 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने दिल्ली विधानसभा का चुनाव कराने के लिए लंबा इंतजार किया. आखिरकार चुनाव हुआ. लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया और केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें हासिल हुईं. बिहार में भी उन्होंने वही सब किया और उन्हें वहां भी पराजय का मुंह देखना पड़ा.

जाहिर है, कांग्रेस अभी अपने बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन भाजपा भी अवसर खोती जा रही है. भाजपा को कार्य करने के लिए एक स्पष्ट बहुमत मिला है. उसे राजनीति में नए मानक स्थापित करने चाहिए. गलत चीजों को सुधारना चाहिए. ये सब करने के बजाय भाजपा, कांग्रेस के रास्ते पर ही चलती दिख रही है. उन्हें लगता है कि सत्ता ही सब कुछ है. उन्हें यह समझना चाहिए कि पूर्वोत्तर या किसी छोटे राज्य में सत्ता का कोई मतलब नहीं है. ये राज्य अपने रोड रेवेन्यू से जुड़े खर्च का दस फीसदी से भी कम इकट्ठा कर पाते हैं और बाकी 90 फीसदी के लिए केंद्र पर निर्भर होते हैं. दल-बदल से कहीं भी सरकार बनाना गलत है और खास कर पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों में सत्ता पाने की लालच में ऐसा करना और भी बुरा है. इससे अनावश्यक अस्थिरता फैलती है. उम्मीद करते हैं कि इस फैसले की उचित समीक्षा की जाएगी. सरकार अपने लिए खुद कुछ पैरामीटर्स तय करेगी कि राज्यपाल को कैसे अपना दायित्व निभाना चाहिए, ताकि इस पद की विश्वसनीयता व साख को और नुकसान न पहुंचे. वैसे तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था की साख ही खतरे में है लेकिन यह दूसरा मुद्दा है, जिस पर अलग से ध्यान दिए जाने की जरूरत है. लेकिन संवैधानिक पद की महत्ता बरकरार रहनी चाहिए.

हमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, जिससे इस संवैधानिक पद (राष्ट्रपति का पद) की गरिमा को नुकसान पहुंचे. उत्तराखंड मामले में उन्होंने कैबिनेट के भेजे हुए सिफारिश (उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन) पर हस्ताक्षर नहीं किया और उसे पुनर्विचार के लिए कैबिनेट को भेज दिया. उन्होंने इस मामले में संविधान के बताए रास्ते पर चलने का फैसला किया. जब कैबिनेट ने उन्हें दोबारा सिफारिश भेजा तब उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया. इसके बाद जो भी परिणाम होगा, उसका सामना केंद्र सरकार और कैबिनेट को करना होगा. मैं समझता हूं कि अब भाजपा को राजनीति में बेहतर मानक तय करने चाहिए.

दूसरा मुद्दा है मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक का, जिन्हें मैंने कुरान की व्याख्या करते हुए कई बार टीवी पर सुना है. मैं उन्हें इस बात का क्रेडिट देता हूं कि वे टीवी पर मुस्लिम दर्शकों के कठिन सवालों के जवाब देते हैं. इनमें कुरान से जुड़े सवालों के अलावा कई अव्यावहारिक सवाल भी होते हैं. किसी अच्छे उपदेशक की तरह नाइक कुरान और शरीयत की व्याख्या करते हुए लोगों को अपने जवाब से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं. इस देश में यह सब ठीक है. लेकिन अभी जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है. मैं नहीं जानता कि वे आतंकवाद वगैरह की बातें कर रहे हैं. देश का कानून इस मामले में अपना काम करेगा. अगर उन्होंने सचमुच कुछ ऐसा बोला है, जिस पर कार्रवाई हो सकती है, तो पुलिस को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए. अन्यथा मैं नहीं समझता कि उन्हें सिर्फ इसलिए गाली दी जाए कि वे मुस्लिम समुदाय से हैं या हमें वो बात पसंद नहीं है जो वे बोलते हैं. आखिरकार, बोलने की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ स्पीच) का क्या मतलब है. फ्रीडम ऑफ स्पीच का अर्थ है कि जो बात हमें पसंद नहीं है, उस बात को बोलने की स्वतंत्रता भी किसी व्यक्ति को हो. अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वही बोले जो हमें पसंद है, तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की जरूरत क्या है? कोई व्यक्ति मुख्यधारा की बातों के विपरीत भी बोलता है, तो उसे इसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उसके इस स्वतंत्रता की रक्षा भी की जानी चाहिए. हां, ये जरूर है कि किसी की बातों से कानून और व्यवस्था की समस्या न खड़ी हो. अगर ऐसा होता है तो पुलिस है, कानून है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए.

अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है. अभी चार पार्टियों में वहां कांग्रेस निश्चित तौर पर चौथे नंबर की पार्टी है. कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक ऐसी ताकत चाहते हैं, जो पार्टी को सक्रिय बना सके. राज बब्बर को यूपी कांग्रेस कमेटी का मुखिया बनाया गया है. प्रशांत किशोर चाहते हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान का नेतृत्व करें. मुझे नहीं मालूम कि इस सब से क्या मदद मिलेगी? लेकिन तथ्य ये भी है कि तीन साल बाद लोक सभा का चुनाव है और कांग्रेस अब भी असुरक्षित, अनिश्चित, दुविधाग्रस्त और अस्पष्ट तरीके से काम करती हुई दिख रही है. यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. मैं इस बात को लेकर चिंतित नहीं हूं कि कौन चुनाव जीतेगा या हारेगा, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में जीवंत और सक्रिय विपक्ष का होना बहुत जरूरी है. हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि वे कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तब वे इसके खतरे को नहीं समझते. आज जनता से वोट करा लें, जनता तो नेतामुक्त भारत चाहती है. जनता की नजर में तो सारे नेता खराब हैं. क्या आप चाहते हैं कि सेना सत्ता संभाल ले? इस तरह की बातें खतरनाक हैं. प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त सरकार, या ये कहें कि हम चुनाव लड़कर फिर पांच साल के लिए सत्ता में आएंगे. इस तरह की बात करना सही है. लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर आप लोकतंत्र की महत्ता को ही कम करते हैं. उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कहां तक सफल होती है या कांग्रेस में कितना जान डाल पाती हैं, नहीं पता. ये कांग्रेस का आंतरिक फैसला है. हम और आप सिर्फ इंतजार करें. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

घोटालेबाजों की सरकार

कवर स्टोरी- अखिलेश जी! सात हजार करोड़ कहां हैं? (11 जुलाई-17 जुलाई, 2016) ने बेहद प्रभावित किया. प्रभात रंजन दीन ने उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने की ओर जनता का ध्यान बखूबी आकर्षित किया है. स्टोरी बताती है कि सारे विद्युत सब-स्टेशन बन गए और मुख्यमंत्री ने फीता काट कर उसे शुरू करा दिया. राजकीय निर्माण निगम समेत अन्य निर्माता कंपनियों का भुगतान भी हो गया, लेकिन करीब सात हजार करोड़ रुपया गायब है. उसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है. सच है कि प्रदेश का विकास कभी सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा, उसकी प्राथमिकता में केवल कॉरपोरेट्स रहे हैं.

–राकेश कुमार, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

ईमानदार सोच की जरूरत

आलेख-नीलगाय के साथ हाथी बंदर, सुअर भी निशाने पर (11 जुलाई-17 जुलाई, 2016) पढ़ा. शशि शेखर का आलेख विश्लेषणात्मक एवं तथ्यपरक है. आलेख से पता चलता है कि बिहार में नीलगायों को मारे जाने को लेकर खुद मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच वाकयुद्ध जारी है. सवाल उठता है कि क्या फसल को नुकसान से बचाने का एकमात्र रास्ता इन जानवरों को मारना ही है? क्या सरकार को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि आखिर ये जानवर जंगल से खेतों की ओर या रिहायशी इलाकों की ओर क्यों आ रहे हैं? हमने खुद जंगल और इन जानवरों के प्राकृतिक आवास को कितना नुकसान पहुंचाया है, क्या इस पर ईमानदारी से सोचने की जरूरत नहीं है?

–परमानंद मिश्र, *बेगुसराय, बिहार.*

किसके हाथ होगी सत्ता

जब तोप मुकाबिल हो-अब ख़ाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई... (11 जुलाई-17 जुलाई, 2016) पढ़ा. प्रभावित करने वाला संपादकीय है. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि यूपी का चुनाव भाजपा के लिए वाटरलू साबित हो सकता है, कांग्रेस और मुलायम के लिए भी हो सकता है. कौन अपने साथ विधायकों की कमी पूरा कर सकता है, ये रणनीति देखने लायक होगी. सवाल है कि जिस तरह मुलायम को अनुमान

से ज्यादा यूपी में सीटें मिलीं, क्या इस बार मायावती को अनुमान से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं. अगर ऐसा है तो यूपी तमिलनाडु के रास्ते पर चल पड़ेगा. जहां बाकी लोग समझौते की आस में बैठे रह जाएंगे और या तो बसपा या सपा सत्ता के नजदीक पहुंच जाएगी.

–अभिनव कुमार, *उन्नाव उत्तर प्रदेश.*

अनाथ हैं गोद लिए गांव

आलेख-अच्छे दिनों पर भारी आदर्श ग्राम पठारी (11 जुलाई- 17 जुलाई 2016) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक लेख है. इसरार पठान ने अपने आलेख में सही कहा है कि अच्छे दिन आने के दावे और वादे की उम्र दो साल हो चुकी है. लेकिन अब भी अच्छे दिनों का इंतजार जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की सरकार बनने की बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी और सांसदों को कहा था कि वे एक-एक गांव गोद लें. लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के दावे खोखले साबित हो रहे हैं. सफाई के मामले में भी गांवों की दशा खराब है. दस हजार की आबादी वाले गांव में सिर्फ एक सफाई कर्मी की नियुक्ति की गई है. यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि शौचालयों का धन पहले ही गांव के पूर्व प्रधान और सचिव ने मिलकर डकार लिए. यही देश के प्रत्येक गांव की सच्चाई है.

–कमला प्रसाद, *झांसी, उत्तर प्रदेश.*

कश्मीर समस्या का हल तो निकालिए

कमल मोरारका ने अपने आलेख-नेहरू नहीं होते तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता(11 जुलाई- 17 जुलाई 2016) में सही कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के वैचारिक विकल्प के रूप में भारतीय जन संघ की स्थापना की थी. दरअसल यह लोकतंत्र का हिस्सा है. वैचारिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एक रहना चाहिए. राजनीतिक दलों में मतैक्य हो तो कश्मीर समस्या का समाधान भी निकाला जा सकता है. भाजपा हमेशा कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताती रहती है जो बिल्कुल असत्य है. नेहरू के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए कि उन्होंने अभी तक कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाया है? सिर्फ नेहरू की आलोचना करने और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने से कश्मीर की समस्या का कोई हल नहीं निकलने वाला है.

–हिमांशु शेखर, *पालम, दिल्ली.*

दिलचस्प होगा चुनाव

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय रह गया है. सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत के लिए जोर-आजमाइश शुरू कर दी है. कांग्रेस ने शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं भाजपा में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची जारी है. मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में भगदड़ मची हुई है. स्वामी प्रसाद मौर्य और आरके चौधरी जैसे कद्दावर नेताओं ने मायावती पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आए सर्वे में बहुजन समाज पार्टी को बढ़त दिखाया गया था, लेकिन बसपा में फूट के बाद कुछ और तस्वीर नजर आ रही है. सपा की पारिवारिक लड़ाई अब सतह पर दिखने लगी है, जिससे सपा कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है.

–नमिता सिंह, *गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश.*

मूल सवाल तो छूट गया

चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशिल खबर *ऐसे समझौता का क्या मतलब* (11 जुलाई-17 जुलाई 2016) पढ़ा. नगा बागी संगठन एनएसीएन-आईएम और केंद्र सरकार के बीच कई वर्षों से शांति वार्ता चल रही है. लेकिन हाल में सोशल मीडिया में अलग झंडा और पासपोर्ट की खबर ने वार्ता की मूल बातों से लोगों के ध्यान को भटका दिया है. यह दुखद है कि नॉर्थ ईस्ट की खबरों को मुख्यधारा की मीडिया में कोई जगह नहीं मिलती है. अलग झंडा और पासपोर्ट की बात को न तो मीडिया ने दिखाया और न ही इस पर कोई चर्चा हुई. मुझे आशा है कि मीडिया सही मुद्दे को सामने लाएगा.

–समुज्जल, *गुवाहाटी, असम.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कश्मीरियों को भी अपना समझिए

कश्मीर के बारे में कुछ भी कहना देशभक्ति या देशद्रोह का विषय बन जाता है. कश्मीर में अगर असंतोष या इससे जुड़ी गतिविधियां होती हैं, तो उन्हें तुरंत प्रायोजित गतिविधियां मान लिया जाता है. हमारा ये स्पष्ट मानना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. अगर हम कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, तब हमें कश्मीर के लोगों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा हम पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से करते हैं. दुर्भाग्यवश पिछले साठ साल में देश के दिमाग में कुछ लोगों ने ये बात बैठा दी है कि कश्मीर के लोगों को सिर्फ बंदूक के बल पर अपने कब्जे में किया जा सकता है. सवाल उठता है कि अगर बंदूक के बल पर ही देश के निवासियों पर राज करना है, तो क्या हम लोकतंत्र, विचार, बातचीत और समझाने-बुझाने का केवल नाटक कर रहे हैं?

अभी कश्मीर में बुरहान वानी की वारदात के बाद फैले असंतोष के जवाब में या इस असंतोष को दबाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. प्रशासन ने अगर इसमें कोताही की होती, तो कश्मीर में काफी नुकसान होने की आशंका थी. इसमें सार्वजनिक संपत्ति का ज्यादा विनाश होना निश्चित था. इसके साथ ही वहां इंटरनेट सेवाएं, जिनमें फेसबुक व वाट्सएप सेवा भी शामिल है, बंद कर दी गईं. प्रशासन ने अपनी समझ से उचित किया होगा, लेकिन इसके कारण कश्मीर में ज्यादा तेजी से अफवाहें फैलीं. अफवाहों का बाजार गरम होने से लोगों का गुस्सा भड़का. 18 से 24 साल के नौजवान आजकल फेसबुक और वाट्सएप के जरिए अपने अंदर के सारे गुस्से को निकालने की कोशिश करते हैं. पूरे देश में सोशल मीडिया के नाम पर फेसबुक और वाट्सएप मुख्य स्थान रखते हैं. इन दोनों सोशल साइट्स में झूठी-सच्ची, नफरत व प्यार फैलाने वाली हर तरह की ख़बरें या पोस्ट दिखाई देती हैं. वे वहीं लिखी जाती हैं और वहीं अपना दम तोड़ देती हैं. इसमें कोई दोराय नहीं कि सोशल मीडिया ने दिल्ली या नरेंद्र मोदी के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. इस बार कश्मीर में अशांति के दौरान देखा गया कि वे नौजवान जो फेसबुक या वाट्सएप के जरिए अपनी भड़ास निकाल लेते थे, जब उनसे ये सुविधाएं छीन ली गईं, तब वे सड़कों पर उतर आए. हो सकता है प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया हो, लेकिन इन दोनों सेवाओं के बंद होने का एक बड़ा परिणाम ये हुआ कि 18 से 24 साल के नौजवान सड़कों पर उतरे, उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की और

अभी कश्मीर में बुरहान वानी की वारदात के बाद फैले असंतोष के जवाब में या इस असंतोष को दबाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. प्रशासन ने अगर इसमें कोताही की होती, तो कश्मीर में काफी नुकसान होने की आशंका थी. इसमें सार्वजनिक संपत्ति का ज्यादा विनाश होना निश्चित था. इसके साथ ही वहां इंटरनेट सेवाएं, जिनमें फेसबुक व वाट्सएप सेवा भी शामिल है, बंद कर दी गईं. प्रशासन ने अपनी समझ से उचित किया होगा, लेकिन इसके कारण कश्मीर में ज्यादा तेजी से अफवाहें फैलीं. अफवाहों का बाजार गरम होने से लोगों का गुस्सा भड़का. 18 से 24 साल के नौजवान आजकल फेसबुक और वाट्सएप के जरिए अपने अंदर के सारे गुस्से को निकालने की कोशिश करते हैं. पूरे देश में सोशल मीडिया के नाम पर फेसबुक और वाट्सएप मुख्य स्थान रखते हैं.

सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया. अगर फेसबुक और वाट्सएप सुविधाएं बंद नहीं हुई होतीं, तो सड़क पर उतरे इन नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा इन सोशल साइट्स पर गालियां देकर या उकसाने वाली पोस्ट लिखकर ही रह जाता, वे खुद सड़क पर नहीं उतरते. चूंकि वे विरोध-प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे तो पुलिस की गोली का निशाना भी वे ही बने. बहुत दिनों के बाद कश्मीर में कर्फ्यू लगा.

कश्मीर में लगे इस कर्फ्यू ने वहां के लोगों के जीवन को दुखदायी बना दिया. आम लोगों को रोजमर्रा की चीजें मिलने में काफी दिक्कतें हुईं. हालांकि प्रशासन और स्थानीय विधायकों ने कर्फ्यू के दौरान लोगों की पूरी मदद की. उन्होंने टेलीविजन पर ऐसे नंबर भी जारी किए ताकि किसी आवश्यक सामान की कमी होने पर वहां सूचना देकर उन चीजों को उपलब्ध कराया जा सके. हालांकि बहुत सारी जगहों पर प्रशासन ने जरूरी सामान भिजवाया भी, लेकिन वे सभी लोगों तक नहीं पहुंच सके. तीन बच्चों की मां ने अपने भाई को फोन किया कि उसके पास पीने का पानी खत्म हो गया है. भाई परेशान होकर इस उम्मीद में चारों तरफ घूमता रहा कि किसी तरह अपनी बहन के यहां पानी भिजवा सके. कश्मीर में इस कर्फ्यू के दौरान लोगों को पीने के पानी की बहुत परेशानी हुई. लोग दुकानों से पानी खरीदने नहीं जा सकते थे, घरों में पानी बंद हो चुका था. खाने-पीने के सामान के बिना तो कुछ वक्त गुजारा जा सकता है, पर पानी के बिना वक्त बिताना बहुत तकलीफदेह होता है. इस तरह के बहुत से वाकये कश्मीर से निकलकर दिल्ली तक पहुंचे हैं. ये वाकये बताते हैं कि अगर प्रशासन थोड़ी सूझ-बूझ से काम लेता तो कश्मीर में उग्र असंतोष से बचा जा सकता था. लेकिन पूरे देश में फेसबुक और वाट्सएप के जरिए कश्मीर के सारे लोगों को देश विरोधी मानकर ऐसी भावना फैला दी गई कि यहां बिना गोली के काम नहीं चल सकता. हम फेसबुक पर देखते हैं कि कश्मीरियों को मारने और जला देने के फरमान बुरी तरह से छाए हुए हैं. जो लोग फेसबुक पर ये लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एक चींटी तक नहीं मारी होगी. वे इतने डरपोक हैं कि अपने कमरे से निकलकर बाहर किसी सेमिनार में इस बात को कहने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहे हैं. लेकिन देश में नफरत और घृणा फैलाना उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रखा है. इस रवैये से कश्मीर को हम कितने दिनों तक अपने साथ रख पाएंगे. कश्मीर समस्या पर बोलने वाली महिला पत्रकारों को फेसबुक पर ये तथाकथित भारतीय संस्कृति के पुजारी पत्रकारिता की वैश्या कहकर संबोधित कर रहे हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता का इन्हें समर्थन नहीं है, लेकिन भाड़े के टट्टू पैसे लेकर घृणा फैलाने में विदेशी ताकतों का मोहरा बने हुए लोग देश में दुर्भावना का माहौल पैदा कर रहे हैं. इसका मुकाबला करने के लिए सिविल सोसायटी को आगे आना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह सिविल सोसायटी आगे आने में देर कर रही है. आज इतना अवश्य कहना है कि प्रशासन ने कश्मीर में समझदारी का काम लिया. थोड़ी और समझदारी का काम लेते तो शायद कश्मीर में इतना लंबा कर्फ्यू वर्षों के बाद नहीं लगता.

editor@chauthiduniya.com

ब्रिटिश ही खेल सकते हैं ब्रेक्जिट का जुआ

मेघनाद देसाई

अब सभी को पता चल गया है कि ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री एक महिला होंगी. कंजरवेटिव पार्टी की संसदीय दल की दो दौर की वोटिंग के बाद तीन पुरुष उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गए. हालांकि दो उम्मीदवार तो पहले ही दौर में बाहर हो गए थे, जबकि तीसरे उम्मीदवार मिशेल गोव, जो ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाने (ब्रेक्जिट) के बड़े प्रचारकों में से थे, दूसरे दौर में जाकर बाहर हुए. जब बोरिस जॉनसन अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करने वाले थे, तभी उनके मित्र गोव ने उनके साथ विश्वासघात किया इसलिए वे ब्रिटिश लोगों में गैर भरोसेमंद समझे जाने लगे थे. इसके बाद केवल दो महिला उम्मीदवार ही मैदान में रह गई थीं. इनमें थेरेसा मे को दो तिहाई वोट मिले, जबकि एंड्रिया लीड्सम को एक चौथाई. थेरेसा मे अनुभवी राजनेता हैं. वे कंजरवेटिव पार्टी की चेयरपर्सन और छह साल तक गृह मंत्री (गृह सचिव) रह चुकी हैं. यह हालिया दौर में किसी गृह मंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है. लीड्सम की अभी बतौर नेता ठीक से परख नहीं हुई है. हालांकि वे 2010 से संसद में हैं, लेकिन वे केवल एक जूनियर मंत्री रही हैं.

अब पार्टी के साधारण सदस्यों को इन दो महिला नेताओं में से किसी एक को अपना नेता चुनना है जो यूनाइटेड किंगडम की अगली प्रधानमंत्री होंगी. लीड्सम के मैदान से हट जाने के बाद अब थेरेसा मे का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है. ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर आने (ब्रेक्जिट) के पक्ष में टोरी पार्टी के सदस्यों में ज़बरदस्त रुझान था. इसलिए एक कम अनुभव वाला उम्मीदवार जीत जाए, इसकी गुंजाइश कम ही थी.

जैसी अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति 24 जून के बाद (ब्रेक्जिट के जनादेश के बाद) देखने को मिली, वैसी स्थिति मैंने पिछले 51 वर्षों के अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान कभी नहीं देखी थी. हम कह सकते हैं कि हमारे यहां एक प्रधानमंत्री था जिसने जनमत संग्रह के नतीजे आने के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा कर (लेकिन नए नेता के चुनाव तक पद पर बने रहने का फैसला कर) खुद को पंगु बना लिया. इसका नतीजा यह हुआ कि जब तक कोई नया नेता प्रधानमंत्री पद संभाल नहीं लेता, तब तक ब्रेक्जिट के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता. उम्मीद है कि नई सरकार सितंबर के शुरू में अपना कार्यभार संभाल लेगी, लिहाज़ा दो महीने तक यहां कोई सीरियस सरकार नहीं रहेगी. हालांकि इस स्थिति का एहसास यहां की सड़कों पर नहीं दिखेगा. यहां ब्रिटिश लोगों की ज़िन्दगी अपने सामान्य रफ़्तार से चलती रहेगी, लेकिन ये भी तय है कि इस दौरान सियासी दुनिया में अव्यवस्था बनी रहेगी. ऐसी स्थिति में कोई दूसरा देश अस्थिरता का शिकार हो जाता, लेकिन बहुत पुराना देश होने के कारण ब्रिटेन में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी.

पार्टी को टूटने से बचाने के लिए कैमरन ने जनमत संग्रह का आदेश दिया था. दरअसल यह फैसला एक जुआ था और इसमें वे हार गए. अब कोई नहीं जानता कि नई सरकार बन जाने के बाद भी पार्टी टूटने से बच पाएगी या नहीं. पार्टी में आपसी रंजिश और वैचारिक मतभेद अब इतने बढ़ गए हैं कि यहां शांति की संभावना कम ही दिखती है.यह बदलाव का क्षण है. जल्द ही नए नेता को यूके के ईयू से बाहर जाने की वार्ता के लिए अपनी रणनीति तैयार करनी होगी. उम्मीद है कि इसमें कम से कम दो साल का समय लगेगा.

दरअसल ब्रेक्जिट वोटिंग, जिसे बेशक जनमत संग्रह कहा जाना चाहिए, की उत्पत्ति कंजरवेटिव पार्टी के हालिया इतिहास में छुपी हुई है. उस दौरान मागरिट थैचर के नेतृत्व को यूरोप-हिमायती सांसद मिचेअल हेसेलटाइन ने 1990 में चुनौती दी थी. थैचर पहले राउंड में पर्याप्त वोट हासिल करने में नाकाम रही थीं. उन दिनों विजेता पक्ष को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 10 प्रतिशत अधिक वोट हासिल करना होता था. नतीजा यह हुआ कि उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था.

उसके बाद से थैचर के समर्थक टोरी (कंजरवेटिव) यूरोप से नफरत करने लगे थे. इस झगड़े ने जॉन मेजर को बहैसियत एक कमजोर प्रधानमंत्री बना दिया. इसका खामियाजा पार्टी को लगातार तीन पराजय के रूप में भी भुगतना पड़ा. इसके बाद वर्ष 2005 में डेविड कैमरन ने कंजरवेटिव पार्टी को जीत दिलाई.

पार्टी को टूटने से बचाने के लिए कैमरन ने जनमत संग्रह का आदेश दिया था. दरअसल यह फैसला एक जुआ था और इसमें वे हार गए. अब कोई नहीं जानता कि नई सरकार बन जाने के बाद भी पार्टी टूटने से बच पाएगी या नहीं. पार्टी में आपसी रंजिश और वैचारिक मतभेद अब इतने बढ़ गए हैं कि यहां शांति की संभावना कम ही दिखती है.

यह बदलाव का क्षण है. जल्द ही नए नेता को यूके के ईयू से बाहर जाने की वार्ता के लिए अपनी रणनीति तैयार करनी होगी. उम्मीद है कि इसमें कम से कम दो साल का समय लगेगा. फिर इसके बाद वैकल्पिक उपाय की तलाश में भी कम से कम दो साल का समय लगना तय है. वर्ष 2020 में जाकर हमें पता चल पाएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं. दरअसल इस तरह का जुआ केवल ब्रिटिश ही खेल सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

हरपिस सिंप्लेक्स नामक बीमारी से हर सप्ताह आठ बच्चों की मौत

मौत की गोद में समा रहे नौनिहाल

एक सप्ताह के भीतर जिन आठ बच्चों की मौत हो चुकी है, उन बच्चों की मौत की वजह क्या है, अभी तक यह नहीं पता चल पाया है. इस नई बीमारी के बारे में जानकारी मिलने से मगध के पांच जिलों गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत है, क्योंकि इन्हीं पांच जिलों से इस बीमारी से ग्रस्त बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं. दहशत की वजह यह है कि अज्ञात बीमारी का वायरस तो सक्रिय है ही और अब बारिश शुरू होने की वजह से जापानी इंसेफ्लाइटिस का भी खतरा मंडराने लगा है. पिछले वर्ष मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट सिंड्रोम इंसेफ्लाइटिस के कुल 124 मामले आए थे, जिनमें से 25 बच्चों की मौत हो गई थी.

सुनील सौरभ

बिहार के मगध प्रमंडल में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट सिंड्रोम इंसेफ्लाइटिस नामक बीमारी यहां के नौनिहालों के लिए बारिश का मौसम आते ही काल बन जाती है. प्रत्येक वर्ष इस बीमारी की वजह से कई बच्चों की मौत हो जाती है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में मगध के पांच जिलों में सौ से अधिक बच्चों की मौत जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट सिंड्रोम इंसेफ्लाइटिस की वजह से हो चुकी है. यह आंकड़े अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने वाले बच्चों की है. यह आंकडे बीमार की वजह से सरकारी अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के हैं और जिन बच्चों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई वो आंकडे इसमें शामिल नहीं हैं.

पिछले दो महीने से मगध के ग्रामीण क्षेत्रों से अज्ञात बीमारी से ग्रस्त बच्चे गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल पहुंच रहे थे, लेकिन चिकित्सकों को समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों में कौन सी बीमारी है? चिकित्सकों ने पहले जापानी इंसेफ्लाइटिस समझ कर बच्चों का इलाज शुरू किया, लेकिन जांच यह नहीं पता चल पा रहा था कि क्या बीमारी है? जब तक पता चल पाता कि बीमारी क्या है, तब तक आठ बच्चों की मौत हो गई. अज्ञात बीमारी से ग्रस्त बच्चों की संख्या भी अस्पताल में बढ़ने लगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गया जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के उच्च पदाधिकारियों को दी. उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की पुणे, दिल्ली और पटना से एक विशेषज्ञों की टीम आई जिसने मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती बच्चों को देखा. विशेषज्ञों की टीम ने जब अज्ञात बीमारी से ग्रस्त बच्चों की जांच की तो एक नई बीमारी हरपिस सिंप्लेक्स का पता चला. विशेषज्ञों के अनुसार हरपिस सिंप्लेक्स दूसरे वायरस की तरह ही दिमाग पर तेजी से असर करता है और साथ ही शरीर के कुछ हिस्सों को अपंग भी बना देता है. जिन बच्चों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनके लिए यह बीमारी खतरनाक है. हालांकि

एक सप्ताह के भीतर जिन आठ बच्चों की मौत हो चुकी है, उन बच्चों की मौत की वजह क्या है? यह नहीं पता चल पाया है. इस नई बीमारी के बारे में जानकारी मिलते ही मगध के पांच जिलों गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत है, क्योंकि इन्हीं पांच जिलों से इस बीमारी से ग्रस्त बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं. दहशत की वजह यह है कि अज्ञात बीमारी का वायरस तो सक्रिय है ही और अब बारिश शुरू होने की वजह से जापानी इंसेफ्लाइटिस का भी खतरा मंडराने लगा है. पिछले वर्ष मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट सिंड्रोम इंसेफ्लाइटिस के कुल 124 मामले आए थे, जिनमें 25 बच्चों की मौत हो गई थी. प्रत्येक वर्ष मानसून की शुरुआत के साथ ही गया जिले के फतेहपुर, टनकुप्पा, अतरी, मोहड़ा, वजीरगंज, डुमरिया, इमामगंज, मोहनपुर, बाराचट्टी, नवादा जिले के कौवाकोल, पकरीबरावां, अकबरपुर, गोविंदपुर, रोह, सिरदला, रजौली, अरवल के कुर्था, औरंगाबाद के मदनपुर, रफीगंज, देव, कुटुम्बा आदि प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों में जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी की संभावना से दहशत रहती है. मगध प्रमंडल में पिछले नौ वर्षों में ही लगभग पांच सौ से अधिक बच्चों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है, जिनमें सिर्फ गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जापानी इंसेफ्लाइटिस तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से 310 बच्चों की मौत हो चुकी है. इस बीमारी की वजह से गया जिले में सबसे अधिक बच्चों की मौत 2012 में हुई, उस समय मगध मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी से ग्रस्त 50 बच्चों की मौत हो गई थी. स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007 से 2015 तक पूरे राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के 4811 मामले सामने आए थे जिनमें 1002 बच्चों की मौत हो गई. इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण इलाकों पर पड़ता है. विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों बीमारी के वायरस अधिकतर मच्छर, जानवर, पक्षी व धान के खेतों में पाए जाते हैं. जानकारी के अभाव और झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज की वजह से इस बीमारी से ग्रस्त बच्चों की अधिक मौते होती हैं.

गया के सिविल सर्जन डॉ. कृष्णमोहन पूर्वे और मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुधीर कुमार सिन्हा ने कहा कि यदि इन दोनों बीमारियों के लक्षण बच्चों में दिखाई दें, तो बीमार बच्चों को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती करें जिससे समय रहते बच्चों की जान बचाई जा सके. फिलहाल खबर लिखने तक कॉलेज में दो दर्जन से अधिक बच्चों का इलाज चल रहा था. केंद्र और राज्य की टीम में शामिल डॉ. निगम प्रकाश, डॉ. एसके जयसवाल, डॉ. अल्का, डब्लूएचओ के बिहार चीफ डॉ. विशेष, बिहार के राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. एनके सिन्हा के अलावा राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में ऐसे बीमार बच्चों का इलाज कर रहे चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिया है, जिससे अधिकतर बच्चों की जान इलाज से बचाई जा सके.

पिछले एक दशक से जापानी इंसेफ्लाइटिस तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम श्रेणी की बीमारियों ने राज्य के सैकड़ों बच्चों की जान ले ली है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई बीमारी के वायरस का इलाज जल्द नहीं खोजा गया, तो यह बीमारी पूरे राज्य के लिए खतरनाक साबित होगी. विशेषज्ञों ने कहा कि नई बीमारी हरपिस सिंप्लेक्स से ग्रस्त बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज का प्रयास किया जा रहा है. उनका कहना है कि लोगों को भी अपने घरों में पूरी तरह से साफ-सफाई के साथ मच्छर से बचाव के भी उपाय करने चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पताल आने वाले इस बीमारी से ग्रसित बच्चों की सबसे अधिक संख्या पिछड़े ग्रामीण इलाकों से है. इसलिए ग्रामीण इलाकों में इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है जिससे मानसून आने के पूर्व ही ग्रामीण सतर्क हो जाएं. 4 जुलाई 2016 को हरपिस सिंप्लेक्स और जापानी इंसेफ्लाइटिस एवं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस बीमारी की जांच के लिए केंद्र की टीम मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची. शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. बाबा साहेब टांगले, डॉ. अभिजीत शाह ने पिछले एक सप्ताह में जिन आठ बच्चों की मौत हो चुकी है उसकी पूरी रिपोर्ट देखी. इस टीम के विशेषज्ञों ने जिन ग्रामीण क्षेत्रों से बीमार बच्चे आए थे, उन गांवों का भी निरीक्षण किया. फिलहाल मेडिकल कॉलेज के अलावा मगध के अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों में भी दो दर्जन से अधिक संदिग्ध बीमारी से ग्रस्त बच्चों का इलाज चल रहा है जिनमें कई बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पिछले एक दशक से जापानी इंसेफ्लाइटिस तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम श्रेणी की बीमारियों ने राज्य के सैकड़ों बच्चों की जान ले ली है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई बीमारी के वायरस का इलाज जल्द नहीं खोजा गया, तो यह बीमारी पूरे राज्य के लिए खतरनाक साबित होगी. विशेषज्ञों ने कहा कि नई बीमारी हरपिस सिंप्लेक्स से ग्रस्त बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज का प्रयास किया जा रहा है.

www.iiher.org,
Mob. : 9386745004, 9204791696 Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate In Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/- only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

Made from Imported Chemicals
Lab Tested
ITALIAN
WHITE
Wall Putty
Slight Costly but Superior
For Trade Enquiry : 9431234022/9709401366.
E-mail: italianpaints@yahoo.com
Laboratory Tested – Please Compare Lab Report
Super Strength compared to ordinary Wall Putty
Super Whiteness compared to ordinary Wall Putty
Super Smoothness compared to ordinary Wall Putty
Super Covering capacity compared to ordinary Wall Putty
Increases Life of Walls & Paints compared to ordinary Wall Putty
Technical collaboration with Italian International Private Limited
Laboratory Tested – ISO 9001:2008
।। सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ ।।

Tonic of Cement
Mr.
CHEMIST
Waterproofing
Slight Costly but Superior
For Trade Enquiry :
9431234022/9709401366.
E-mail: italianpaints@yahoo.com
सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक मे अब आपके यहां भी उपलब्ध। मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, आपके घर को मजबुत बनाए

जलमार्ग से आ रही शराब

प्रशासन ने शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए गंगा, कोसी, महानंदा, कनकई समेत अन्य नदियों में मोटरबोट के सहारे गश्ती के बंदोबस्त किए जाने का दावा किया था. लेकिन गंगा नदी में फरक्का से लेकर भागलपुर तक कुछ मोटरबोट के सहारे दिन में गश्त किया जाता है, लेकिन देर शाम होते ही गश्ती दल गायब हो जाते हैं. नतीजतन रात होते शराब माफिया का खेल शुरू हो जाता है. दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी उमाशंकर सुधांशु का कहना है कि सूबे में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद गंगा में भी नावों के सहारे गश्ती की व्यवस्था की गई है. बंगाल एवं झारखंड के साथ-साथ नेपाल का सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहां शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं.

राजेश सिन्हा

बिहार में शराबबंदी के बाद अब शराब तस्कर गंगा व कोसी के अलावा अन्य नदियों के रास्ते बंगाल, झारखंड, उत्तरप्रदेश व नेपाल से शराब की खेप मंगाने लगे हैं. जलमार्ग के सहारे पहले भी तस्करी होती रही है. मुंगेर निर्मित हथियारों व मादक पदार्थों की तस्करी के लिए गंगा व कोसी की राह तस्करों के लिए हमेशा आसान रही है. लेकिन शराब तस्करों द्वारा जलमार्ग का इस्तेमाल अब शासन-प्रशासन के लिए चिंता की बात है. शाम ढलते ही गंगा, कोसी समेत अन्य नदियों के आस-पास बनाए गए पेशाघाट अर्थात धंधा के लिए बनाए गए घाट पर धंधेबाजों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है. तड़के सुबह तक शराब ढोए जाने का खेल बदस्तूर जारी रहता है. शराब से भरे कंटेनरों व छोटे वाहनों को नाव से गंतव्य तक पहुंचाने का दृश्य सरकार के सपनों को चकनाचूर करता नजर आता है. शराब तस्करों द्वारा फरक्का से भागलपुरघाट, मुंगेरघाट से लेकर मुजफ्फरपुर के विभिन्न घाटों व नेपाल से लेकर कोसी के विभिन्न घाट के बीच अस्थाई तौर पर दर्जनों घाटों का निर्माण किया गया है. पुलिस प्रशासन को भी इन घाटों से शराब की खेप मंगायी जाने की खबर है. लेकिन इलाके की भौगोलिक बनावट के कारण पुलिस का अभियान टांय-टांय फिस्स साबित हो रहा है. दिन के उजाले में शराब तस्कर किसी और धंधे में लगे रहते हैं. शाम ढलते ही धंधेबाजों की भीड़ घाटों पर जुटने लगती है. शराब की तस्करी के दौरान धंधेबाज जगह-जगह पर हथियारबंद अपराधियों को तैनात कर देते हैं. इनके खौफ से ग्रामीण धंधेबाजों की करतूतों को सार्वजनिक करने से डरते हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब तस्करों द्वारा बंगाल एवं झारखंड के साथ-साथ नेपाल के गंगा किनारे के जिलों से मोटरवाले नाव से शराब की खेप गंगा किनारे के दियारा इलाकों में ले जाया जाता है. यहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता पगडंडी ही होता है. इन इलाकों तक पहुंचने के रास्ते इतने दुर्गम हैं कि पुलिस को गंतव्य तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर पुलिस समय पर पहुंच भी जाती है तो शराब की खेप उनके हाथ नहीं लग पाती है. भनक मिलते ही शराब तस्कर नियमित नदी घाट के बजाय शराब की खेप को पेशाघाट अर्थात धंधे के लिए बने अस्थायी घाट पर छुपा देते हैं. शराब की बोतलों को कंटेनर में भरकर नदियों में इस तरह डूबो दिया जाता है कि पुलिस हाथ मलती रह जाती है. मोटरचालित नाव के निचले हिस्से में शराब छिपाने के लिए नाविकों की मदद से तस्कर विशेष इंतजाम करते हैं. तस्करों द्वारा बंगाल एवं झारखंड से लाई गई शराब की खेप सीमावर्ती जिले कटिहार के साथ-साथ पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया व मिथिलांचल तक पहुंचायी जा रही है. एक माह के दौरान मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया व अररिया से पकड़े गए शराब के धंधेबाजों ने भी पुलिस के समक्ष खुलासा किया है कि गंगा के रास्ते बंगाल, झारखंड व नेपाल से शराब की खेप बिहार मंगाई जा रही है.

इसके बावजूद शराब माफिया तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं. कभी-कभी शराब के काले धंधे से जुड़ी छोटी मछलियों को पकड़ कर ही पुलिस इतिश्री कर लेती है. जानकारों के मुताबिक गंगा तथा कोसी सहित विभिन्न नदियों के अस्थायी घाट पर शराब की खेप मंगाए जाने के बाद उसे फिर एजेंट के जरिए निर्धारित स्थल तक पहुंचाया जाता है. गंतव्य तक शराब पहुंचाने के लिए एजेंट ग्रामीण स्तर पर उपयोग में लाई जाने वाली बैलगाड़ी, साइकिल व मोपेड का ही इस्तेमाल करते हैं.

प्रशासन ने शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए गंगा, कोसी, महानंदा, कनकई समेत अन्य नदियों में मोटरबोट के सहारे गश्ती के बंदोबस्त किए जाने का दावा किया था. लेकिन गंगा नदी में फरक्का से लेकर भागलपुर तक कुछ मोटरबोट के सहारे दिन में गश्ती किया जाता है, लेकिन देर शाम होते ही गश्ती दल गायब हो जाते हैं. रात होते ही शराब माफिया का खेल शुरू हो जाता है. दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी उमाशंकर सुधांशु का कहना है कि सूबे में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद गंगा में भी नावों के सहारे गश्ती की व्यवस्था की गई है. बंगाल एवं झारखंड के साथ-साथ नेपाल का सीमावर्ती इलाका होने के कारण शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं. शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए गंगा समेत अन्य नदियों में गश्ती की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी. बहरहाल, गंगा सहित अन्य नदियों में पुलिसिया गश्ती के पुख्ता इंतजामात किए जाने से ही शराब तस्करी पर रोक लगाई जा सकती है. शराब माफिया की करतूतों को देख आम जनता यही कहने को मजबूर है कि 'शराबमुक्त बिहार' का सपना नहीं हो सका साकार.■

feedback@chauthiduniya.com

एम्बुलेंस बना शराब तस्करी का सुरक्षित जरिया

गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को भले ही अस्पताल पहुंचने के लिए समय पर एंबुलेंस न मिले, लेकिन शराब माफिया जमकर इनका इस्तेमाल शराब की तस्करी के लिए कर रहे हैं. लोग बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों की बात तो जाने दें, शहरी इलाकों में भी प्राइवेट क्लीनिक के एंबुलेंस का इस्तेमाल मरीजों की बजाय शराब ढोने में हो रहा है. बीते दिनों पूर्णिया जिले में गिरफ्तार किए गए एक वाहन चालक ने भी पुलिस के समक्ष इस बात का खुलासा किया था कि विभिन्न प्राइवेट नर्सिंग होम के एम्बुलेंस चालक शराब लाने-ले जाने के खेल में जुटे हैं. कभी शराब माफिया के प्रभाव में आकर तो कभी शराब बिक्री के एवज में मनमानी कीमत वसूलकर एंबुलेंस चालक मालामाल हो रहे हैं. बार-बार मिल रही शिकायत के बाद जब पुलिस ने मामले की पड़ताल की, तो सच सामने आया. निजी नर्सिंग होम के एम्बुलेंस चालक बेहतर चिकित्सा के लिए मरीजों को रेफर किए जाने के दौरान अस्पताल द्वारा दी गई रेफर ऑर्डर की कॉपी अपने पास रख लेते हैं. मरीजों को गंतव्य तक पहुंचाने के बाद उसी रेफर ऑर्डर कॉपी को दिखाकर कई दिनों तक आराम से शराब को गंतव्य तक पहुंचाया जाता है. इसके एवज में एम्बुलेंस चालकों को शराब के साथ-साथ बंधी-बंधाई रकम उपलब्ध करायी जाती है, साथ ही पुलिस की पकड़ में आने के बाद छुड़ाने का आश्वासन भी दिया जाता है. पुलिस प्रशासन इमरजेंसी सर्विस होने के कारण आमतौर पर एंबुलेंस की तलाशी नहीं लेते. वहीं प्राइवेट नर्सिंग होम के एम्बुलेंस चालकों को इतना कम पगार मिलता है कि वे जाने-अनजाने शराब माफिया के झांसे में आ जाते हैं. वैसे मरीज व मौत के शिकार हुए लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के नाम पर उपयोग में लाए जाने वाले एम्बुलेंस से अन्य तरह के सामानों को ढोए जाने का मामला पहली बार सामने नहीं आया है. मरीज को गंतव्य तक पहुंचाने के बाद एम्बुलेंस का इस्तेमाल यात्री वाहन के रूप में भी किया जाता है. अब एम्बुलेंस से प्रतिबंधित सामानों को इधर से उधर पहुंचाए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है. कोसी तथा सीमांचल का इलाका एम्बुलेंस के जरिए हो रही शराब तस्करी को लेकर खासा सुर्खियों में है. इधर खगड़िया के पुलिस कप्तान अनिल कुमार सिंह का कहना है कि शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ-साथ शराबियों को भी गिरफ्तार किया जाता रहा है. इस इलाके में अगर एम्बुलेंस से शराब की तस्करी हो रही है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी. किसी भी कीमत पर धंधेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा. बहरहाल, शराब तस्कर शराब के अवैध कारोबार के नए-नए तरीके ढूंढने में लगे हैं, वहीं पुलिस केवल सतर्कता के दावे करने में जुटी है. शराब तस्करों और प्रशासन के बीच चूहा-बिल्ली के खेल में पूर्ण शराबबंदी का सपना कहीं चकनाचूर न हो जाए, इस पर आम जनता की नजर टिकी है.■

- गीता कुमार

स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल से दूर होगी बीमारियाँ

ariskon Pharma Pvt.Ltd
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ. कुमुद कुमार
MD Medicine
Mil Road, Khagaria

डॉ. कुमुद कुमार जो कि अनुभवी एवं कुशल चिकित्सक हैं और खगड़िया, मिल रोड में निजि क्लिनिक चला रहे हैं से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि कि धूप हो या बारिश आनेवाली है आप पूरी बांह के सूती कपड़े पहन कर निकलें साथ ही भरपेट पानी पीकर निकलें। इन दिनों बरसात में पानी को बॉयल कर पियें या बॉयल करने के बाद उसे ठंढा कर लें और उसका इस्तेमाल करें। चूकि गर्मी में शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है और डिइहाईड्रेशन का खतरा रहता है। इन दिनों पेट की समस्या ज्यादा रहती है। इसलिए आपको चाहिए कि बाहर का जंक फूड न खायें। बाजार का खाना बीमारियों का घर है। स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल आपको गर्मी में कई बीमारियों से बचाती है। उन्होंने बताया कि इन दिनों उनके पास टायफायड और जॉन्डिस के ज्यादा मरीज आ रहे हैं। डॉ. कुमद के अनुसार जॉन्डिस एक वायरल इन्फेक्शन डिजिज है इसे हेपटाइटिस 'ए' भी कहते हैं। जॉन्डिस के लक्षणों में बुखार आना, आँख का पीला होना, उल्टी महसूस होना, भूख नहीं लगना जैसे लक्षण हैं। चूकि यह वायरल इन्फेक्शन डिजिज है इसलिए गंदा पानी और बाजार के भोजन से बचें। घर में भी भोजन साफ और शुद्धता के साथ बनना चाहिए। यदि आपको जॉन्डिस के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक से सम्पर्क करें और ऐसे मरीजों को पूरा आराम दें। इन्हें आराम की जरूरत होती है साथ ही इन्हें ग्लूकोज का सेवन कराते रहें। ■ -भारती

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

JOHNSON PAINTS
— Interior & Exterior Wall Paints —
JP
बड़े अच्छे लगते हैं...

अखिलेश यादव ने भ्रष्ट नौकरशाह को बनाया मुख्य सचिव

सपा को सिंघम नहीं सिंघल चाहिए

फोटो-प्रभात पाण्डेय

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी पर अमर सिंह का वर्चस्व फिर से कायम हो रहा है. उन्होंने अपने खास नौकरशाह दीपक सिंघल को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनवाकर यह स्थापित किया है. प्रदेश के 10 अखंड भ्रष्टों में दीपक सिंघल का नाम शुमार रहा है. भ्रष्टाचार की डीलिंग से सम्बन्धित अमर सिंह और दीपक सिंघल के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ताओं की रिकॉर्डिंग सुर्खियों में रही हैं. उस बातचीत के तीन टेप उपलब्ध हैं. ये टेप यू-ट्यूब पर भी अपलोडेड हैं. इसमें एक में दीपक सिंघल और अमर सिंह के बीच किसी शुगर डील के साथ-साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) के टेंडर डॉक्युमेंट और उसकी पॉलिसी और भूमि आवंटन में मनमाफिक बदलाव की खुली चर्चा हो रही है. दूसरे टेप में गैस की डील, आईएएस संजीव शरण के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हिस्सेदारी और किसी शासकीय मामले में मुख्य सचिव पर बाहरी दबाव डलवाने जैसी बातें हो रही हैं. तीसरे टेप में अमर सिंह दीपक सिंघल को आरडीए वाले देवेंद्र कुमार को 96.5 लाख रुपये पहुंचाने का निर्देश देते साफ-साफ सुने जा सकते हैं. मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद आम तौर पर लोग कहते मिलेंगे, सपा सरकार को सिंघम नहीं, सिंघल चाहिए.

उसी स्वनामधन्य नौकरशाह दीपक सिंघल को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. अब आप याद करें, कौमी एकता दल के सपा में विलय को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के फैसलों के खिलाफ कितना माहौल बनाया था. अखिलेश ने माफिया मुख्तार अंसारी की पार्टी के सपा में विलय के विरोध का वितंडा खड़ा कर अपनी साफ छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की. लेकिन यही साफ छवि का विचार भ्रष्ट नौकरशाह को मुख्य सचिव नियुक्त करते वक्त कहां विलुप्त हो गया था? सपा के सामान्य कार्यकर्ताओं के मन में मुलायम सिंह यादव के प्रति भी ऐसे ही सवाल गूंजते हैं. भ्रष्ट आचरण करने वाले नेताओं पर बरसने वाले मुलायम भ्रष्ट नौकरशाह को मुख्य सचिव बनाते वक्त क्यों नहीं बरसते, ऐसे मौकों पर क्यों चुप्पी साध जाते हैं? इन सवालों के जवाब लोग जानते हैं. अखिलेश यादव का छवा और समाजवादी पार्टी की प्राथमिकताएं क्या हैं, जनता के सामने यह पूरी तरह उजागर हो चुकी हैं.

उत्तर प्रदेश के 18 वरिष्ठ आईएएस अफसरों की वरिष्ठता को लांघ (सुपरसीड) कर दीपक सिंघल को उत्तर प्रदेश का 48वां मुख्य सचिव बनाया गया है. इसके पहले आलोक रंजन मुख्य सचिव थे. आलोक रंजन को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया गया. एक्सटेंशन की अवधि बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे. उनका वश चलता तो आलोक रंजन को फिर से एक्सटेंशन दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें अपना सलाहकार बना कर उन्हें लाल बत्ती दे दी और मंत्री का दर्जा दे दिया. इधर, दीपक सिंघल की भी विशेषता और विशेषज्ञता है कि वे अखिलेश, मुलायम, शिवपाल, अमर सबके प्रिय हैं. मुख्य सचिव बनने के पहले दीपक सिंघल शिवपाल के अधीन सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव थे. प्रदेश के 10 सबसे भ्रष्ट अफसरों में सिंघल का नाम शुमार रहा है. 10 महाभ्रष्टों में से तीन नौकरशाह अखंड प्रताप सिंह, नीरा यादव और दीपक सिंघल समाजवादी पार्टी के खास पसंद साबित हुए, जिन्हें सपा के विभिन्न कार्यकाल में प्रदेश का मुख्य सचिव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.■

feedback@chauthiduniya.com

सिंघल की सुपरस्पीड 18 अफसर सुपरसीड

1982 बैच के आईएएस दीपक सिंघल को सुपरस्पीड तरक्की मिली. उन्होंने अपने से सीनियर 18 आईएएस अफसरों को सुपरसीड कर मुख्य सचिव की कुर्सी हासिल कर ली. सिंघल से सीनियर अफसरों में 1979 बैच के आईएएस अफसर राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार गुप्ता, 1980 बैच के आईएएस शैलेश कृष्ण, 1981 बैच के आईएएस कुंवर फतेह बहादुर और 1982 बैच के आईएएस कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) प्रवीर कुमार शामिल हैं. दीपक सिंघल से सीनियर अन्य 14 आईएएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. ■

दीपक सिंघल

कभी हुआं-हुआं करने वाले आज क्यों हैं धुआं-धुआं?

भ्रष्टाचार के मामलों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह, नीरा यादव और मौजूदा मुख्य सचिव दीपक सिंघल के साथ-साथ भारत की मुख्य धारा के कई और आईएएस भ्रष्ट आचरणों में बराबर के शरीक हैं. इनमें एनआरएचएम घोटाले के प्रमुख अभियुक्त प्रदीप शुक्ला जैसे वरिष्ठ नौकरशाह भी हैं, जो अभी हाल तक जेल में थे, समाजवादी सरकार की कृपा मिलने पर जेल से छूट कर आए हैं और आते ही तैनाती पाए हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश के पसंदीदा नौकरशाह रहे राजीव कुमार भी उसी भ्रष्ट-धारा के हैं. सीबीआई अदालत उन्हें तीन साल की सजा भी सुना चुकी है.

अखंड प्रताप सिंह, नीरा यादव और ब्रजेंद्र यादव को लेकर सारे नौकरशाहों ने इतना शोर-गुल मचाया था कि जैसे वे तीन ही बेईमान थे और बाकी अफसर दूध के धुले हुए थे. असलियत यह थी कि सारे भ्रष्ट मिल कर तीन पर उंगली उठा रहे थे, जैसे सारे गीदड़ मिल कर हुआं-हुआं करते हैं. बाद के परिदृश्य में जब प्रदीप शुक्ला, राजीव कुमार जैसे अन्य भ्रष्ट नौकरशाहों की कलई खुलने लगी तो हुआं-हुआं करने वाले नौकरशाह चुप्पी साध गए. यह पूरी तरह से जाहिर हुआ कि नौकरशाहों की हुआं-हुआं भ्रष्टाचार को लेकर नहीं बल्कि कुछ खास अफसरों को दुनिया की नजरों से गिराने के षडयंत्र को लेकर हो रही थी.

तब आईएएस एसोसिएशन भी भ्रष्ट आईएएस चुनने और तीन अफसरों को बदनाम करने के षडयंत्र में लगा था. आज महाभ्रष्टों की कतार लगी हुई है, लेकिन आईएएस एसोसिएशन के मुंह पर पट्टर बंधा हुआ है. भ्रष्टाचार में नेताओं और नौकरशाहों की साठगांठ पक्की हो चुकी है और भ्रष्टाचार को मान्यता मिल चुकी है. तभी तो दीपक सिंघल जैसे लोग मुख्य सचिव बनाए जा रहे हैं! यादव सिंह जैसे महाभ्रष्टों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का संरक्षण बुरी तरह उजागर हो चुका है. यादव सिंह को सीबीआई के चंगुल से बचाने के लिए अखिलेश ने क्या-क्या जतन नहीं किए. इस पर सुप्रीम कोर्ट तक को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी. कोर्ट ने कहा, एक अधिकारी को बचाने के लिए राज्य सरकार इतनी उतावली और चिन्तित क्यों है? यहां तक कि यादव सिंह के ही चक्कर में पार्टी को बिहार के महागठबंधन से भी अलग होने का फैसला करना पड़ा, जिसका खामियाजा पार्टी भुगत रही है. आईएएस संजीव सरन और राकेश बहादुर के महा-भ्रष्टाचार पर भी हाईकोर्ट नकारात्मक टिप्पणी दे चुकी है. अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही दोनों को क्रमशः नोएडा का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बना दिया था. मुख्यमंत्री सचिवालय के खास अधिकारी रहे आईएएस पंधारी यादव का नाम भ्रष्टों के चर्चा में न लें तो यह भ्रष्टाचार के साथ ही नाइंसाफी होगी. सोनभद्र का जिलाधिकारी रहते हुए पंधारी ने पूरा जिला खा लिया, उसके बाद वे जिस विभाग में जाते हैं, उसे ही भोज्य बनाने लगते हैं. उनके भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच हो रही है. लेकिन जांच भी सपाई रफ्तार में ही चल रही है. पंधारी यादव मनरेगा घोटाला मामले में प्रमुख आरोपी हैं. पंधारी पर मनरेगा के मद से जिलाधिकारी रहते हुए 98 करोड़ का नाश्ता करने जैसे कई आरोप हैं.

भ्रष्ट-प्रेमी समाजवादी सरकार में जो अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं, उन्हें ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. वरिष्ठ आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर अखिलेश सरकार की प्रताड़ना से इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने यूपी कैडर बदल कर दूसरे किसी राज्य में जाने के लिए आवेदन भी डाल रखा है. जितने ईमानदार और कर्मठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, वे सब केंद्र में अपनी प्रतिनियुक्ति करा कर बाहर चले गए या शंटिंग में हैं. सरकार की प्रताड़नाओं के कारण ईमानदार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह भी सुर्खियों में रहे हैं.■

फिर गरमाया अमर-सिंघल टेलीफोन टेपकांड

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने चीनी मिल घोटाले में सिंघल के खिलाफ जांच कराई थी. बरेली में तैनाती के दौरान दीपक सिंघल चीनी मिल घोटाले में फंसे थे. कल्याण सिंह के कार्यकाल में जांच शुरू हुई और सरकार बदली तो जांच खत्म हो गई. बसपा सरकार आई तो जांच दोबारा शुरू हुई लेकिन सिंघल की विशेषज्ञता के आगे वह जांच भी ढेर हो गई. फिर अमर सिंह से पैसे के लेन देन के तीन टेप लीक हुए और दीपक सिंघल फिर सुर्खियों में आ गए. सिंघल और अमर सिंह की बातचीत के पहले टेप(https://www.youtube.com/watch?v=IehyzO-vTIg) में किसी शुगर डील, एसईजेड के टेंडर डॉक्युमेंट और उसकी पॉलिसी और लैंड अलॉटमेंट में मनमर्जी बदलाव की चर्चा है. दूसरे टेप(https://www.youtube.com/watch?v=8y34DMYfBxk) में किसी गैस वाली डील, आईएएस संजीव शरण के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हिस्सेदारी और किसी शासकीय मामले में मुख्य सचिव पर बाहरी दबाव डलवाने की बातचीत है. तीसरे टेप में अमर सिंह सीधे तौर पर सिंघल को आरडीए वाले देवेंद्र कुमार को 96.5 लाख रुपये पहुंचाने का निर्देश देते सुने जा सकते हैं. दीपक सिंघल पर अपने रिश्तेदार की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देने का भी आरोप रहा है. सिंघल जब ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव थे, तब अपने रिश्तेदार की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बहाल कर काम देना शुरू कर दिया था. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर अमर सिंह-दीपक सिंघल टेप प्रकरण की जांच की मांग अर्से से करती रही हैं. यहां तक कि इस मामले में नियुक्ति विभाग के उप सचिव अनिल कुमार सिंह ने नूतन ठाकुर से 13 नवम्बर 2014 को ही शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था. 26 फरवरी को शपथपत्र दाखिल भी कर दिया गया था, लेकिन जांच का कुछ नहीं हुआ और सिंघल को तरक्की मिलती चली गई और आखिरकार वे प्रदेश के मुख्य सचिव भी बना दिए गए.

डॉ. नूतन ठाकुर ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा था कि दीपक सिंघल सरकार की गोपनीय बातें एक निजी व्यक्ति (अमर सिंह) को बता रहे हैं, यह बहुत ही गंभीर मामला है. सिंघल एक निजी व्यक्ति से सरकारी कामकाज के लिए आदेश प्राप्त कर रहे हैं और लगातार सरकार की गोपनीयता भंग कर रहे हैं. लेकिन जांच की मांग अब तक लंबित पड़ी है. नूतन का कहना है कि दर्जनभर से अधिक वरिष्ठ अफसरों को सुपरसीड कर दीपक सिंघल की मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति भ्रष्टाचार के प्रति समाजवादी सरकार के उदासीन रवैये के साथ-साथ अखिलेश सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को भी उजागर करती है. ■

सपा नेताओं की बेजा हरकतों पर फिर गुर्राए मुलायम

सिर्फ़ बोलते हैं करते कुछ नहीं

दीनबंधु कबीर

मुलायम सिंह यादव केवल बोल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर अपनी पार्टी के नेताओं के गैरकानूनी कृत्यों पर प्रहार किया और सामान्य कार्यकर्ताओं की तालियां बटोरीं. मुलायम के आक्रामक तेवर और बेबाक वक्तव्य पर सपाई थोड़ी देर के लिए उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके दिमाग में यह सवाल गूंजने लगता है कि नेताजी इतना बोलते हैं तो कुछ करते क्यों नहीं! कुछ सपाई तो मुखर होकर बोल भी उठते हैं. एक कार्यकर्ता ने कहा कि अगर अखिलेश यादव के नेतृत्व की प्रदेश सरकार और प्रदेश इकाई इतनी ही बेहाथ हो गई है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नेताजी भ्रष्ट और अनुशासनहीन नेताओं के खिलाफ सीधी कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई करते भी हैं, तो पुत्र-मोह में उसे फिर वापस क्यों ले लेते हैं? अब सपा के आम कार्यकर्ताओं से लेकर आम नागरिक तक इसे मुलायम का सियासी प्रहसन ही बताते हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर पिछले दिनों लखनऊ में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के नेताओं को खूब खरी-खोटी सुनाई. मुलायम ने कहा कि सपा के कुछ नेता जमीन कब्जा करने में, पैसा कमाने में और लूट-खसोट में लगे हुए हैं. उनके इस आचरण से पार्टी को नुकसान हो रहा है. मुलायम ने कहा कि ऐसे नेताओं को अपना आचरण बदलना चाहिए. मुलायम ने कहा कि अगर 2017 के चुनाव के बाद सरकार बनानी है तो कुछ नेताओं को अपना आचरण बदलना ही होगा. मुलायम बोले कि मेरे पास सबकी रिपोर्ट मौजूद है. मुलायम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग दबंगई करने और पैसा कमाने में लगे हैं. अगर यह आचरण नहीं सुधरा तो आगामी चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे. मुलायम ने कहा कि सपा नेता पैसे और जमीन के चक्कर में पड़े हैं. इससे पार्टी की बदनामी हो रही है. मुलायम ने कुछ ऐसा प्रदर्शित किया कि 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर वे काफी सतर्क हैं और पार्टी से जुड़े लोगों की गुंडागर्दी और अवैध गतिविधियों पर उनकी पूरी नजर है और वह नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर पार्टी की छवि खराब हो. मुलायम का यही टोन सपा मुख्यालय में जिला पंचायत अध्यक्षों और सपा के 64 विधान परिषद सदस्यों की बैठक में भी था. बैठक में सपा के प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल थे. मुलायम ने लापरवाही, दबंगई और गुंडई कर रहे नेताओं को लताड़ लगाई और अखिलेश के काम की तारीफ की.

सपा सुप्रीमो ने बैठक में मौजूद सपाइयों से कहा कि चुनाव के पहले सुधर जाओ वर्ना सरकार नहीं बनेगी. कुछ लोग जमीनों पर कब्जे, पैसे के लिए लूट-खसोट और दबंगई में लगे हैं. हमें सब मालूम है कि कौन क्या कर रहा है. इशारों ही इशारों में मैं अपनी बात बोल देता हूं, कुछ नेता मान लेते हैं और सुधर भी जाते हैं. यदि नहीं सुधरे तो जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी. मेरे पास कुछ पार्टी नेताओं के जमीन कब्जा करने, भ्रष्टाचार और अवैध ढंग से धन कमाने की पूरी सूचना है. अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखा देगी. जनता ही राजा बनाती है और वही सड़क पर भी ले जाती है. उनके पास पूरी सूचना है और वह ऐसे नेताओं के हावभाव भी समझते हैं.

मुलायम के इस तेवर की हवा निकालते हुए मझोले दर्जे के एक सपा नेता ने कहा कि मुलायम के ऐसे बयान कोरे राजनीतिक स्टंट हैं. नेताजी बार-बार कहते हैं कि सपाइयों के अवैध धंधे की उन्हें पूरी जानकारी है, पूरी रिपोर्ट है, तो वे कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों भ्रष्टाचार और गुंडई को वे पांच साल तक बर्दाश्त करते रहे और केवल बोलते रहे? सपा नेता ने कहा कि मुलायम लगातार बयान दे रहे हैं लेकिन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति जैसे भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने में भी लगे रहते हैं. पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ही मुलायम ने कहा कि पार्टी में चापलूसों की संख्या बढ़ गई है. लेकिन सपा में चापलूस क्यों पनप रहे हैं, इस बारे में नेताजी ने कुछ नहीं कहा. 26 फरवरी को मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिदायत दी थी कि वे कार्यक्रमों में अधिक जा रहे हैं, लेकिन जनता का कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं. मुलायम ने तब भी कहा था कि विधायक और मंत्री पैसा बनाना बंद करें, अगर उन्हें पैसा कमाना है तो अपना बिजनेस शुरू कर लें. लेकिन मुलायम भी बोल कर औपचारिकता निभा लेते हैं और नेता सुन कर अपने धंधे में लग जाते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

मचेगा सियासी घमासान, राज बब्बर को यूपी की कमान

मशहूर फिल्म अभिनेता और सांसद राज बब्बर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना कर कांग्रेस आलाकमान ने यह प्रदर्शित किया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी गंभीर है. अभी कई और पत्ते खुलने बाकी हैं. मसलन, विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की भूमिका क्या होगी और शीला दीक्षित किस रोल में उतरेंगी, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है. कांग्रेस के एक बुजुर्ग नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कठिन दौर से गुजर रही है, ऐसे में राज बब्बर जैसे जुझारू व्यक्ति के हाथों में कमान देकर पार्टी ने सकारात्मक कार्य किया है. उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद को जैसे ही उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया था, उसी दिन लग गया था कि पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर काफी गंभीर है.

राज बब्बर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही अभी तक अध्यक्ष रहे निर्मल खत्री को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. सहारनपुर के कांग्रेस नेता इमरान मसूद के साथ राजाराम पाल, राजेश मिश्रा, भगवती प्रसाद चौधरी को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है. राज बब्बर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं. उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने का तात्पर्य यह भी है कि चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अब किसी तालमेल की संभावना नहीं है. वैसे, राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, कहना मुश्किल होता है.

राज बब्बर ने अस्सी के दशक में वीपी सिंह के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी लेकिन बाद में वे मुलायम सिंह के साथ हो लिए और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए. 1994 में मुलायम ने उन्हें राज्यसभा भेजा. राज बब्बर ने 2004 में लोकसभा का चुनाव सपा प्रत्याशी के रूप में लड़ा और जीते. अमर सिंह से सीधे टकराव के कारण पार्टी में उनकी स्थिति असहज होती चली गई. 2006 में सपा ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा कर पार्टी से निष्कासित कर दिया. 2008 में राज बब्बर कांग्रेस में शामिल हो गए. 2009 में राज बब्बर ने कांग्रेस के टिकट पर फिरोजाबाद से मुलायम सिंह की बहु डिंपल यादव के खिलाफ लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे. इस हार को मुलायम और अखिलेश दोनों ने अपने सम्मान से जोड़ लिया और राज बब्बर को हमेशा के लिए किरकिरी मानने लगे. 2014 के लोकसभा चुनाव में बब्बर भाजपा प्रत्याशी जनरल वीके सिंह से हार गए. बाद में पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड से राज्यसभा में भेज दिया. राज बब्बर की छवि जनता के साथ खड़े होने वाले जुझारू नेता की है. युवाओं में अब भी उनका अच्छा-खासा प्रभाव है.

राज बब्बर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने 12 जुलाई को दिल्ली में की. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे. आजाद ने कहा कि राज बब्बर मूल रूप से यूपी के ही रहने वाले हैं. वे तीन बार यूपी से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य रहे हैं और इस बार वह उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं. प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए प्रमोद तिवारी से लेकर जितिन प्रसाद और कई अन्य नेताओं की पुरजोर चर्चा के बीच राज बब्बर को आगे कर कांग्रेस ने कारगर चाल चल दी है. ■

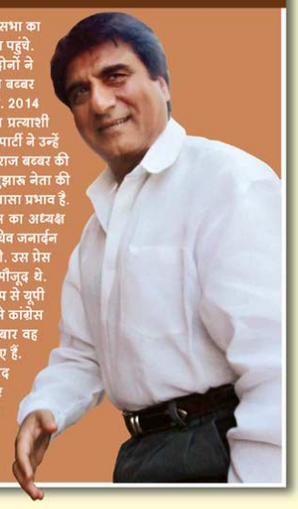

यूपी भाजपा का 'भ्रमोत्पाद'

उत्तर प्रदेश में भाजपा ने भी अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी. इसमें बड़े नेताओं के पुत्रों और पैरवी-पुत्रों का पूरा ध्यान रखा गया है. मुजफ्फरनगर साम्प्रदायिक हिंसा मामले में सपा सरकार द्वारा अभियुक्त बनाए गए बहुचर्चित विधायक सुरेश राणा को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. नीतिगत तौर पर भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी उलझी हुई और अस्पष्ट है. वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह और लालजी टंडन के पुत्र गोपाल टंडन को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के पैरवी-पुत्र विजय बहादुर पाठक को प्रदेश महामंत्री चुना गया है. विलंबित ताल में कार्यकारिणी का गठन करने के बावजूद भाजपा नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी के लिए प्रभावशाली, प्रतिबद्ध और ऊर्जावान नेता नहीं मिले. 40 सदस्यीय टीम में कुछ को छोड़कर बाकी चेहरे सिफारिशी या पके हुए प्रभावहीन चेहरे हैं. उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष केशव मौर्य के हस्ताक्षर से जारी प्रदेश पदाधिकारियों में 15 प्रदेश उपाध्यक्ष, 15 प्रदेश मंत्री, आठ प्रदेश महामंत्री, एक प्रदेश कोषाध्यक्ष और एक सह कोषाध्यक्ष हैं. प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करने में नेतृत्व को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन फिर भी नतीजा सार्थक नहीं निकला. प्रदेश अध्यक्ष के चयन में भी काफी देरी हुई थी. भाजपा नेतृत्व का उहापोह लगातार जनता के सामने अभिव्यक्त होता रहा है. किस चेहरे को सामने लेकर चुनाव लड़ा जाए, इसे लेकर भी भाजपा नेताओं में भीषण भ्रम की स्थिति बनी हुई है. जातीय संतुलन बनाने और 40 सदस्यीय कार्यकारिणी में सवर्णों, 14 ओबीसी और चार दलितों को स्थान देने की जद्दोजहद में पार्टी की मूल प्राथमिकता खो गई. ■

क्या हाथी नहीं रहेगा साथी

बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती सियासत के बुरे दौर से गुजर रही हैं. एक तरफ बड़े-बड़े नेता उनकी पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी भी पार्टी से छूटने के खतरे में है. मायावती ने अपने शासनकाल में हाथी की इतनी ढेर सारी मूर्तियां सार्वजनिक स्थलों पर लगवा दीं कि अब वही पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में विभिन्न स्मारकों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित हाथी की प्रतिमाएं चुनाव प्रचार की तरह इस्तेमाल में आएंगी, इसका अंदेशा काफी अर्सा पहले से जताया जाता रहा है. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में अभी एक जनहित याचिका भी दाखिल हुई है. इस याचिका में यह मांग की गई है कि बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी रद्द कर उसे कोई दूसरा चुनाव चिन्ह देने के लिए चुनाव आयोग को निर्देशित किया जाए. हाईकोर्ट ने इस मामले को चुनाव आयोग को भेजते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को कुछ ऐसे गाइड-लाइंस बनाने चाहिए जिससे राजनीतिक पार्टियां सार्वजनिक स्थलों और जनता के धन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न कर सकें. जो पार्टियां ऐसा करें, उनकी मान्यता रद्द करने का विकल्प रहना चाहिए. उल्लेखनीय है कि चुनाव के समय आयोग के निर्देश पर मूर्तियों को पर्दे से ढंकने का मामला सुर्खियों में रह चुका है.

उधर, बड़े नेताओं के छोड़ कर जाने के बाद बसपा डांवाडोल की स्थिति में है. मायावती कहती हैं कि उनके जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ रहा. लेकिन पार्टी छोड़ कर जाने का क्रम जारी है, यानी पार्टी पर नकारात्मक असर का क्रम जारी है. स्वामी प्रसाद मौर्य, आरके चौधरी, राजेश त्रिपाठी, परमदेव यादव के साथ नेताओं के छोड़ने का सिलसिला जारी है. पिछले साल जब मायावती ने बसपा नेता दद्दू प्रसाद को पार्टी से निष्कासित किया तभी से पार्टी में चला-चली तेज हो गई थी. हालांकि उसके पहले दारा सिंह चौहान, डॉ. अखिलेश दास गुप्ता, कबीर राणा, शाहिद अखलाक, रमाशंकर विद्यार्थी जैसे कई नेता पार्टी से छूटे या छुड़ाए गए. फिर मायावती के भतीजे राज्यसभा सदस्य जुगल किशोर और कुंअर फतेह बहादुर सिंह जैसों ने भी पार्टी छोड़ दी. 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उसका ग्राफ अचानक नीचे गिर पड़ा. मौर्य और पासी जाति के वोट का बसपा को सीधा नुकसान पहुंचा. अन्य जो भी नेता पार्टी छोड़ कर गए, उनका हरजाना तो पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा. दिग्गज राजनीतिक समीक्षकों का भी यही मानना है. ■

> मुलायम के इस तेवर की हवा निकालते हुए मझोले दर्जे के एक सपा नेता ने कहा कि मुलायम के ऐसे बयान कोरे राजनीतिक स्टंट हैं. नेताजी बार-बार कहते हैं कि सपाइयों के अवैध धंधे की उन्हें पूरी जानकारी है, पूरी रिपोर्ट है, तो वे कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों भ्रष्टाचार और गुंडई को वे पांच साल तक बर्दाश्त करते रहे और केवल बोलते रहे?

साहित्य के चुनावी हथकंडे

अनंत विजय

साम्प्रदायिकता- ये एक ऐसा विषय है जो हमारे पढ़े लिखे समाज के एक वर्ग को हमेशा से डराता रहता है. हमारे इस बौद्धिक वर्ग को साम्प्रदायिकता के खिलाफ बार-बार खड़ा भी होना पड़ता है. होना भी चाहिए. हमारे समाज का ये कथित बौद्धिक वर्ग साम्प्रदायिकता को लेकर तब और भी उद्वेलित होने लगता है जब राज्यों या केंद्र में मनमाफिक सरकारें न हों. एक विचारधारा विशेष के आवरण में लिपटे ये लोग साम्प्रदायिकता तो कई बार असहिष्णुता तो कभी अभिव्यक्ति की आजादी पर आसन्न खतरे को लेकर व्याकुल नजर आते हैं. इनकी ये व्याकुलता नाटकों, लेखों से लेकर पुरस्कार वापसी तक में नजर आती है. सांप्रदायिकता के इन चैंपियनों को यह विषय तब और परेशान करने लगता है जब देश के किसी हिस्से में चुनाव आदि की आहट सुनाई देने लगती है. ताजा मामला सामने आ रहा है कर्नाटक से जहां से खबर आ रही है कि थिएटर एक्टिविस्ट प्रसन्ना ने महात्मा गांधी की 1909 में लिखी किताब 'हिंद स्वराज' के आधार पर एक नाटक तैयार किया है जिसका मंचन पूरे कर्नाटक में किया जाएगा. योजना के मुताबिक अलग-अलग गांवों के अलावा इसका मंचन स्कूल और कॉलेजों में भी किया जाएगा. इस नाटक का उद्देश्य सांप्रदायिकता के खतरों से लोगों को आगाह करना है. हिंद स्वराज गांधी की ऐतिहासिक किताब है जिस पर पहले ब्रिटिश शासकों ने प्रतिबंध लगा दिया था. मूल रूप से गुजराती में लिखी गई इस किताब का बाद में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और फिर कई अन्य भाषाओं में अनुदित होकर छपा और लोगों को गांधी के इस विचार को जानने समझने का मौका मिला.

इस किताब के आधार पर तैयार किए गए नाटक को प्रसन्ना ने संपादित कर आधुनिक रूप देने की कोशिश की है. प्रसन्ना ने तो ये भी दावा किया है कि कुछ अंशों को जस का तस रखा गया है जैसा बापू ने लिखा था. इस नाटक में गांधी एक जगह कहते हैं कि गाय को बचाने के लिए क्या मुझे किसी मुसलमान से लड़ना चाहिए या उसकी हत्या कर देनी चाहिए? अगर हमने ऐसा किया तो हम मुसलमानों के दुश्मन बन जाएंगे और गाय के भी. गाय संरक्षण का एकमात्र तरीका जो मैं जानता हूं, वह यह है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूं. अगर वो मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मुझे गाय को छोड़ देना चाहिए, यह मानकर कि ये मामला मेरे वश का नहीं है. अब यहीं से चुनिंदा जानकारी देने का खेल शुरू होता है. मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने विचारों को लगातार परिमार्जित करते रहते थे. सत्य और अहिंसा दो ही ऐसी अवधारणा दिखाई देती है जिसका परिमार्जन बापू के लेखन में नहीं दिखाई देता है अन्यथा वो अपने विचारों को लगातार अपडेट करते रहे हैं. मैं जो कह रहा हूं वो अपने अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं. बापू ने विपुल लेखन किया है और उसको पूरा पढ़ने का दावा कम ही लोग कर सकते हैं.

गोरक्षा पर बापू के विचार 1909 में जो थे उससे किसी को इंकार नहीं है. किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की हिंसा अक्षम्य है और हिंसा करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए. लेकिन बापू ने छह अक्टूबर 1921 में यंग इंडिया में गोरक्षा पर क्या लिखा ये देखने की जरूरत है. हिंदू धर्म की मुख्य वस्तु है गोरक्षा. गोरक्षा मुझे मनुष्य के सारे विकासक्रम में सबसे अलौकिक वस्तु मालूम हुई है. ...हिन्दुस्तान में गाय ही मनुष्य का सबसे सच्चा साथी, सबसे बड़ा आधार था. यही हिन्दुस्तान की कामधेनु थी. वह सिर्फ दूध ही नहीं देती थी, बल्कि सारी खेती का आधार स्तंभ थी. गाय दया धर्म की मूर्तिमंत कविता है. इस गरीब और शरीफ जानवर में हम केवल दया ही उमड़ती देखते हैं. यह लाखों करोड़ों हिन्दुस्तानियों को पालने वाली माता है. इस गाय की रक्षा करना ईश्वर की सारी मूक सृष्टि की रक्षा करना है. जिस अज्ञात ऋषि या द्रष्टा ने गोपूजा चलाई उसने गाय से शुरुआत की. इसके सिवा कोई और ध्येय हो ही नहीं सकता है. गोरक्षा हिंदू धर्म की दुनिया को दी हुई एक कीमती भेंट है. और हिंदू धर्म भी तभी तक रहेगा, जबतक गाय की रक्षा करने वाले हिंदू हैं. आखिरी पंक्ति पर ध्यान देने की जरूरत है. ईमानदारी तो यही होती कि गोरक्षा पर गांधी के विचारों को समग्रता में जनता के सामने रखा जाता. गांधी ने इसके बाद भी समय-समय पर काल और परिस्थिति के हिसाब से गोरक्षा पर अपने विचार रखे हैं जो यंग इंडिया के सात जुलाई 1927 और हरिजन सेवक के 21 सितंबर 1940 के अंक में प्रकाशित हैं. सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि हम चुनिंदा तरीके से किसी बात को पेश करके हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या ये बौद्धिक बेइमानी नहीं है? या फिर किसी खास मकसद से नहीं किया जा रहा है?

कर्नाटक से खबर आ रही है कि थिएटर एक्टिविस्ट प्रसन्ना ने महात्मा गांधी की 1909 में लिखी किताब 'हिंद स्वराज' के आधार पर एक नाटक तैयार किया है जिसका मंचन पूरे कर्नाटक में किया जाएगा. योजना के मुताबिक अलग-अलग गांवों के अलावा इसका मंचन स्कूल और कॉलेजों में भी किया जाएगा. इस नाटक का उद्देश्य सांप्रदायिकता के खतरों से लोगों को आगाह करना है.

कर्नाटक में 2018 में विधानसभा चुनाव हैं. इस वक्त वहां कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी ने येदियुरप्पा को वहां की कमान सौंप कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं. कर्नाटक में कांग्रेसी मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर उनकी खुद की ही पार्टी के लोग उनको कठघरे में खड़े कर चुके हैं. देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस अभी आंतरिक संघर्षों से ही जूझ रही है. ऐसे माहौल में हिंद स्वाराज का गांव-गांव में जाकर मंचन और साम्प्रदायिकता के खिलाफ लोगों के जागरण के मंसूबों का एलान राजनीति के आंगन का नाच दिखाई देता है. इन नाटकों का मंचन कन्नड़ और अंग्रेजी में होगा और एक कैंपेन की तरह से किया जाएगा ताकि कर्नाटक में साम्प्रदायिकता के खिलाफ लोग जागृत हो सकें. इस कैंपेन से जुड़े लोग जिस तरह की बोली बोल रहे हैं वो भी उनकी प्रतिबद्धता को साफ करते हैं. हिटलर, नाजी शासन आदि शब्दावली का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है. एक बार फिर से सवाल वही कि चुनाव के वक्त क्यों? क्या कर्नाटक में सांप्रदायिकता इस वक्त का मुद्दा है? क्या उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है? जहां दोनों पक्ष के लोग इस मसले को हवा देकर सियासी फसल काटने की कोशिश में जुटे हैं. यहां की सरकार को लेकर हमारे बौद्धिकों का एक वर्ग कमोबेश खामोश रहता है.

पाठकों को याद होगा कि बिहार चुनाव के वक्त किस तरह से पुरस्कार वापसी को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की गई थी. छोटे-मोटे धरने आदि भी असहिष्णुता के खिलाफ दिए गए थे. मुंह पर काली पट्टी बांधे चंद लेखकों का साहित्य अकादमी के बाहर जमावड़ा भी हुआ था लेकिन चुनाव में बीजेपी की पराजय के बाद सब शांत हो गया. क्या देश की स्थिति अगर खराब थी तो, ठीक हो गई? क्या असहिष्णुता समाप्त हो गई? क्या साम्प्रदायिकता की जगह साम्प्रदायिक सौहार्द ने ले ली? नहीं. स्थिति कमोबेश वैसी ही है. मीडिया में इस तरह की भी खबरें हैं कि पुरस्कार वापसी के कुछ अगुवा बिहार सरकार से पद आदि की ख्वाहिश भी जता चुके हैं. खैर ये अवांतर प्रसंग होगा जिस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी. पानसरे, दाभोलकर और कालबुर्गी हत्याकांड की जांच की प्रगति को देखें तो यह साफ हो जाएगा कि कौन सी सरकार कितना आगे बढ़ा पाई है.

दरअसल साहित्य, कला और संस्कृति को भी हमारे विचारधारा से सराबोर लेखकों ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है. इसके लिए बहुत हद तक लेखक संगठन जिम्मेदार हैं जो विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टियों के बौद्धिक प्रकोष्ठ की तरह काम करते रहे. नतीजा यह हुआ कि इन संगठन से जुड़े लेखक उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बनकर रह गए. मुझे याद है कि अस्सी के दशक में साहित्यिक कार्यक्रमों में इस बात का उल्लेख किया जाता था कि अमुक लेखक सीपीआई का होल टाइमर या कार्ड होल्डर रहा है. और ये बात साहित्यिक मंच पर बेहद गर्व से बताई जाती थी और हम उसे नए लोगों से ये अपेक्षा की जाती थी कि उन होल टाइमर को बड़ा लेखक मानें. साहित्य को समाज के आगे चलने वाली मशाल से राजनीति का पिछलग्गू बना देने की जिम्मेदारी इन लेखक संगठनों और इनके कर्ता-धर्ताओं पर है. अब जब ये लेखक संगठन कमजोर हो गए हैं तो अलग-अलग तरीके से व्यक्तिगत प्रयासों से राजनीति की जा रही है. कर्नाटक में ग्प्रदायिकता के खिलाफ माहौल बनाना एक अच्छी पहल है. इसका स्वागत होना चाहिए लेकिन जिस तरीके से गांधी के गोरक्षा पर विचारों को समग्रता में पेश नहीं किया जा रहा है वो खतरनाक और चिंता की बात है. और यही बात उनकी मंशा को भी संदेहास्पद बनाती है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.tbn@gmail.com

आम

पिछले अंक से आगे

❖ **विसूचिका-** 20 ग्राम आम के पत्तों को कूट कर आधा लीटर जल में पकाकर क्वाथ बनाएं, चतुर्थांश शेष रहने पर, छानकर पिलाने से लाभ होता है.

❖ आम का शर्बत या आम का पना बार-बार पिलाने से विसूचिका में लाभ होता है.

❖ **परिणाम शूल (अल्सर)-** प्रातः 8 बजे और सायंकाल 4 बजे 2-3 मीठे पके आमों को खाने के बाद 250 मिली दूध पी लें, पानी बिल्कुल न पीएं. एक घंटे बाद उबालकर ठंडा किया हुआ पानी, जरूरत हो तो पी लें. दोपहर के भोजन में आम के रस के साथ गेहूं की रोटी का सेवन करें. इस अवधि में अन्य कोई भोज्य पदार्थ न लें. एक सप्ताह में आशातीत लाभ होता है.

❖ आम के ताजे कोमल पत्ते 10 नग और काली मिर्च 2-3 नग दोनों को जल में पीसकर गोलियां बना लें, किसी भी दवा से बंद न होने वाले उल्टी-दस्त इससे बंद हो जाते हैं.

❖ **भस्मक रोग-** मीठे आम का रस 250 मिली, 40 ग्राम घी, 50 ग्राम खांड तीनों को एक साथ मिलाकर सेवन करने से भस्मक रोग (अत्यधिक भूख लगना) में लाभ होता है.

❖ **उदरकृमि-** 250 से 500 मिग्रा कच्चे आम की गुठली के चूर्ण को दही या जल के साथ सुबह-शाम सेवन करने से उदरकृमियों का शमन होता है.

वृक्कवस्ति रोग :

❖ **मधुमेह-**आम के छाया में सुखाए हुए 10 पत्तों को आधा किलो जल में उबालें, चौथाई जल शेष रहने पर प्रातः सायं पिलाने से मधुमेह में लाभ होता है.

❖ 2-5 ग्राम छाया शुष्क पत्र चूर्ण को गुनगुने जल के साथ सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है.

❖ आम की 25 ग्राम ताजी छाल को यवकुट कर रात्रि में 250 मिली जल में भिगो कर प्रातः काल मसलकर, छानकर पीने से सुजाक तथा प्रमेह में लाभ होता है.

❖ आम पत्र के छाया शुष्क 6 ग्राम चूर्ण को प्रातः सायं ताजे जल के साथ सेवन करने से लाभ होता है.

❖ आम की ताजी अन्तःछाल के 20 मिली रस में 5 मिली चूने का निथरा हुआ जल मिलाकर पिलाने से प्रमेह एवं सूजाक में लाभ होता है.

त्वचा रोग :

❖ आम के कच्चे फलों को तोड़कर (जिनमें जाली न पड़ी हो), कुचलकर कपड़े से छानकर रस निकाल लें. रस का चौथाई भाग विकृत स्प्रिट या शुद्ध एल्कोहल मिलाकर शीशी में भरकर रखें. इसे दो दिन बाद प्रयोग करें. इसको लगाने से पुरानी दाद, खुजली आदि

व्याधियां शीघ्र मिटती हैं. इसे रूई की फुहेरी से लगाने से फूटी हुई गले की गांठें, भगंदर, पुराने फोड़े आदि जड़ से दूर हो जाते हैं.

❖ आम को तोड़ते समय, आम फल की पीठ में जो गोंदयुक्त रस निकलता है, उसे दाद पर लगा देने से छाला पड़ जाता है और फूटकर पानी निकल जाता है. दो-तीन बार लगाने से दाद से छुटकारा मिल जाता है.

❖ आम वृक्ष के गोंद को थोड़ा गर्म कर लगाने से फोड़ा पककर, फूटकर बह जाता है और घाव आसानी से भर जाता है.

❖ **घमौरियां-** गर्मी के दिनों में शरीर पर पसीने के कारण छोटी-छोटी फुन्सियां हो जाती हैं, इन पर कच्चे आम के भुने हुए गूदे को लगाने से लाभ होता है.

❖ **अग्निदग्ध-** गुठली की गिरी को थोड़े पानी के साथ पीसकर आग से जले हुए स्थान पर लगाने से दाह तथा वेदना का शमन होता है.

सर्वशरीर रोग :

❖ **शरीर पुष्टि के लिए-** नित्य प्रातः काल मीठे आम चूसकर, उपर से सोंठ व छुहारे डालकर पकाए हुए दूध को पीने से पुरुषत्व में वृद्धि और शरीर पुष्ट होता है.

विष चिकित्सा :

❖ आम की गुठली को जल के साथ पीसकर दंश स्थान पर लगाने से भंवरी, मधुमक्खी, बर्र, ततैया, बिच्छू आदि विषैले कीड़े मकौड़े के दंश से उत्पन्न दाह तथा वेदना का शमन होता है.

आम के अन्य प्रयोग :

❖ पके हुए मीठे देशी आमों का ताजा रस 250-350 मिली, 50 मिली गाय का ताजा दूहा हुआ गर्म दूध अदरक का रस एक चम्मच तीनों को कांसे की थाली में अच्छी तरह फेंट लें, लस्सी जैसा हो जाने पर धीरे-धीरे पी लें, 2-3 सप्ताह सेवन करने से मस्तिष्क की दुर्बलता, सिर की पीड़ा, सिर का भारी होना, आखों के आगे अंधेरा हो जाना आदि दूर होता है. यह कल्प यकृत् के लिए भी विशेष लाभदायक है.

❖ कच्चे आम की गुठली जिसमें जाली न पड़ी हो का चूर्ण 60 ग्राम, जीरा, काली मिर्च व सोंठ का चूर्ण, 20 ग्राम आम्रवृक्ष के गोंद का चूर्ण 5 ग्राम तथा अफीम का चूर्ण 1 ग्राम इनको खरल कर, वस्त्र से छानकर बोतल में बंद कर सुरक्षित करें. 3-6 ग्राम तक अवस्थानुसार दिन में 3-4 बार सेवन करने से संग्रहणी, आम अतिसार, रक्तस्राव शूलादि का शमन होता है.

❖ आम की मंजरी का क्वाथ (10-20 मिली) या चूर्ण (1-2 ग्राम), अतिसार, पुरानी पेचिश और सूजाक में उपयोगी है. इसके चूर्ण का धुआं मच्छरों को भगाता है.

❖ 10-20 मिली आम के फूलों का काढ़ा या 1-2 ग्राम चूर्ण सेवन करने से अथवा इनके चूर्ण में चौथाई भाग मिश्री मिला सेवन करने से अतिसार, प्रमेह, अरुचि, रक्तदोष, दाह एवं पित्त के उपद्रव नष्ट होते हैं.

❖ 10-20 मिली आम के फूलों के रस में 10 ग्राम खांड मिलाकर सेवन करने से प्रदर में लाभ होता है.

❖ आम का ताजा कोमल पत्र तोड़ने से जो एक प्रकार का द्रव पदार्थ निकलता है, उसे नेत्र-पिडका पर लगाने से, या पत्रों के बीच की लकड़ी (मध्य शिरा) की भस्म लगाने से लाभ होता है. पत्रों के उक्त द्रव पदार्थ को बिवाई में भर देने से तुरंत लाभ होता है.

❖ आम के 11 पत्र, जो वृक्ष पर ही पककर पीले रंग के हो गए हों, उसे लेकर 11 लीटर पानी में उबालें, जब पानी आधा शेष रह जाए तो उतार कर शक्कर और दूध मिलाकर चाय की तरह पिएं. यह चाय शरीर के समस्त अवयवों को शक्ति-प्रदान करती है.

❖ आम की गुठली की गिरी का अनाज और चारे की जगह अच्छा प्रयोग हो सकता है. इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में पाए जाते हैं.

❖ आम में मक्खन से कई गुना अधिक पोषक तत्व विद्यमान हैं, उचित तरीके से प्रयोग करने पर आम स्नायु तंत्र को मजबूत बनाता है. शुद्ध रक्त बहतायत से उत्पन्न होता है और शक्ति वृद्धि होती है.

❖ जिन व्यक्तियों को मंदाग्नि, संग्रहणी, पुराना अतिसार, अजीर्ण, प्रमेह, धातुक्षीणता, क्षय, उदर रोग, प्लीहा, वायुगोला, नसों में सूजन हो गया हो, जिनके शरीर में कफ और पित्त का निरंतर प्रकोप रहता हो, दिल दिमाग कमजोर हो गया हो, ऐसे रोगियों को आम का कल्प लाभदायक है.

❖ आग से झुलसना, खरोंच लगना आदि के लिए आम के पत्तों की भस्म एक उत्तम औषधि है.

❖ रक्तप्रदर एवं अर्श- 10-20 मिली छाल स्वरस को दिन में दो बार पीने से बवासीर, अत्यधिक मासिक-स्राव या रक्तातिसार के कारण होने वाले रक्तस्राव में लाभ होता है. ■

प्रयोज्यांग : फल, पत्र, बीज गिरी, छाल, पुष्प तथा मंजरी.

मात्रा : चिकित्सक के परामर्शानुसार.

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

जन्नत श्री गुरु के चरणों में ही अनुभव होता है

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण

सर्वोत्तम शिष्य बनने के लिए, शिष्य को क्या करना चाहिए?

सर्वोत्तम शिष्य बनने के लिए गुरु की सम्पूर्ण शक्ति लेकर स्वयं को गुरु होना पड़ेगा. सद्गुरु शिष्य नहीं बनाते अपितु सद्गुरु बनाने का प्रयास करते हैं. वे शिष्य की आत्मा को अपने स्तर पर पहुंचाने के लिए विकसित करते हैं अर्थात् सद्गुरु शिष्य को अपने स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं. यह स्थिति तो बहुत ऊ पर होती है और सर्वोत्तम शिष्य आदमी स्वयं तब होता है, जब वह गुरु की पदवी धारण करता है. परन्तु इससे पहले हमें धैर्य न खाते हुए स्वयं समय निर्धारित न करते हुए, मार्ग स्वयं न बनाते हुए, जैसे कि वस्तुतः संसार में होता है, पूर्णरूप से गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए और धीरे-धीरे उन्हीं के प्रति अभिमुख हो जाना चाहिए. सर्वप्रथम गुरु के आलोक में आना चाहिए, फिर समीप आना चाहिए, फिर उनके साथ सान्निध्य जोड़ना चाहिए और फिर धीरे-धीरे उनके समस्त कार्य करने चाहिए. इसी प्रकार की शक्ति के साथ इंसान आगे बढ़ सकता है.

गुरु-प्रेम

एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर श्री गुरु को अर्पित किया, क्या आज के युग में किसी शिष्य के लिए ऐसा करना सम्भव है?

'श्री साईं सच्चरित्र' में बाबा द्वारा वर्णित है 'मेरे गुरु ने एक बार बांध कर मुझे कुएं में डाल दिया. कई घंटों तक मैं लटका रहा. जब उठा तो गुरु ने पूछा-कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है. इस संसार में जितने सद्गुरु हुए, जितने संत बने, उन्होंने भी अवश्य अपने गुरु के लिए कुछ ऐसा ही किया होगा. एकलव्य एक पौराणिक चरित्र है, जिसने अंगूठा काटकर अपने गुरु को अर्पित किया, पर यह सुनिश्चित है कि जो लोग परमहंस बनते हैं, जीवन मुक्त बनते हैं, उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, उनका गुरु-प्रेम जरूर उतना ही है. इसकी पराकाष्ठा कई जगह मिलती है.

दास-भाव

जन्नत श्री गुरु के चरणों में है तो इसका कब और कैसे अनुभव होता है?

श्री गुरु के जीवनकाल में उनके चरणों की पूजा करना, पाद-सेवन करना नवधा भक्ति में से एक भक्ति भाव है. श्री गुरु के समाधि लेने के पश्चात् उनके चरणों का ध्यान किया जा सकता है. केवल चरणों का ही नहीं, बाबा के अनुसार 'चरण से सर तक, सर से चरण तक का ध्यान करना चाहिए. गुरु-चरणों को मन में रखने का अभिप्राय हमारे दास-भाव से है. यहां हम समभाव, बन्धु-भाव नहीं रखते, वरन दास-भाव रखते हैं. चरण-पूजा का मतलब है-दास-भाव, अर्थात गुरु के वचनों का अनुसरण तथा बिना पूछे उनके आदेश का पालन. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

भारत के निशानेबाजों से स्वर्ण की उम्मीद

टार्गेट रियो

अभिनव बिंद्रा

अपूर्वी चंदेला

गगन नारंग

चैन सिंह

हिना सिद्धू

बचपन से ही शूटिंग का शौक रखने वाली हिना ने शुरुआती दिनों में ही निशाना लगाना शुरू कर दिया था. यह बात भी सत्य है कि वह अंजलि भागवत के बाद भारत की पहली महिला शूटर हैं जिन्होंने विश्व कप शूटिंग में स्वर्ण पदक के साथ-साथ नंबर वन शूटर होने का गौरव प्राप्त किया.

सैय्यद मोहम्मद अब्बास

विश्व खेल पटल पर भारतीय खिलाड़ी लगातार चमक रहे हैं. उनके प्रदर्शन से अब विश्व खेल जगत में हलचल देखी जा सकती है. दरअसल रियो के खेल में इस बार भारतीय चुनौती तगड़ी दिख रही है. प्रत्येक खेल में भारतीय खिलाड़ियों का पदक पर दावा मजबूत दिख रहा है. बैडमिंटन से लेकर कुश्ती तक में इस बार पदक की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. बात अगर निशानेबाजी की जाए तो इतना तो साफ है विदेशी खिलाड़ियों की तुलना में भारतीय खिलाड़ी भी बेहतर दिख रहे हैं. रियो में उनका अचूक निशाना गोल्ड पर लग सकता है. निशानेबाजी में कई चमकदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने सटीक निशाने से विदेशी खिलाड़ियों के माथे पर बल ला दिया है. लंदन ओलम्पिक में भारतीय निशानेबाजों ने अपनी अलग पहचान बनाई थी लेकिन इस बार कुल 12 खिलाड़ियों ने रियो का टिकट हासिल किया है. लंदन में 11 निशानेबाजों ने भाग लिया था. उसकी तुलना में इस बार मजबूत निशानेबाजों की अच्छी कतार शामिल है. उनमें सबसे अनुभवी अभिनव बिंद्रा का निशाना सबसे बेहतर भले ही माना जाता हो लेकिन कई और खिलाड़ी हैं जिनका निशाना सही बैठ गया तो रियो ओलम्पिक में भारत की तस्वीर निशानेबाजी में बदल सकती है. गगन नारंग में माहा है कि वह गगन को छू सकते हैं, जबकि जीतू राय के बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि वह अगर लय में हुए तो स्वर्ण से कम में बात नहीं होगी. इतना ही नहीं, कुछ और निशानेबाज हैं जो इस बार रियो में भारत का झंडा बुलंद कर सकते हैं.

निशानेबाजी में भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने का सुनहरा अवसर है. ओलम्पिक में इस बार करीब 390 निशानेबाज अपना भाग्य आजमाएंगे. इस तरह से करीब 15 स्वर्ण के साथ 45 पदक दांव पर लगे हुए हैं. अभिनव बिन्द्रा इस बार पदक जीतकर अपने करियर का समापन करना चाहते हैं. रियो ओलम्पिक के लिए अभिनव बिंद्रा को भारतीय दल का ध्वजवाहक भी बनाया गया है. ओलम्पिक के इतिहास पर गौर किया जाए तो भारतीय निशानेबाज खासकर अभिनव बिंद्रा का कद सबसे ऊपर आता है क्योंकि उन्होंने 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर भारत का परचम बुलंद किया था. इस बार भी रियो के खेल में अभिनव से सोने की उम्मीद जगी है. हालांकि यह बात भी सत्य है कि वह लंदन ओलम्पिक में भारत की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे. रियो ओलम्पिक में पदक जीतने का अभिनव बिंद्रा पर भारी दबाव होगा. 33 साल के अभिनव बिंद्रा ओलम्पिक खेल महाकुंभ में पांचवीं बार दम दिखाने को बेताब हैं. उन्होंने ओलम्पिक में भारत की दावेदारी को लेकर ठोस योजना बनाई है. अभिनव बिंद्रा के करियर पर नजर दौड़ायी जाए तो इतना साफ है कि उन्होंने हमेशा भारत का मान बढ़ाया है. ओलम्पिक में गोल्ड लाने से पूर्व उन्होंने कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार निशाना लगाते हुए अपनी अलग पहचान बना ली थी. 2000 में अभिनव सिडनी ओलम्पिक के सबसे युवा निशानेबाज थे. उनके लिए यह पहला अनुभव था. 2001 के म्यूनिख कप में उन्होंने कास्य पदक जीता. इसी साल अभिनव ने मैन्चेस्टर में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर सबको चौंका दिया था. 2004 में एथेंस ओलम्पिक में शानदार शुरुआत करते हुए रिकॉर्ड बनाया लेकिन वह पदक जीतने से चूक गए थे. 2014 में अभिनव ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण जीतकर अपनी धमक कायम रखी. अब वह अपने करियर के अंतिम दौर में हैं. ऐसे में पूरा भारत उनसे रियो ओलम्पिक में पदक की उम्मीद लगा रहा है. दूसरी ओर अभिनव बिंद्रा के बाद अगर कोई निशानेबाज सुर्खियों में आया है तो वह हैं गगन नारंग. गगन नारंग ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब भारत की झोली में डाला है. 2003 में गगन नारंग ने एफ्रो एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उम्दा प्रदर्शन करते हुए अलग-अलग दो वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया. इतना ही नहीं 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल चार स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय खेल जगत में तहलका मचा दिया था. इस प्रदर्शन के बाद उनका स्तर भारतीय खेल में बढ़ने लगा. गगन का जलवा विश्व शूटिंग में भी देखने को मिला जब उन्हें तीन बार चैम्पियन होने का ताज भी मिला. 2012 लंदन ओलम्पिक में उन्होंने देश की उम्मीदों का बोझ उठाते हुए कांस्य पदक हासिल किया. अब वह रियो ओलम्पिक में पदक के लिए पूरा जोर लगाएंगे. छह साल की उम्र से निशानाबाजी का गुर सीखने वाले गगन में इस बार पदक जीतने की कूवत इसलिये लग रही है, क्योंकि वह पहले से बेहतर तैयारी के साथ ओलम्पिक में जा रहे हैं.

अभिनव और गगन स्टार खिलाड़ियों में शुमार हैं, लेकिन लखनऊ के जीतू राय भी किसी से कम नहीं हैं. उनके निशाने की चर्चा चारों ओर होती है. उनका निशाना अक्सर स्वर्ण पर लगता है. हाल के दिनों में उनका निशाना स्वर्ण की बारिश कर रहा है. दरअसल 2014 में जीतू ने इतना कमाल का प्रदर्शन किया कि हर कोई उनकी निशानेबाजी का कायल हो गया. उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में तीन सोना जीतकर अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया. यह पहला मौका था, जब किसी भारतीय ने इतने बड़े टूर्नामेंट तीन स्वर्ण झटके थे. नेपाली मूल के भारतीय निशानेबाज जीतू राय ओलम्पिक में भारत की तरफ से पदक की दावेदारी में सबसे आगे आते हैं. जीतू राय का बचपन पूर्वी नेपाल में गुजरा है. पिता की मौत के बाद जीतू भारत आ गए थे. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय सेना में ट्रेनिंग लेकर जीतू ने निशानेबाजी में अपना हुनर तराशना शुरू कर दिया था. शुरुआती दौर में उन्होंने अपने खेल को बड़े स्तर पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की. गोरखा रेजिमेंट में नायब सूबेदार भी बने. इस दौरान शूटिंग में प्रभावित करने के बाद सेना ने उन्हें मध्य स्थित आर्मी मार्क्समैन यूनिट में भेज दिया. यहां से उन्होंने शूटिंग को नया आयाम देना शुरू कर दिया. राष्ट्रीय स्तर पर जीतू का नाम हो रहा था लेकिन उन्हें असली पहचान आईएसएसएफ वर्ल्डकप म्युनिख में मिली. उन्होंने वहां गजब का प्रदर्शन करते रिकॉर्ड भी बनाया. इतना ही नहीं, जीतू को अपने दमदार प्रदर्शन के बल पर आईएसएसएफ वर्ल्डकप में पिस्टल रैंकिंग में नम्बर वन का तमगा हासिल हुआ. पूरे भारत में उनके प्रदर्शन की सराहना होने लगी, लगा भारत को निशानेबाजी में एक और नया सितारा मिल गया है. उनकी कामयाबी देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपये का इनाम भी दिया. हाल के दिनों में भले ही जीतू का निशाना उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा हो लेकिन ओलम्पिक जैसी प्रतियोगिता के लिए जीतू ने खास रणनीति बनाते हुए अपनी तकनीक में भी खासा सुधार किया है. अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित जीतू राय को अब असली इम्तिहान देना होगा. भले ही उन पर पदक जीतने का दबाव हो लेकिन ओलम्पिक जैसी प्रतियोगिता में पदक जीतने के लिए वे एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, ऐसा लगता है.

जीतू राय

भारत की महिला निशानेबाज हिना सिद्धू भी इस बार करिश्मा कर सकती हैं. पूर्व वर्ल्ड नम्बर वन हिना सिद्धू ने हाल के दिनों में जानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने एशियाई ओलम्पिक क्वालीफायर में शानदार निशानेबाजी का नमूना पेश करते हुए स्वर्ण के साथ ओलम्पिक का टिकट हासिल किया. वह भारत की प्रतिभावान निशानेबाजों में से एक मानी जाती हैं. हिना सिद्धू का पूरा परिवार निशानेबाजी से जुड़ा है. उनके पिता और भाई भी शूटर हैं. हिना के पति भी शूटिंग में हाथ आजमा रहे हैं. बचपन से ही शूटिंग का शौक रखने वाली हिना ने शुरुआती दिनों में ही निशाना लगाना शुरू कर दिया था. यह बात भी सत्य है कि वह अंजलि भागवत के बाद भारत की पहली महिला शूटर हैं जिन्होंने विश्व कप शूटिंग में स्वर्ण पदक के साथ-साथ नंबर वन शूटर होने का गौरव प्राप्त किया. विरासत में मिले इस खेल में हिना सिद्धू को अपने करियर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में पदक जीतने की उम्मीद बंधी है. इनके अलावा कुछ और भारतीय निशानेबाज हैं जो ओलम्पिक में चमत्कार करने का माद्दा रखते हैं. उनमें उत्तर प्रदेश के मैराज अहमद खान भी इस बार रियो में पदक जीतने के दावेदार हैं. उनका प्रदर्शन भी इस बात का गवाह है. स्कीट स्पर्धा में मैराज अहमद खान ओलम्पिक का टिकट हासिल करने के बाद पिछले एक साल से दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. कॉमनवेल्थ में स्वर्ण जीतने वाले मैराज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वह शूटिंग से पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे. वह अपना पहला प्यार क्रिकेट को मानते थे. वीरेंद्र सहवाग के साथ वे क्रिकेट भी खेल चुके हैं. क्रिकेट की दुनिया में सौरभ गांगुली को फैन बताने वाले मैराज ओलम्पिक में सबसे मुश्किल लोनाटो शॉटगन चैम्पियनशिप्स में हाथ आजमा रहे हैं. यूपी के बुलंदशहर के निवासी मैराज अरसे से नोएडा में रह रहे हैं और दिल्ली में 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की स्कीट स्पर्धा में भी कमाल दिखा चुके हैं. ऐसे में वह रियो के खेल में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं. वहीं चैन सिंह जैसे निशानेबाज भी अपनी उपयोगिता साबित करने को बेताब हैं. चैन सिंह ने विश्व कप के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में दमदार प्रदर्शन कर रियो का टिकट हासिल किया. दूसरी ओर मानवजीत सिंह संधू बेहद अनुभवी निशानेबाज हैं, लेकिन उनके फॉर्म को लेकर अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी. ■

मैराज अहमद खान

दमदार है निशानेबाजों का दस्ता

अयोनिका पॉल

गुरप्रीत सिंह

प्रकाश नान्जप्पा

रियो ओलम्पिक में भाग लेने वाले निशानेबाजों में अपूर्वी चंदेला, गुरप्रीत सिंह, प्रकाश नान्जप्पा, चैन सिंह, मैराज अहमद खान, हिना सिंधू, कीनन चेनई, अयोनिका पॉल, मानवजीत सिंह संधू, अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग के नाम शामिल हैं. देखा जाए तो इन सभी निशानेबाजों में अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा. अपूर्वी चंदेला की निशानेबाजी अभी नई है. म्युनिख में आयोजित शूटिंग चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतकर उन्होंने कुछ उम्मीद बढ़ाई है. निशानेबाजी को लेकर सरकार भी मदद में आगे रही है. ओलम्पिक को ध्यान में रखकर उन्हें सारी सुविधा दी गई ताकि वे ओलम्पिक में बेहतर प्रदर्शन कर सकें. कुल मिलाकर इस बार निशानेबाजी में भारत की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं. अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो भारत इस बार उम्मीद से ज्यादा पदक जीत सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स 2016

आगामी 29 जुलाई 2016 को फिल्म नगरी मुम्बई में देश व विदेश से 50 चुने हुए भारतीयों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने कार्यों से समाज व आम जनमानस पर एक अलग छाप छोड़ी है एवं आने वाली व वर्तमान पीढ़ी पर एक सकारात्मक प्रभाव भी डाला है और निश्चित रूप से सभी चयनित प्रतिभागी इस प्रतिष्ठित सूची के लायक हैं. ऐसे लोग जो व्यक्तिगत व पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से ऊपर उठ कर अपना मूल्यवान समय समाज व देशहित में अर्पित करते हैं. ऐसे भी लोग हैं जिनका लक्ष्य ही समाज सेवा है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फर्श से अर्श तक की कामयाबी की कहानी सुन कर आंखें भर आती हैं. कुछ-कुछ जादुई एहसास भी होता है. और यह महसूस होता है कि दिल में सच्चाई और ईमानदारी हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और लक्ष्य को प्राप्त करने की रही सही कसर पूरा कर देता है उनके सीने में धधक रहा लक्ष्य और मंज़िल को पाने का जुनून. कोई भी कार्य, कहानी व उद्यम 100 प्रतिशत सफल नहीं होता. इस अभिनव प्रयास को सभी लोगों की प्रशंसा मिलेगी ऐसा विश्वास इस अवार्ड समारोह के आयोजकों को है. मुम्बई शहर के इस्कॉन ऑडिटोरियम जुहू में आयोजित हो रहे इस समारोह में देश की शीर्ष राजीतिक, कॉर्पोरेट व मनोरंजन जगत की हस्तियां अपनी उपस्थिती दर्ज करायेंगी.

आवार्ड समारोह में देश के कई मीडिया दिग्गज व मीडिया समूह अपना सक्रिय सहयोग दे रहे हैं. कार्यक्रम के निर्देशक व एम. फार. यू. एन्टरटेनमेन्ट के अध्यक्ष दुष्यन्त सिंह के अनुसार उपरोक्त सूची में समाज के तकरीबन सभी वर्गों, जैसे कला, साहित्य, संगीत, व्यापार, शिक्षा, धर्म इत्यादि क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियतों को सम्मानित किया जा रहा है. टॉप 50 इन्डियन आईकन अवार्ड 2016 के नाम से हो रहे इस अवार्ड समारोह में समूचे देश व सिंगापुर, थाइलैंड, एवं दुबई से चुने गये पचास भारतीयों को इस सम्मान से विभूषित किया जायेगा पारम्परिक आयोजनों की श्रृंखला में यह आयोजन निश्चित रूप से अपनी एक अलग पहचान कायम करेगा ऐसा विश्वास उन्होने व्यक्त किया है. सभी चयनित प्रतिभागियों का चयन एक चयन समिति द्वारा जिसके सदस्य-पूज्य महामण्डलेश्वर मार्तण्ड पुरी जी, पूर्व न्यायाधीश श्री चन्द्रभाल श्रीवास्तव, डॉ. कृष्णबीर चैधरी, डॉ. अमी आधार निडर, समाज सेवी श्री नरेश पारस, श्री पी. के. बजाज, श्री कमल शेखरी है व चयन समूह की अध्यक्षता पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री संतोष भारतीय कर रहे हैं व समारोह का मीडिया समन्वयन श्री अनुराग बत्रा व मीडिया प्लानर द्वारा किया जा रहा है.

कदाचित यह ऐसा अनोखा कार्यक्रम है जहां पहली बार किसी भी जाति, धर्म व दल विशेष से ऊपर उठ कर देश व विदेश के प्रमुख विशिष्ठ व्यक्तित्व एक छत के नीचे इस महाआयोजन का हिस्सा बनेंगे. कार्यक्रम समन्वयक अनुराग बत्रा के अनुसार लखनऊ शहर से भी कुछ विभूतियों का चयन इस सम्मान समारोह हेतु किया गया है. कार्यक्रम की कॉन्सेप्ट एडिटर श्रीमती रितू सिंह के अनुसार चयन समिति ने जिस पारदर्शित व मेहनत से सभी प्रतिभागियों का चुनाव किया है वह अत्यंत ही प्रंशसनीय है. पहली बार देश में आयोजित हो रहे किसी कार्यक्रम में ऐसे सफल लोगों को भी सम्मानित किया जायेगा, जिनसे आम लोग व युवा तकरीबन अपरिचित हैं. देश-विदेश में भारतीय संस्कृति व ज्ञान और अनुशासन का परचम लहरा रहे यह लोग निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं एवं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से समाज को एक नई दिशा मिलेगी.■

विशेष सम्मान

श्री पहलाज निहलानी (अध्यक्ष फिल्म सेंसर बोर्ड भारत सरकार)
श्री गजेंद्र चौहान (चेयरमैन फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे भारत सरकार)
डॉ. कैलाश प्रज्ञ सुथार (अंक ज्योतिष जयपुर)
श्री रमेश चोपड़े (समाजसेवी नागपुर)
सुश्री शोभा टिपनिस (आध्यात्मिक समाजसेवी मुम्बई)

डॉ. अश्वनी महाजन (सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली)
डॉ. जसपिन्दर नरूला (पार्श्व गायिका मुम्बई)
श्री श्रीवर्धन त्रिवेदी (वरिष्ठ/ पत्रकार/प्रस्तोता सनसनी ए.बी.पी. न्यूज दिल्ली)
सुश्री नीतू चन्द्रा (अभिनेत्री/खिलाड़ी मुम्बई)
सुश्री विशाखा त्रिपाठी (अध्यक्ष जगद्गुरू कृपालू परिषद् वृन्दावन, मथुरा)
डॉ एच डी गुप्ता (सिंगापुर)
परम् पूज्य संत श्री राधे राधे बाबू जी (फरीदाबाद)
सुश्री अर्चना कोचर (अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर मुम्बई)
श्री गुरूस्वरूप श्रीवास्तव (समाजसेवी/उद्योगपती कुरूक्षेत्र, हरियाणा)
श्री आलोक सिंह (समाजसेवी/पत्रकार/ क्रेडाई उपाध्यक्ष आगरा)
डॉ सुकेश यादव (कुलाधिपति जे.एस. यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद)
सुश्री सुगन्धा मिश्रा (अभिनेत्री/ गायिका मुम्बई)
श्री विनीत दुबे (पत्रकार न्यूज नेशन चैनल आगरा)
सुश्री निशी सिंह (कथक नृत्यांगना दुबई)
श्री जयेश मडियार (समाजसेवी/ उद्योगपती राजकोट)
सुश्री जोया अफरोज (अभिनेत्री मुम्बई)
श्री प्रेम शुक्ल (वरिष्ठ त्रकार/ राजनीतिज्ञ मुम्बई)
श्री राजा हसन (पार्श्व गायक मुम्बई)
श्री रामशंकर (पार्श्व गायक मुम्बई)
डॉ कमलजीत सिंह (वरिष्ठ चिकित्सक बैकॉक थाईलैण्ड)
श्री दीप सैनी (समाजसेवी/उद्योगपती कुरूक्षेत्र, हरियाणा)
श्री अभिलाष (फिल्म लेखक/गीतकार मुम्बई)
श्री आनंद शर्मा (संगीतकार मुम्बई)
श्री अतुल मोहन (फिल्म ट्रेड पत्रकार मुम्बई)
सुश्री रौशनी वालिया (बाल अभिनेत्री मुम्बई)
श्री योगेश लखानी (वरिष्ठ विज्ञापन प्रबंधक मुम्बई)
डॉ कुमार गणेश (अंक ज्योतिष जयपुर)
श्री अमित भाटी (समाजसेवी/ शिक्षा कार्यकर्ता गौतम बुद्ध नगर)
श्री पंकज दुबे (समाजसेवी/ऑटोमोबाईल विशेषज्ञ दिल्ली)
श्री राजा सागू (अभिनेता/ गायक/ संगीतकार मुम्बई)
श्री विदुर (अभिनय शिक्षक मुम्बई)
श्री जैद शेख (अभिनेता मुम्बई)
सुश्री अर्जुमन मुघल (अभिनेत्री मुम्बई)
श्री अभिषेक गुप्ता (समाजसेवी/ उद्योगपति आगरा)
मो. सलीम शेख (फिल्म लेखक मुम्बई)
श्री मनीश अवस्थी (राजनैतिक संपादक इंडिया न्यूज चैनल मुम्वई)
श्री अंकुर श्रीवास्तव (समाजसेवी/ उद्योगपति लखनऊ)
श्री प्रखर गर्ग (समाजसेवी/ उद्योगपति आगरा)
श्री रिकी गुप्ता (नृत्य निर्देशक मुम्बई)
डॉ सुरेंद्र सिंह भगौर (वरिष्ठ चिकित्सक आगरा)
सुश्री पूजा माथुर (टैरो कार्ड विशेषज्ञ मुम्बई)
सुश्री सिमर भाटिया (फिल्म निर्मात्री/ साइकोलाजिस्ट मुम्वई)
डॉ सान्तनु सेन (वरिष्ठ चिकित्सक मुम्बई)
सुश्री अनादि सरस्वती (धर्मगुरू मुम्बई)
श्री राजेन्द्र जैन (समाजसेवी/ उद्योगपती मुम्बई)
डॉ खुश्बू कादरी (वरिष्ठ चिकित्सक मुम्बई)
श्री राहुल श्रीवास्तव (समाजसेवी/ उद्योगपति लखनऊ)
डॉ डी.एम. तिवारी (वरिष्ठ चिकित्सक लखनऊ)
श्री आशीष डे (समाजसेवी/ उद्योगपति लखनऊ)

मैं हॉलीवुड में खुद अपने कपड़े धोती थी : दीपिका

दीपिका पादुकोण के साथ अब बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड के अनुभव भी जुड़ गए हैं. उन्होंने अपनी हॉलीवुड फिल्म के दौरान विदेश में बिताए समय का काफी आनंद लिया. दीपिका जल्द ही हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. जब उनसे उनकी डेब्यू फिल्म के बारे में पूछा गया कि इसे आप किस तरह से देखती हैं तो उन्होंने कहा कि यह वैसे ही है, जैसे कि मेरी जिंदगी में दूसरी चीजें हैं. बेशक, ये वो मुकाम नहीं है, जिसे मैं पाना चाहती हूं. ये बहुत ही सामान्य है. मुझे एक ऑफर आया. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी. अपना रोल अच्छा व अहम लगा. ऐसा नहीं था कि ओह! ये हॉलीवुड फिल्म है, इसलिए मैं ये जरूर करूं. मैंने हॉलीवुड फिल्म सिर्फ अपने दिलचस्प अनुभव के लिए चुनी है.

मुझे पहले भी हॉलीवुड फिल्म के ऑफर मिले हैं, लेकिन तब मैं इनके लिए तैयार नहीं थी. किसी मौके को भुनाने से पहले आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं. कोई भी रोल बड़ा या छोटा नहीं होता. कभी-कभी छोटा सा रोल भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है. मैं लकी हूं कि मुझे हॉलीवुड फिल्म में मौका मिला. ये रोल के साइज की बात नहीं है, बल्कि अवसर की बात है.

आगे दीपिका बताती हैं कि मैंने एक काम को काफी एंजॉय किया. मैं हॉलीवुड में अपने कपड़े खुद ही धोती थी. मैंने ये काम सीरियस तरीके से किया है. वहां इस तरह का टाइमिंग शेड्यूल है कि आपको वीकेंड मनाने का मौका मिल जाता है. इस दौरान मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग, खाना बनाना, कपड़े धोना जैसे तमाम काम खुद किए.

दीपिका ने आगे हॉलीवुड और बॉलीवुड की समानताओं के बारे में बताया कि दोनों इंडस्ट्री में काफी समानताएं हैं. मैंने दोनों इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पाया. इससे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का कद पता चलता है. मुझे लगता है कि हम पिछले कई सालों से लगातार विकसित हो रहे हैं. हमारे यहां इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर सिस्टम था. फिर पिछले कुछ सालों में कई स्टूडियो आए. अब हम कई तरह की महिला केंद्रित फिल्मों को टच कर रहे हैं.■

कभी-कभी छोटा सा रोल भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है. मैं लकी हूं कि मुझे हॉलीवुड फिल्म में मौका मिला. ये रोल के साइज की बात नहीं है, बल्कि अवसर की बात है.